# नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । मुंबई । बुधवार, 8 अक्टूबर 2025


शांति बल से नहीं, समझ और संवाद से स्थापित होती है।

– ड्वाइट डी. आइजनहावर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति

## ख़त्म हो संघर्ष

**इस्राइल और** हमास को लड़ते हुए दो साल हो गए। इस संघर्ष ने 65 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले ली और लाखों को विस्थापित कर दिया। इस बार अमेरिका ने शांति का प्लान तैयार किया है और दुनिया की नजरें इजिप्ट में हो रही वार्ता पर टिकी हैं।

**सबसे लंबा संघर्ष ।** इस्राइल-फलस्तीन विवाद एक सदी से भी अधिक समय से सुलग रहा है। 1948 में इस्राइल के नक्शे पर आने के बाद यह इलाका कई युद्ध और संघर्ष देख चुका है, लेकिन मौजूदा संकट जितना लंबा कोई भी नहीं चला। इन दो बरसों के दौरान कई ऐसे मोड़ आए, जब लगा कि यह संघर्ष भयानक युद्ध का रूप लेकर पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेगा।

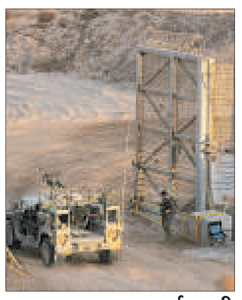

इस्राइल-हमास वार्ता जारी

**ट्रंप का प्लान ।** शांति की राह में सबसे बड़ी रुकावट दोनों पक्षों का एक-दूसरे पर अविश्वास है। न इस्राइल को हमास पर भरोसा है और न अरब वर्ल्ड इस्राइल पर यकीन कर पा रहा है। संघर्षविराम के पिछले सारे प्रयास इसी वजह से किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि इस बार बात अलग है। यह प्लान ट्रंप सरकार ने बनाया है, जो अभी तक इस्राइल को खुली छूट दिए हुए था। सबसे बड़ी बात, इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए जगह छोड़ी गई है।

**समझदारी दिखाएं ।** अमेरिकी दबाव में ही सही, इस्राइल का इस बिंदु पर सहमत होना बड़ा बदलाव है। वहीं, हमास का प्लान को स्वीकार करते हुए बातचीत की मेज पर आना भी सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक वह ऐसे प्रस्तावों को सिरे से खारिज करता रहा है। किसी भी बातचीत के सफल होने के लिए लचीलापन जरूरी है। अब उम्मीद ही की जा सकती है कि दोनों पक्ष समझदारी दिखाएंगे।

**जल्दबाजी में काम न बिगड़े ।** यहां अहम है कि ट्रंप तुरंत कोई परिणाम चाहते हैं। उनके हिसाब से इस हफ्ते के आखिर तक पहले दौर की योजना पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन शायद इतनी आशा पालना भी सही नहीं। इस्राइल और हमास के अलावा भी गाजा से जुड़े कई पक्ष हैं, और जब तक सभी संतुष्ट नहीं हो जाते, कोई नतीजा निकलना मुश्किल है।

**गाजा की मांग ।** दुनिया को याद रखना चाहिए कि गाजा जियो-पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, जहां किसी प्लान की जोर-आजमाइश की जाए। यह 20 लाख से अधिक लोगों का घर है, जो दशकों से वैश्विक ताकतों के बीच पिसते आ रहे हैं। कहीं और रहने वालों को जो मिलता है - सम्मान, सुरक्षा और पहचान, यही इनकी भी मांग है।

### नाभि में तीर

## चूहों का अस्पताल!

**शीर्षक पढ़कर** पहले पहल यही लगेगा कि यहां किसी ऐसे हॉस्पिटल का जिक्र होने जा रहा है, जहां कुत्ते-बिल्लियों की तरह ही चूहों का इलाज किया जाता हो! यूं आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आदमी के इलाज के अलावा किसी भी जीव के इलाज के लिए चिंतित हो सकते हैं लोग। ऐसे में कोई चूहों का अस्पताल भी खोल दे, तो आश्चर्य कैसा?

हरि मृदुल

मुंबई के एक सरकारी अस्पताल को लोगों ने इसलिए 'चूहों का अस्पताल' कहना शुरू कर दिया है कि यहां नर्सों और डॉक्टरों की कुल संख्या से ज्यादा चूहे दिखते हैं। सीन तो यह है कि मरीज या उसके परिजन जब किसी नर्स या डॉक्टर को पुकारते हैं, चूहा पहले मौजूद हो जाता है। खींसे निपोरता हुआ। दांत चमकाता हुआ। बोलो- कहां लगाना है इंजेक्शन? कई मरीज ऐसे होते हैं, जिनका इस महानगर में परिवार नहीं होता। कोई रिश्तेदार नहीं होता। पड़ोसी भर्ती करवा कर चले जाते हैं और फिर कभी सुध लेने नहीं आते। ऐसे लोगों की मिजाजपुर्सी ये चूहे ही करते हैं इस सरकारी अस्पताल में। वे मरीज को किसी भी हालत में अकेलापन महसूस नहीं होने देते। मरीज इन चूहों की उछल-कूद निहारता रहता है और उसका टाइमपास हो जाता है।

कई बार तो लगता है कि अब तक ये चूहे ऑपरेशन करना भी सीख गए होंगे। जब भी किसी मरीज का ऑपरेशन होता है, इनकी मौजूदगी रहती ही रहती है। सैकड़ों ऑपरेशन इनकी नजरों के सामने हुए हैं। डॉक्टरों से ज्यादा इन्हें पता है कि कब कौन सा इंजेक्शन लगना है और यह भी कि चीरा कहां लगाना है!!

अब बस यही कमी रह गई है कि जब डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए सर्जिकल नाइफ की जरूरत पड़े, तो कोई चूहा सामने आ जाए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहे कि डॉक्टर साहब, नाइफ की क्या जरूरत? मेरे पैने दांत हैं ना। बड़ी से बड़ी चीज कुतर कर रख दूं, यह पेट क्या चीज है!

### एकदा

संकलन : रेनू सैनी

## हिम्मत को मेडल

**15 साल** की किशोरी Betty Robinson एक दिन स्कूल से घर जाने के लिए दौड़ रही थी। उसके अध्यापक चार्ल्स प्राइज, जो खुद एक एथलीट रह चुके थे, उसकी गति देखकर चकित रह गए। उन्होंने बेट्टी को प्रशिक्षण देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह 100 मीटर रेस की अमेरिकी चैंपियन Helen Filkey से मुकाबला करने लगी। पहले वह दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जल्द ही उसने फिल्की को पछाड़ दिया। 1928 में उसने एम्सटर्डम ओलिंपिक के लिए क्वॉलिफाई किया और मात्र 16 वर्ष की आयु में 100 मीटर दौड़ की पहली ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी। लेकिन, 1931 बड़ी त्रासदी लेकर आया। एक विमान यात्रा के दौरान हादसा हो गया। विमान उस समय 600 मीटर की ऊंचाई पर था, बेट्टी चमत्कारिक रूप से बच गई। लेकिन, पैर और बांह की हड्डियां टूट गई थीं और डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगी। Betty Robinson ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। हिम्मत बटोरकर उसने धीरे-धीरे चलना, फिर दौड़ना शुरू किया। चार साल बाद, 1936 के बर्लिन ओलिंपिक में वह फिर दौड़ी और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। उसने साबित किया कि असली जीत हिम्मत और आत्मबल की होती है।

Subrata Dhar

वांगचुक के नेतृत्व में 5 साल से आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था

# लद्दाख में हालात क्यों बिगड़े

**कुछ बिल्कुल** स्वाभाविक लगती मांगों को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा पांच साल से चलाए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में अचानक हिंसा से लद्दाख का अशांत हो जाना कई सवाल खड़े करता है। लद्दाख में रहने वाले मेहमाननवाजी से लेकर राष्ट्रभक्ति तक, तमाम सकारात्मक चीजों के लिए जाने जाते हैं। वे पर्यावरण प्रेमी ही नहीं हैं, उसके संरक्षण के लिए समर्पित और निरंतर प्रयासरत भी रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण से लेकर देश-समाज के लिए अनुकूल शिक्षा व्यवस्था तक - तमाम क्षेत्रों में अकेले लद्दाख में जितना काम हुआ है, शायद पूरे देश में नहीं हुआ होगा।

राज कुमार सिंह

**इनोवेशन के नायक ।** हाल के दशकों में वहां ऐसे नवाचार (इनोवेशन) के नायक सोनम वांगचुक ही रहे हैं, जिन्हें हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) में गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया है। वांगचुक के विरुद्ध सरकार के हाथ क्या सूचनाएं लग गईं, देश नहीं जानता, पर देश यह जरूर जानता है कि उन्होंने पर्यावरण से लेकर शिक्षा और विज्ञान तक के क्षेत्र में अपने आविष्कारों से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। इसके लिए उन्हें अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिले हैं।

**मुखर समर्थन ।** अगस्त, 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370 हटाते हुए जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित इकाइयों - जम्मू-कश्मीर व लद्दाख - में विभाजित किया, तब वहां से समर्थन में उठने वाली सबसे मुखर आवाज सोनम वांगचुक की ही थी। बेशक उसके मूल में जम्मू-कश्मीर के वर्चस्व से लद्दाख की मुक्ति की खुशी भी रही होगी। लद्दाख का मानना रहा है कि जम्मू-कश्मीर की सत्ता-राजनीति में उसकी आवाज अनसुनी ही रही, जबकि भौगोलिक विशिष्टता के चलते उसकी आवश्यकताएं विशेष प्राथमिकता की मांग करती हैं।

**केंद्र का वादा ।** खुद BJP लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करने की मुखर समर्थक रही है। इस सच से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित इकाइयों में विभाजित करते समय जल्द ही दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। बाद में हुए चुनाव में BJP ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा भी किया।

**अधूरा है वादा**

- लद्दाख संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र
- देश-समाज के साथ रहे हैं सोनम
- अपना वादा नहीं निभा रही सरकार

पर हुआ क्या? जम्मू-कश्मीर को विधानसभा तो मिल गई, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए छह साल से इंतजार है। लद्दाख के साथ तो और भी बुरा हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा तो दूर, उसे विधानसभा तक नहीं दी गई।

**मांग असंवैधानिक नहीं ।** भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टता वाले आदिवासी क्षेत्रों को स्थानीय शासन का विशेष अधिकार देने का प्रावधान भारत के संविधान में है। संविधान के अनुच्छेद 244 (2) के तहत छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में विशेष प्रशासनिक ढांचे का प्रावधान करती है। इस ढांचे को सामाजिक रीति-रिवाज, उत्तराधिकार के अलावा भूमि और जंगल संरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में यह प्रावधान लागू भी है।

**शांतिपूर्ण आंदोलन की उपेक्षा ।** पांच साल से लेह-लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले शांतिपूर्ण आंदोलन की मुख्य मांग विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी सूची में शामिल करने की ही है। इन मांगों में ऐसा कुछ नहीं दिखता, जिसे पांच साल लंबे शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद स्वीकार कर पाना संभव न हो। इस आरोप पर क्षणिक विश्वास कर भी लें कि आंदोलन की आड़ में नेपाल जैसी Gen Z क्रांति की साजिश हुई तो क्या उसके हालात शांतिपूर्ण आंदोलन की पांच साल तक उपेक्षा से ही पैदा नहीं हुए? लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर के पैदल मार्च तथा पांच बार अनशन से ज्यादा और क्या सूबत चाहिए गांधीवादी शांतिपूर्ण आंदोलन का?

**जमीन खरीद-फरोख्त का खेल ।** लद्दाख के लोग खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर का अंग रहते अनुच्छेद-370 के तहत लद्दाख में भी बाहरी लोगों के जमीन खरीदने और सरकारी नौकरी करने पर प्रतिबंध था। वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे लद्दाखियों का आरोप है कि 2019 के बाद बाहरी लोगों द्वारा जमीन की खरीद-फरोख्त का खेल शुरू हो गया है और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ताक पर रख वैसी ही विकास परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरीखे पर्वतीय राज्यों के लिए विनाशकारी साबित हो रही हैं।

**राष्ट्रीय सुरक्षा की व्याख्या ।** राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही लोकतंत्र की मूल भावना है, स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर गांव उसकी प्राथमिक इकाई। बेशक राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, पर उसकी व्याख्या और विशेषाधिकार सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रखी जा सकती।

## है हिदायत चौक के हर वोटर-ए-शौक़ीन को

**आजादी के** पहले की बात है- 1920 की। लखनऊ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला चुनाव हो रहा था। उसे लेकर लखनवियों का उत्साह देखते ही बनता था। वरिष्ठ लखनऊविद योगेश प्रवीन, जो अब इस संसार में नहीं हैं, इस चुनाव के बारे में बहुत-सी बातें बहुत रस लेकर बताया करते थे। एक बार उन्होंने बताया कि उन दिनों लखनऊ के चौक वार्ड में, जहां तवायफों की बस्ती थी, दिलरुबा जान नाम की एक नामी तवायफ हुआ करती थी।

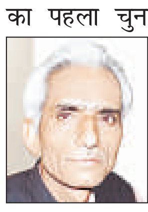

कृष्ण प्रताप सिंह

उसे जाने क्या सूझी कि वह इस चुनाव में पार्षदी की प्रत्याशी बन गई। फिर तो जैसे तहलका मच गया। शहर में जिधर देखिए उधर उसकी ही चर्चा होने लगी। वह जिधर भी चुनाव प्रचार करने निकलती, लोगों का मजमा लग जाता और उसकी सभाओं में लोग टूटे पड़ते। इस कदर कि पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रित करना खासा मुश्किल हो जाता। यह सब देखकर कोई और प्रत्याशी उसके मुकाबले उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।

ऐसे में कुछ अज़ीज़ों के दबाव में शहर के अकबरी गेट के पास के नामी हकीम शम्सुद्दीन ने मैदान में उतरने का हौसला दिखाया। अब मुकाबला 'तवायफ बनाम हकीम' बन गया तो लोगों को इस चकल्लस में और मजा आने लगा। लेकिन जमीनी हकीकत को महसूस करते हुए हकीम साहब को दिन में ही तारे नज़र आने लगे थे। आते भी क्यों नहीं, दिलरुबा के मुकाबले उनके समर्थक उंगलियों पर गिने जा सकते थे।

लेकिन वह हकीम कैसा, जिसके पास हर मर्ज का इलाज न हो! अजीजों से सलाह मशवरे के बाद उन्होंने चौक वार्ड के तमाम घरों की दीवारों पर यह चुटीली हिदायत लिखवा दी -

*'है हिदायत चौक के हर वोटर-ए-शौकीन को, दीजिए दिल दिलरुबा को, वोट शम्सुद्दीन को!'*

### अवधनामा

AI Image

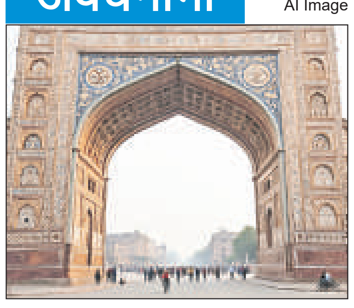

देखते ही देखते, यह हिदायत रंग लाने लगी तो निराश हकीम साहब की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगीं।

लेकिन दिलरुबा भी कम न थीं। आसानी से मैदान छोड़ना गवारा नहीं किया। हकीम साहब के ही अंदाज में वोटरों के घरों पर जवाबी हिदायत लिखवा दी :

*'है हिदायत चौक के हर वोटर-ए-शौकीन को, वोट देना दिलरुबा को, नब्ज शम्सुद्दीन को!'*

उसकी बदकिस्मती कि चौक के 'वोटर-ए-शौकीन' वोट देने पोलिंग बूथों पर गए तो उसकी हिदायत भूल गए।

फलस्वरूप मतगणना के बाद नतीजा आया तो हकीम शमसुद्दीन चुनाव जीत गए और तवायफ दिलरुबा हार गई। स्वाभाविक ही इससे दिलरुबा को बहुत निराशा हुई। लेकिन हकीम शम्सुद्दीन को जीत की बधाई देते हुए उसने एक और बड़ी ही चुटीली बात कही - हकीम साहब, आपकी जीत आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इससे सिर्फ यह बात साफ हुई है कि नवाबों के इस शहर के चौक में मर्द कम हैं और मरीज ज्यादा।' बेचारे हकीम साहब क्या जवाब देते!

### THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

## भीड़ में भी मन को शांत रखने वाला सच्चा तपस्वी

श्री श्री आनंदमूर्ति

**अक्सर हम** सोचते हैं कि तपस्या या साधना केवल हिमालय की गुफाओं में, संसार से दूर रहकर ही की जा सकती है। लेकिन सच्ची तपस्या किसी स्थान पर निर्भर नहीं करती, वह तो मन की अवस्था है। जिस क्षण मन संयमित हो जाता है, वहीं से साधना आरंभ होती है।

जीवन में हर व्यक्ति के सामने दो मार्ग आते हैं - श्रेय और प्रेय। प्रेय वह है, जो अभी सुख देता है, लेकिन आगे चलकर दुख या बंधन का कारण बनता है। जैसे - इंद्रियों की इच्छाएं, आलस्य या झूठे सुख अपनी तरफ खींचते हैं और हम कमजोर पड़ने लगते हैं। श्रेय वह मार्ग है जो शुरू में कठिन लगता है, पर आत्मा को ऊंचा उठाता है। संयम, सत्य, कर्तव्य और आत्मनियंत्रण श्रेय के मार्ग हैं। श्रेय वह है जो दीर्घकाल में सही हो, जैसे ईमानदारी से पढ़ाई या मेहनत से करियर बनाना, जबकि प्रेय वह है जो तुरंत सुख दे, जैसे मनोरंजन या आराम। दोनों का संतुलन आवश्यक है। विद्यार्थी परीक्षा के समय लगातार मोबाइल चलाने में समय गंवाता है, तो वह तात्कालिक सुख (प्रेय) के कारण अपने स्थायी हित (श्रेय) को खो देता है।

AI Image

हिमालय की ठंडी चोटियों पर जाकर साधना करना सरल हो सकता है, लेकिन असली साधना तो संसार के बीच रहकर भी मन को शांत और पवित्र रखना है। जो व्यक्ति भीड़ में रहकर भी भीतर से एकाग्र है, वही है सच्चा तपस्वी। तपस्या का अर्थ है - अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। आंख वही देखे जो पवित्र है, वाणी वही बोले जो हितकारी है और मन वही सोचे जो शुभ है। इस संतुलन से घर ही आश्रम बन जाता है और मनुष्य स्वयं साधु।

सच्चा साधु वह नहीं जो वस्त्र बदल ले, बल्कि वह है जो विचारों को बदल ले। जो अपने भीतर की अशुद्धियों से लड़े, वही तपस्वी है। इसलिए तपस्या के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं, हिमालय तो मन में बसाना है, जहां विचार निर्मल हों और आत्मा शांत।

वहीं से आरंभ होती है वह यात्रा, जो हमें परमात्मा के साक्षात्कार तक ले जाती है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

### कांटे की बात

### छोटी सोच, बड़ा फ़र्क़

सम्राट चौधरी, BJP नेता

## असली पहाड़ी स्वाद फैला रहा गढ़भोज

*काले भट का साग, मंडुवे की रोटी... पिज्जा-नूडल्स के आगे बच्चों को यह सब खिलाना बहुत मुश्किल है। इसी चुनौती से निपट कर उत्तराखंड के पारंपरिक खानपान को बढ़ावा दे रहा है 'गढ़भोज' अभियान।*

**रेस्तरां में 'मोटा अनाज'**

उत्तराखंड के स्कूल-कॉलेजों, पुलिस मेस और यहां तक कि होटल-रेस्तरां में भी चौलाई, लाल भात, लिंगड़ा, झंगोरा की वापसी हो रही है और इसका बहुत कुछ क्रेडिट जाता है 'गढ़भोज' को। इसकी शुरुआत की थी उत्तरकाशी के द्वारिका सेमवाल ने। सरकारी समर्थन के लिए वह सीएम से मिले। पहली बार 7 अक्टूबर 2022 को देहरादून के स्कूलों में मिड-डे मील में पारंपरिक भोजन परोसा गया। इसके बाद से विभिन्न स्तरों पर तमाम लोग अभियान से जुड़ते गए।

**पहाड़ की जरूरत**

पारंपरिक भोजन की पहचान का यह संघर्ष अलग उत्तराखंड राज्य के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के साथ पीछे छूट गया। आर्थिक और स्वास्थ्य, दोनों स्तरों पर इसके नुकसान हुए। द्वारिका कहते हैं कि पारंपरिक फसलों की ओर मुड़कर खाद्यान्न संकट को भी टाला जा सकता है। पहले गांवों के कोठार-भंडार भरे रहते थे, अब गेहूं-चावल बाहर से खरीद कर आता है और धराली जैसी आपदा आए तो लोग खाने को मोहताज हो जाते हैं। 'मोटा अनाज' पहाड़ों की पहचान ही नहीं जरूरत भी है।

### मीम बहार

वो जो हममें तुममें करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो

## क्या नीतीश के पास है जीत की जादुई छड़ी

नरेन्द्र नाथ

**बिहार में** विधानसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। नवंबर में दो चरणों में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को परिणाम आएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA एक बार फिर से सत्ता में आने की आशा कर रहा है। इसके लिए नीतीश की रणनीति अपने कोर वोटरों को साथ बनाए रखने की है। यह कोर वोटर है महिलाओं का। NDA को लगता है कि अगर फिर से महिलाओं का साथ मिल गया तो सत्ता की सीढ़ी तक वह फिर पहुंच जाएगा। यही कारण है कि चुनाव से पहले एक करोड़ से अधिक महिलाओं को सरकार ने 10 हजार रुपये की बड़ी रकम एक साथ ट्रांसफर की है। लाखों और महिलाओं के खाते में पैसे जाने अभी बाकी हैं। उधर, तेजस्वी की अगुआई में I.N.D.I.A. ब्लॉक अभी इसकी काट नहीं खोज पाया है। लेकिन उसने भी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया है, जो नीतीश के दांव के आगे हल्का लग रहा है।

### सफलता का पुराना फॉर्म्युला

नीतीश का पूरा फोकस महिला वोटरों पर है। 2005 से अब तक महिलाएं और महादलित उनके साइलेंट कोर सपोर्ट रहे हैं। खासकर, महिला वोटर चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ा X फैक्टर बनकर उभरती रही हैं। नीतीश जब 2005 में सत्ता में आए थे तो उन्हें पता था कि राज्य की राजनीति जातीय समीकरण में उलझी है। नीतीश की जाति राज्य में बड़ा आधार नहीं रखती थी। इसीलिए उन्होंने महिलाओं और महादलितों-अतिपिछड़ों के बीच पार्टी का विस्तार किया। वह हर बार अपनी पार्टी के घोषणापत्र में महिलाओं के लिए खास वायदे भी करते रहे हैं, जो निर्णायक भी साबित होता रहा है। 2015 में उन्होंने शराबबंदी और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का वादा किया था। यह दांव सफल रहा। चुनाव बाद आए सर्वे में बताया गया कि 60% से अधिक महिलाओं ने उस चुनाव में नीतीश के पक्ष में वोट किया था। 2009 की जीत में स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकल देने की घोषणा का अहम रोल था। इसकी वजह यह भी है कि बिहार में महिलाओं की वोटिंग में शानदार बढ़ोतरी हुई है। 2020 में नीतीश ने 'जीविका दीदी' योजना पर फोकस किया, जो उनके लिए ब्रैंड एंबेसडर बनी।

विशुद्ध राजनीति कसौटी

### साइलेंस फैक्टर की काट!

नीतीश के करीबी रणनीतिकारों का दावा है कि हर बार चुनाव से पहले उनके बारे में नकारात्मक बातें होती हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। इनका दावा है कि साइलेंट वोटर इस बार भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस मजबूत किले में माई-बहिन योजना की बदौलत सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हर महिला को 2,500 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। वह नीतीश सरकार के महिलाओं के खाते में 10 हजार ट्रांसफर किए जाने की योजना को काउंटर करने के लिए वादा कर रहे हैं कि सत्ता में आए तो 2,500 रुपये की योजना को लागू करने के साथ ही हर महिला के खाते में पूरे साल का एकमुश्त 30 हजार रुपया एडवांस दे देंगे। I.N.D.I.A. ब्लॉक महिला वोटरों का डेटा बनाकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसका गणित है कि अगर इसमें कुछ हद तक भी सेंध लगाने में सफलता मिल गई तो सियासी संतुलन उसके पक्ष में आ जाएगा। मगर सवाल यह है कि क्या विपक्षी गठबंधन नीतीश के कोर वोटरों के किले में सेंध लगा पाएगा?

### रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

## जीवनशैली में सुधार

**7 अक्टूबर** का लेख 'हमारे दिखावे की कीमत चुका रही धरती' पढ़ा। सचमुच आधुनिक जीवनशैली और दिखावे की संस्कृति ने पर्यावरण पर गहरा असर डाला है। उपभोग की अंधी दौड़ ने न केवल संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हमारी संवेदनशीलता भी कम की है। यह लेख संदेश देता है कि असली सफलता भौतिक वस्तुओं के बेतहाशा उपभोग में नहीं, बल्कि ऐसी जीवनशैली में है जो प्रकृति के अनुकूल हो। यदि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और उपभोग की आदतों पर फिर से सोच-विचार करें, तो एक टिकाऊ और संतुलित भविष्य का निर्माण होगा।

**गिरीश डोभाल**, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।


**आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957** स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्स: (022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांस: (022) 66353636, 22733636 फैक्स: (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • बुधवार • 8 अक्टूबर • 2025
www.rashtriyasahara.com



अनमोल वचन

*अगर तुम किसी चीज को पसंद नहीं करते हो तो उसे बदल दो।
अगर बदल नहीं सकते तो अपना रवैया बदल दो।*
-माया एंजेलो

# एक करोड़ महिलाओं की ताकत

नई वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के समकाल और देशकाल को देखना खासा दिलचस्प है। समाज, राजनीति और लोकतंत्र की बात करें तो देश आपातकाल से पांच दशक आगे निकल चुका है। यह भी कि इस वर्ष जब आखिरी विधानसभा चुनाव के रूप में बिहार में नई सरकार चुनी जानी है तो जयप्रकाश आंदोलन के भी पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से बिहार इस आंदोलन का एक तरह से एपिक सेंटर था। इन पांच दशकों में जरूर गंगा में बहुत पानी पानी बह चुका है, पर समय के इस बहाव के बीच कुछ चीजें स्थिर भी हुई है और वे नई मिसालें और मानदंडों के साथ हमारे समय में लोकनीति और विकास को व्याख्यायित कर रही हैं। इस बात की बड़ी अहमियत है कि जिस बिहार में आकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र देश-दुनिया को दिया, आज उस सूबे की धरती पर महिलाओं ने एक बड़ी मूक क्रांति को सच कर दिखाया है। यह क्रांति महिला सशक्तीकरण की इकहरी समझ से आगे कई मायनों में सर्व-समावेशी है और इससे इस प्रदेश की महिलाओं के साथ ग्रामीण इलाकों में विकास और बदलाव का एक सर्वथा नया दौर सामने आया है। इस लिहाज से इन दिनों मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की खासी चर्चा है। आकार के लिहाज से यह देश की ऐसी सबसे बड़ी योजना है, जिसने न सिर्फ सामाजिक बदलाव की जमीन को मजबूत किया है, बल्कि इसे महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का सर्वथा नया दौर शुरू हुआ है।

गौरतलब है कि बीते 26 सितंबर को जब यह योजना शुरू हुई तो 75 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में दस-दस हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके कुछ ही दिन बाद 25 लाख और महिलाओं को इसमें जोड़ा गया और उनके भी खाते में पैसे पहुंचे। इस तरह 75 लाख का आंकड़ा देखते-देखते एक करोड़ पर पहुंच गया। राज्य क्या देश के स्तर पर पर भी यह संख्या ऐतिहासिक तौर असाधारण है। महिलाओं को यह राशि स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए दी जा रही है। वस्तुतः चुनाव से पूर्व होने वाली तमाम तरह की अव्यावहारिक और हवाई घोषणाओं से अलग बिहार सरकार ने कैबिनेट स्तर पर बीते कुछ महीनें में कई अहम फैसले लिए है। इस क्रम में जो बड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया है, वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। राज्य सरकार ने इस योजना को प्रदेश की महिलाओं की स्थिति और जरूरत को समझते हुए न सिर्फ फ्रेम किया, बल्कि इसके शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर भी वह लगातार गंभीर रही। योजना के तहत जिन महिलाओं को दस हजार रुपए की मदद मिलीहै, उन्हें छह महीने बाद मूल्यांकन पर खरा उतरने पर दो लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

बात महिला सशक्तीकरण की हो रही है तो यह जान लेना जरूरी है बिहार में नीतीश सरकार की सबसे सफल योजनाओं में जीविका है। विश्व बैंक की मदद से वर्ष 2006 में शुरू इस योजना के बूते आज राज्य में एक करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाएं 11 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जीविका दीदी के रूप में पहचान बना चुकी है। ये महिलाएं सिलाई, बुनाई, कृषि, पशुपालन, किराना दुकान, मसाला निर्माण, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन जैसे छोटे-छोटे उद्योगों के जरिए न केवल अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। आज की तारीख में जीविका देश में महिला स्वरोजगार का सबसे बड़ा समूह है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जीविका के ही मॉडल का विस्तृत रूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। इन महिलाओं को सरकार की आर्थिक मदद स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे बिजनेस शुरू करने या वर्तमान में चल रहे व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता के उद्देश्य से दी जा रही है। इससे बड़ी किसी योजना की सफलता और उपयोगिता क्या होगी कि इसके लिए 1.05 करोड़ जीविका दीदियों ने, जबकि 1.40 लाख से अधिक महिलाओं ने समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया।

जो लोग बिहार की राजनीतिक-सामाजिक स्थिति को कम से कम बीते दो दशकों से गौर से देख रहे है, वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस विवेक की जरूर दाद देते है कि इन वर्षों में उन्होंने सूबे की महिलाओं को सिर्फ मतदाता नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की धुरी बनाया। भूले नहीं है लोग कि देश में मंडल और कमंडल की राजनीति के अश्वमेध का घोड़ा एक साथ दौड़ा तो बिहार की जनता ने राजनीति से जुड़े सामाजिक सरोकारों का तार्किक चुनाव किया। इस मॉडल के नायक निस्संदेह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिनकी मौजूदगी आज प्रदेश में हर राजनीतिक गठजोड़ के लिए अपरिहार्य बनी हुई है। उनकी मौजूदगी एक तरफ सांप्रदायिकता के खिलाफ सद्भाव की राजनीति का आश्वासन है, तो वहीं महिलाओं और अति पिछड़ों के कल्याण को लेकर बीते दो दशक में उन्होंने सफलता की एक लंबी पटकथा लिखी है।

नए विकासवादी अभिप्रायों और लक्ष्यों के साथ बिहार को लेकर इस रूप में चर्चा का आज की तारीख में महत्व इसलिए भी है कि इससे विकास के साथ सामाजिक बदलाव के लक्ष्य को साधने वाली राजनीति की भूमिका नए सिरे से रेखांकित होती है। यह भूमिका हमारा ध्यान उस मूक क्रांति की तरफ ले जाती है जिसके बारे में बीते दो दशक में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से लेकर विश्व मुद्रा कोष तक ने विमर्श और समकालीन नैतिक दरकार के लिहाज से काफी कुछ कहा और लिखा है। यहां तक कि दुनियाभर की सरकारों के बीच कोरोना महामारी के बाद यह नैतिक दरकार उनकी नीतिगत प्राथमिकता की एक बड़ी कसौटी बन चुकी है। बिहार आज इस कसौटी पर खरा उतरता दिख रहा है तो यह देश में राज्यों के नए वर्ग चरित्र का भी उद्घाटन है। इस चरित्र के साथ हम बदलते देश-समाज के साथ राज्यों की नई बन रही पहचान को देख सकते है। यह पहचान सामाजिक बदलाव के ऊंचे लक्ष्य को जिस तरह स्पर्श कर रही है, वह शानदार है। खासतौर पर बिहार के लिए यह गर्व की बात है कि देश में पंचायतीराज व्यवस्था और नगर निकायों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण सबसे पहले देने वाले इस सूबे के पास आज महिला स्वावलंबन का अपना मॉडल तो है ही, सुशासन के रूप में नीति और राजकाज का साफ-सुथरा विवेक भी है।

कटाक्ष/अनुराग पंडित

## जंगलराज, सुशासन व तड़केदार बिहार

बिहार की राजनीति कोई साधारण सब्ज़ी नहीं, यह एक ऐसी हांडी है जिसमें दशकों से लालू प्रसाद यादव का 'जंगल राज, नीतीश कुमार का 'सुशासन' और भारतीय जनता पार्टी का 'राजनीतिक तड़का' एक साथ पकते आ रहे हैं। जनता हर पांच साल बाद इस व्यंजन का स्वाद चखती है -कभी नमक कम कहती है, कभी मिर्च ज़्यादा, मगर खाती वही रहती है। लालू यादव के दौर में बिहार को जंगल राज का तमगा मिला। सड़कों पर गड्ढे थे और सरकारी दफ्तरों में रईस। उस समय पुलिस से ज़्यादा असरदार नेता का चमचा हुआ करता था। मगर लालू जी के भाषण और हास्यबोध ने जनता को इतना हंसाया कि लोग भूख भूल गए। लालू जी ने लोकतंत्र को लोक-तमाशा में बदल दिया था, और जनता हंसी-हंसी में वोट डालती रही। फिर आए नीतीश कुमार सुशासन बाबू। उन्होंने बिहार को बनाएंगे सिंगापुर का सपना दिखाया। सड़कों पर गड्ढे भरे गए, बिजली आई, स्कूलों में साइकिलें बंटी और शराब पर पाबंदी लग गई यानि बिहारवासी बिना दारू के ही राजनीति का नशा चढ़ाने लगे। नीतीश जी ने विकास का ऐसा मॉडल दिया कि लोग भ्रमित हो गए सच में सुधार हुआ है या बस स्लोगन बदल गया है? अब कहानी में एंट्री हुई बीजेपी की यानी तड़का लगाने वालों की पार्टी। बीजेपी का काम हमेशा से रहा है कि जो पक रहा हो, उसमें अपना मसाला डाल दो। लालू के जंगल राज में उन्होंने कानून-व्यवस्था का तड़का लगाया, और नीतीश के सुशासन में हिंदुत्व का। कभी गठबंधन किया, कभी तोड़ा, फिर किया, फिर तोड़ा यानी बिहार की राजनीति अनुसंधान प्रयोगशाला बन गई, जहां हर फार्मूला बार-बार आज़माया जाता है। आने वाले मतदान में जनता जानती है कि नतीजा कुछ भी हो, सरकार वही होगी जिसमें थोड़ा जंगल, थोड़ा सुशासन और थोड़ा तड़का ज़रूर होगा। आज का बिहार इस राजनीतिक मिश्रण का जीवंत उदाहरण है न पूरी तरह शांत, न पूरी तरह उथल-पुथल। यहां राजनीति कोई विचारधारा नहीं, बल्कि कला है जिसमें लालू की हंसी, नीतीश की चालाकी और बीजेपी की रणनीति मिलकर एक ऐसा व्यंजन तैयार करती है जिसे देश भर के नेता चखना चाहते हैं। बिहार की राजनीति का यही तो कमाल है यहां शासन बदलता रहता है, मगर स्वाद वही रहता है जंगलराज में सुशासन का तड़का।

# बिहार का रण...

## मुस्लिम बहुल सीटों पर कमल खिलाने की चाह

बिहार चुनाव

विवेक शुक्ला

बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। यह चुनाव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को दो-तिहाई बहुमत के साथ विजयी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए है। शाह का दावा है कि राजग न केवल पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, बल्कि घुसपैठियों को राज्य की पवित्र धरती से बाहर भी करेगा।

**सीमांचल पर विशेष ध्यान :** अमित शाह का फोकस इस बार सीमांचल (पूर्वोत्तर बिहार) के नौ जिलों पर है, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम तैनात की है। उनकी रणनीति साफ है राजद और एमआईएम के गढ़ में कमल खिलाना। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में राजग के लिए 160 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। सीमांचल में घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, जहां मुस्लिम आबादी काफी है और घुसपैठ हिंदुओं के लिए समस्या बनी हुई है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में हिंदू पर्वों और त्योहारों पर पथराव और हिंसा की घटनाएं सामने आई है, जिसे शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से लिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में शामिल होने के मुद्दे को उठाया था। शाह और मोदी ने कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के जवाब में घुसपैठियों के मताधिकार को मुद्दा बनाया है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद लगभग 45 लाख पुराने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए है।

**भाजपा के तरकश में कई तीर :** भाजपा केवल घुसपैठ के मुद्दे पर निर्भर नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद बिहार में मां जानकी मंदिर का निर्माण, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये का वितरण, और अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार जैसे मुद्दे भी अभियान का हिस्सा है। यह चुनाव भाजपा और विशेष

रूप से प्रधानमंत्री मोदी के लिए सामान्य नहीं है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मोर्चो पर चुनौतियों के बीच यह चुनाव राजग के लिए बड़ी परीक्षा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वैश्विक दबावों का सामना करने की सरकार की दृढ़ता ने भारत को गर्व का विषय बनाया है। सवाल यह है कि क्या मोदी बिहार के मतदाताओं पर अपना जादू चला पाएंगे?

**मोदी और शाह का बिहार में दबदबा:** बिहार में भले ही राजग के बैनर तले चुनाव लड़ा जा रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह मोदी और शाह का चुनाव है। 2014 से अब तक भाजपा का सफर 'मोदी युग' के नाम से जाना जाता है। यह केवल इसलिए नहीं कि भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ है, बल्कि इसलिए भी कि विश्व ने भारत को 'मोदी के भारत' के रूप में देखना शुरू किया है। मोदी का व्यक्तित्व मेहनत, कुशल टीम और ठोस नियोजन का परिणाम है। 75 वर्ष की आयु में भी वह अपनी रणनीतिक समझ और संगठनात्मक कौशल से सबको प्रभावित करते है।

मोदी ने विश्वास निर्माण का अनूठा प्रयोग किया है। 1985-1990 के बीच गुजरात में भाजपा के लिए काम करते हुए उन्होंने और अमित शाह ने पहली बार अपनी जोड़ी का कमाल दिखाया। तब से शाह हर चुनाव में मोदी की जीत के शिल्पकार बने हैं।

**बिहार में शाह की रणनीति :** बिहार में एक बार फिर अमित शाह की संगठनात्मक क्षमता की परीक्षा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों में उनकी रणनीति की सफलता देखी जा चुकी है। बिहार में भी वह सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रहे हैं, जिसमें जातिगत समीकरणों को साधना शामिल है। नए चेहरों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, और मुद्दों व नारों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना, और देशव्यापी जाति सर्वेक्षण जैसे मुद्दे जोर-शोर से उठाए जाएंगे।

भाजपा ने 40 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी है और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल है। मंदिर और मंडल दोनों मुद्दों को साथ लेकर चलने में शाह की विश्वसनीयता स्थापित है। अमित शाह की संगठनात्मक क्षमता और नरेंद्र मोदी की रणनीतिक समझ बिहार में राजग की जीत की कुंजी है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक शाह ने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। बिहार में क्या वह हरियाणा की सफलता को दोहरा पाएंगे? यह समय बताएगा।

*(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)*

**243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में राजग के लिए 160 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। सीमांचल में घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, जहां मुस्लिम आबादी काफी है और घुसपैठ हिंदुओं के लिए समस्या बनी हुई है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में हिंदू पर्वों और त्योहारों पर पथराव और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से लिया है।**

## शांति और मुक्ति का मार्ग है 'काशी'

**उत्तर प्रदेश** राज्य में स्थित काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे बनारस भी कहते हैं। काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक मानी जाती है। यह नगर न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। काशी के हृदय में स्थित है भगवान शिव का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, जो श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है।

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार काशी वह नगरी है जिसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। यह नगर 'अविनाशी' कहा गया है, क्योंकि माना जाता है कि जब समूचा संसार प्रलय में डूब जाता है, तब भी काशी अक्षुण्ण रहती है। यहां स्थित विश्वनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में केवल दर्शन मात्र से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

काशी की पवित्रता का आधार केवल मंदिर नहीं, बल्कि यहां की गंगा नदी भी है। गंगा के तट पर बसे घाट दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, अस्सी आदि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट को मोक्षदायिनी कहा गया है, जहां अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हर दिन हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान, पूजा और आरती के लिए काशी आते है। काशी में हर पल भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। यहां की संध्या गंगा आरती, मंदिरों की घंटियां और साधु-संतों की तपस्या एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करती है। काशी न केवल भक्ति की भूमि है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, दर्शन और ज्ञान का भी केंद्र रही है। यहां से अनेक संत, कवि और दार्शनिक उत्पन्न हुए जिन्होंने भारतीय सभ्यता को नई दिशा दी। वास्तव में, काशी विश्वनाथ का दर्शन केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का माध्यम है। यह हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन अस्थायी है, पर आत्मा अमर है। काशी की महिमा में डूबकर हर भक्त यह अनुभव करता है कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल भक्ति और आत्मसमर्पण में निहित है। काशी सचमुच वह भूमि है जहां ईश्वर स्वयं वास करते है 'काश्यां हि काशते काशी'।

## शिक्षकों पर क्यों लटकी तलवार?

मुद्दा | रोहित कौशिक

पूरे देश में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षक इन दिनों भारी मानसिक दबाव झेल रहे हैं। कारण है सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करने का आदेश दिया गया है। टीईटी के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह सही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में नियम और कानून के हिसाब से अपना फैसला दिया है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला व्यावहारिक है ? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला दे दिया है लेकिन देश की संसद क्या कर रही है ? इस मुद्दे पर राजनेता चुप क्यों है ? जो शिक्षक पचास या पचपन वर्ष के हो चुके हैं क्या उनके लिए यह फैसला व्यावहारिक है ?

पिछले कुछ समय से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें शिक्षकों पर विभिन्न तरह के दबाव डाल रही है। शिक्षा प्रदान करने के अलावा शिक्षकों से हजार काम लिए जा रहे है, इसके बावजूद शिक्षकों को पापी सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अब कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक का समय बाकी है, उन्हें दो साल के भीतर टीईटी पास करना होगा। अगर वे इस अवधि में परीक्षा पास नहीं कर पाते है तो उन्हें सेवा छोड़नी पड़ेगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। हालांकि जिनकी सेवा अवधि पांच साल से कम है उन्हें टीईटी पास करने की बाध्यता नहीं है लेकिन वे प्रमोशन के लिए अयोग्य रहेंगे। यह नियम सरकारी और निजी दोनों शिक्षकों पर लागू होगा। हालांकि फिलहाल अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे छूट दी गई है। इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया है। खबर है कि फैसले का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

शिक्षकों का कहना है कि पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे, उनकी भर्ती उस समय के नियम और मानकों के हिसाब से हुई थी। अब सेवा के आखिरी वर्षों में उनसे टीईटी पास करने को कहना न्यायसंगत नहीं है। दरअसल पचास-पचपन की उम्र के बाद इंसान कई तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव झेल रहा होता है। इस उम्र में वह पढ़ा तो सकता है लेकिन अगर उससे कहा जाएगा कि आप परीक्षा पास कीजिए नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी तो उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ जाएगा। यही कारण है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिक्षक परेशान है। शिक्षकों के लिए समय-समय पर कई तरह की रिफ्रेशर कोर्स चलते रहते हैं। बेहतर होता कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देती। इस तरह का अव्यावहारिक फैसला शिक्षकों पर थोपना उनके साथ अन्याय है। टीईटी के संबंध में यह फैसला कई तरह से व्यावहारिक नहीं है। स्कूलों में बड़ी संख्या में बीएड, बीपीएड, इंटरमीडिएट पास तथा बीटीसी मुक्त शिक्षक हैं। कई शिक्षक मृतक आश्रित कोटे में भी भर्ती हुए हैं। शिक्षकों की भर्ती के मानक अलग अलग समय पर अलग अलग रहे। जैसे उत्तर प्रदेश में 1898 से पहले बारहवी पास और बीटीसी के आधार पर भर्ती हुई। 1999 से इसे स्नातक किया गया, इसमें कुछ बीएड और बीपीएड लोग भी आए। यानी उस समय जो मानक थे उसी के आधार पर शिक्षकों की भर्ती हुई। एक व्यावहारिक दिक्कत यह है कि अगर कोई बारहवी पास शिक्षक टीईटी पास करना चाहे तो उसे पहले स्नातक की परीक्षा पास करनी होगी और फिर बीटीसी का प्रशिक्षण लेना होगा, तब जाकर वह टीईटी कर पाएगा। यानी इसमें काफी साल लग जाएंगे। जबकि टीईटी पास करने के लिए सिर्फ दो साल का समय दिया गया है।

शायद ही किसी नौकरी में मानक इतनी बार बदले गए हों जितनी बार शिक्षकों की भर्ती में बदले गए हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों पर समय-समय पर कई तरह के दबाव बनाए जाते हैं। समाज के कुछ लोग भी यह प्रदर्शित करने से पीछे नहीं हटते कि शिक्षक तो फ्री का वेतन ले रहे हैं। ऐसे लोग इस बात को भूल जाते है कि शिक्षकों को गांव-गांव मंप धूप, बारिश और बाढ़ में भी काम पर लगा दिया जाता है। अगर स्कूल में बच्चे नहीं आते है तो उसमें भी शिक्षकों की गलती निकाल दी जाती है। सवाल यह है कि जानबूझकर शिक्षकों का शोषण करने की कोशिश क्यों की जा रही है ? अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में आशा की एक किरण दिखाई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी है और समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षकों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है। देश के कई अन्य राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों में नाराजगी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में समय-समय पर कई तरह की असमानताएं रही है। इन असमानताओं को किसी एक नियम से दूर नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों की भर्ती किसी अनुकंपा के आधार पर नहीं की गई है। नियम और कानून के अनुसार ही की गई है। इसलिए अब शिक्षकों पर इस नियम को लादना उसके साथ अन्याय होगा। इस समय शिक्षकों की नौकरी बचाने और उन्हें मानसिक तनाव से बचाने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को गंभीर पहल करनी चाहिए।

अध्यात्म प्रेम | संत राजिन्दर

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा के साथ अपना नाता और अपने उद्देश्य का रास्ता खोज रहे हैं। जो लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो बहुत उत्साह के साथ खोज रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो बड़े जुनून और बड़े उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उनकी रुचि कम हो जाती है, और वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल होते हैं। अगर हमें इस जीवन में अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा करना है, तो हमें इस लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहिए। इस मानव जन्म का लक्ष्य हमारी आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन की तड़प को पूरा करना है। अध्यात्म प्रेम का एक मार्ग है, और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो अपनी वास्तविक पहचान जरूरी है। क्या हम आध्यात्मिक अनुभव की खोज में भौतिक शरीर हैं, या हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, जिसमें भौतिक स्तर पर अनुभव कर रहे हैं? इसी में परमात्मा को पाने का रहस्य छुपा है। हम सब आत्माएं हैं। जैसे हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, इसी रूप में ही वास्तव में स्वयं को जानने की सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। यह आत्मा को परमात्मा के प्रेम का अनुभव करने और परमात्मा के पास वापस जाकर अपनी लंबी यात्रा को पूरा करने का मौका है। अभी हम सब इंद्रियों के स्तर पर जी रहे हैं, और सिर्फ वही अनुभव कर रहे हैं, जो जड़ पदार्थ से बना है। प्रभु, जो चेतना के महासागर हैं, के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से चेतन अवस्था में रहने और अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागृत होने की आवश्यकता है। आत्मा और परमात्मा को खोजने के लिए हमें हमारी खोज पर ही ध्यान देना चाहिए और किसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम परमात्मा से संवाद करते हैं, तब हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें परमात्मा को पाने के नशे में मस्ती की गहराई में डुबकी लगा कर ऊपर के मंडल में उड़ान भरनी है। ध्यान-अभ्यास में एकाग्र चित्त होकर बैठना चाहिए। हमें ध्यान-अभ्यास के दौरान किसी और चीज को बीच में नहीं आने देना चाहिए।

## रीडर्स मेल

### आतंकवाद पर दोहरापन नहीं चलेगा

आतंकवाद के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने अभी तक का सबसे बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत कोई भी दोहरा रवैया कतई सहन करने नहीं जा रहा है। पहलगाम हमला भारत पर ही नहीं, बल्कि मानवता में विश्वास करने वाले हर देश, व्यक्ति के लिए खुली चुनौती था। आज कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इस घोषणापत्र में दोहरे मापदंडों को खारिज करते हुए आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सीमा पार आतंकियों की आवाजाही पर रोक लगाने की भी मांग की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत पिछले चार दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। अतः हमें मिल कर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में कड़ा विरोध करना होगा। कह सकते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन द्वारा पहलगाम आंतकवाद की निंदा करना भारत की एक कूटनीतिक जीत है।

**मनमोहन राजावत 'राज', बैशाली बिहार**

### जीएसटी में राहत स्वागतयोग्य

केंद्र सरकार ने कुछ खाद्य पदार्थों जैसे पनीर, रोटी, चपाती, छेना, टेट्रा पैक आदि को करमुक्त कर लोगों को राहत दी है। महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ हुआ था। दैनिक प्रयोग की कुछ खाद्य वस्तुओं और कपड़े पर कर की स्लैब कम करना आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं भी टैक्स फ्री करने से लोगों की जेब पर अब बोझ कम होगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को करमुक्त करने से ज्यादा लोग इन्हें लेंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूती आएगी। हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसद का अतिरिक्त स्लैब लगाना स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है। कुल मिला कर सरकार ने लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने की कोशिश की है।

**अभिलाषा गुप्ता, दिल्ली**

### जीवन में गुरु का बड़ा महत्त्व

शिक्षा अमृत की एक ऐसी बूंद है, जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना अपूर्ण है। इसी परिपथ पर जीवन के निर्माण में शिक्षक अपनी भूमिका पथिक के रूप में निभाता है, जिस पथ पर शिष्य चल कर अपने जीवन को संभाल सकता है। शिक्षक के बारे में कहा गया है कि 'असतो मा ज्योतिर्गमय' जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन में गुरु का बड़ा महत्त्व होता है जो ताले की चाबी की तरह है। हम सभी को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य, मां को अपने बेटे, किसान को ललहाते खेत देख कर जो आनंद आता है, शायद ही इस पृथ्वी पर इससे बड़ा आनंद होता होगा। गुरु की महिमा अपरंपार है। इस समय होता था। ऋग्वैदिक काल में जब शिष्य-गुरु के आश्रम में रह कर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज डिजिटलाइजेशन के दौर में शिक्षक हमारे टेलीग्राम, पीएफ, वीडियो में कहीं दूर से शिक्षित कर रहे होते हैं। जो हमारे लिए अनमोल है, हमें उनका सम्मान एवं उनके प्रति आदर रखना चाहिए।

**तारामुनी देवी, पटियाला, पंजाब**

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष - 20, अंक 6796
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

# कोलकाता सबसे सुरक्षित

एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) ने अपराध दर्ज होने को आधार बनाकर देश के शीर्ष सुरक्षित शहरों की जो सूची जारी की है, उसमें लगातार चौथी बार कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर के रूप में सामने आया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है. वर्ष 2023 में कोलकाता में प्रति एक लाख की आबादी पर 83.9 संज्ञेय अपराध दर्ज किये गये, जो ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण किये गये 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 शहरों में सबसे कम है. एनसीआरबी के मुताबिक, अपराध नियंत्रण में तकनीक के इस्तेमाल, पुलिस के बेहतर समन्वय और रात्रि गश्त की सख्ती की इसमें अहम भूमिका है. कोलकाता पुलिस द्वारा शहरभर में लगाये गये सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम और डाटा आधारित निगरानी प्रणाली ने अपराध कम करने में मदद की है. पिछले कुछ वर्षों में कोलकाता की अपराध दर में लगातार कमी आयी है. वर्ष 2016 में वहां अपराध की दर प्रति एक लाख की आबादी पर 159.6 थी, जो 2021 में घटकर 103.5, 2022 में 86.5 और 2023 में घटकर 83.9 रह गयी. एनसीआरबी के अनुसार, यह गिरावट दर्शाती है कि शहर में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन ने अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार काम किया है. कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी कमी आयी है. वर्ष 2023 में कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ 1,746 अपराध दर्ज हुए, जबकि 2022 में यह संख्या 1,890 और 2021 में 1,783 थी. बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों के मामले में भी कोलकाता को देश का सबसे सुरक्षित शहर पाया गया है. राज्य सरकार का भी दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सुरक्षा, निगरानी प्रणाली और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया गया है. सुरक्षित शहरों की सूची में हैदराबाद दूसरे, पुणे तीसरे और मुंबई चौथे स्थान पर रही. अपराध दर के मामले में कोच्चि को सबसे असुरक्षित शहर पाया गया, जहां प्रति लाख की आबादी पर 3,092.4 अपराध दर्ज किये गये. दिल्ली दूसरे स्थान पर और सूरत तीसरे स्थान पर रहा. जबकि इससे पहले देश के असुरक्षित शहरों में दिल्ली लगातार सबसे ऊपर बनी हुई थी. वर्ष 2023 में पूरे पश्चिम बंगाल में कुल अपराध दर प्रति लाख की आबादी पर 181.6 रही, जो राष्ट्रीय औसत (433) से कम है. हालांकि उस साल राज्य में हत्या के आंकड़े जरूर 2022 की तुलना में अधिक थे, लेकिन हिंसक अपराधों में समग्र रूप से कमी आयी है और राज्य में अपराध का स्तर कई बड़े राज्यों की तुलना में कम है.

**कोलकाता का लगातार चौथे साल देश के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरना बड़ी उपलब्धि है. एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के मामले में भी अव्वल है.**

# ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के मायने

**शिवकांत**
पूर्व संपादक, बीबीसी हिंदी
shivkant.sharma@gmail.com

**लंदन से विशेष**

**भारत और ब्रिटेन ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीतियों के कारण व्यापार और सप्लाई चेनों में चल रही उथल-पुथल के बीच व्यापार के स्थिर विकल्पों की तलाश में हैं. इसीलिए स्टार्मर राजधानी दिल्ली की जगह वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा पर आये हैं. अमेरिका की देखा-देखी ब्रिटेन में भी आप्रवासियों के खिलाफ असंतोष की लहर चल रही है. भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि का संसदों में अनुमोदन होना बाकी है और भारतीय पेशेवरों व छात्रों के लिए वीजा बढ़ाने और सरल बनाने की मांग भारत की एक मुख्य शर्त रही है.**

ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर अपनी पहली भारत यात्रा पर आज मुंबई आ रहे हैं. उनकी यात्रा के तीन मुख्य उद्देश्य बताये जा रहे हैं. भारत-ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की प्रगति का आकलन करना, दोनों के बीच हुए व्यापक आर्थिक और व्यावसायिक समझौते-सीटा से खुले अवसरों के बारे में कारोबारियों और उद्योगपतियों से चर्चा करना, और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना. भारत और ब्रिटेन, दोनों ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीतियों के कारण व्यापार और सप्लाई चेनों में चल रही उथल-पुथल के बीच व्यापार के स्थिर विकल्पों की तलाश में हैं. इसीलिए स्टार्मर राजधानी दिल्ली की जगह वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा पर आये हैं. वह अपने साथ विदेश, वाणिज्य व शिक्षा विभागों के मंत्रियों के साथ इमर्जिंग और क्रिटिकल प्रौद्योगिकी में शोध और विकास करने वाले उद्यमियों व वित्तीय कंपनियों का एक बड़ा शिष्टमंडल भी लेकर आये हैं.

दोनों प्रधानमंत्री मुंबई में हो रहे फिनटेक- यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी के छठे अंतरराष्ट्रीय उत्सव में अभिभाषण देंगे. फिर भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल या टीएसआइ को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे. इसकी शुरुआत 2024 में दूरसंचार, क्रिटिकल खनिज, एआइ, क्वांटम और जैव प्रौद्योगिकी, प्रोन्नत पदार्थों और सेमीकंडक्टरों के क्षेत्र में सहयोग के लिए की गयी थी. अब दोनों देश उद्योगों को इन क्षेत्रों से जोड़ने, उनके लिए बीज पूंजी जुटाने और उससे त्वरित लाभ हासिल करने के उपाय खोज रहे हैं. दोनों प्रधानमंत्री इस पहल के सातों क्षेत्रों का आकलन कर यह तय करने की कोशिश करेंगे कि किन क्षेत्रों में सबसे तेज प्रगति हो सकती है. कार्नेगी न्यास के शोधकर्ताओं का कहना है कि टीएसआइ में भारत की निर्माण क्षमता और ब्रिटेन की शोध व विकास की गुणवत्ता को मिलाकर महत्वाकांक्षी और दूरगामी परियोजनाओं पर काम करने के प्रयत्न हो रहे हैं. इमर्जिंग और क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ इस यात्रा का उद्देश्य रक्षा सामान के साझा डिजाइन, साझा विकास और साझा निर्माण को आगे बढ़ाना भी है. भारत अब खरीदार की जगह रक्षा सामान का विक्रेता बनना चाहता है. इसके आकलन के लिए भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार परिषद की बैठक भी होगी, जो गत जुलाई में हुए मुक्त व्यापार सौदे के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी. इसमें व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही अड़चनों पर भी विचार होगा.

स्टार्मर और मोदी, दोनों राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं. भारत में बिहार और उसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने हैं, जिनमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगी. ब्रिटेन में स्टार्मर सरकार की लोकप्रियता भारी बहुमत से जीत कर आने के बावजूद निरंतर घट रही है, क्योंकि अमेरिका की देखा-देखी ब्रिटेन में भी घुसपैठियों और आप्रवासियों के खिलाफ असंतोष की लहर चल रही है. वास्तव में, ब्रिटेन समेत सभी पश्चिमी देशों में भारत के पेशेवरों, आप्रवासियों और छात्रों के लिए वीजा और सुरक्षा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. एच-1बी वीजा की फीस बढ़कर एक लाख डॉलर हो जाने के बाद जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन से ऐसे संकेत मिले थे, जैसे ये देश भारत की स्टेम प्रतिभाओं को हाथोंहाथ लेने की कोशिश करेंगे. पर आप्रवासियों के खिलाफ चल रही लहर को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतवंशी पेशेवरों और छात्रों के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू की हैं. ब्रिटेन में कार्य वीजा पर आने वाले लोग पांच साल रहने के बाद स्थायी निवास के वीजा के लिए आवेदन कर सकते थे, जिसे आइएलआर वीजा कहते हैं. गत सप्ताह सत्ताधारी लेबर पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में पाक मूल की नयी गृहमंत्री शबाना महमूद ने एलान किया कि सरकार स्थायी निवास के वीजा के आवेदन की योग्यता बढ़ाकर दस साल कर रही है. जो भारतीय पेशेवर और छात्र ब्रिटेन में बसने के इरादे से आये थे, उन्हें अब स्थायी निवास के वीजा के लिए दस साल प्रतीक्षा करनी होगी. यह सब ब्रिटिश राजनीति में चल रही आप्रवासी विरोधी लहर की वजह से हो रहा है. पिछले तीन दशकों से ब्रिटिश राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रहे धुर दक्षिणपंथी नेता नाइजल फराज ने जनता में सुगबुगा रही आप्रवासी विरोधी भावना भुना कर पिछले आम चुनाव में 14 फीसदी वोट के साथ संसद की पांच सीटें जीत ली थीं. फराज ट्रंप समर्थक हैं, इसलिए अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद ब्रिटेन में फराज और उनकी पार्टी की लोकप्रियता में उछाल आया. उनकी रिफॉर्म पार्टी लोकप्रियता में ब्रिटेन की तीनों स्थापित पार्टियों, लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल से आगे हैं. फराज ने एलान किया है कि अगला चुनाव जीतने पर वह आइएलआर वीजा रद्द कर आप्रवासियों को कड़ी शर्तों वाले नये वीजा का आवेदन करने पर विवश करेंगे. फराज की इस घोषणा से सत्ता बचाने को लेकर चिंतित ब्रिटिश पार्टियों में आप्रवासन की रोकथाम का एलान करने की होड़ लग गयी है.

ब्रिटेन में बसे 20 लाख से अधिक भारतवंशियों में से छह-सात लाख आइएलआर वीजा धारक हैं. हालांकि स्थायी निवास वीजा के लिए स्टार्मर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला 10 साल का नियम पहले से बसे आप्रवासियों पर लागू नहीं होगा. मगर स्थायी निवास को रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियों में चल रही होड़ को देखकर आप्रवासियों की चिंता स्वाभाविक है. मुक्त व्यापार संधि का अभी दोनों देशों की संसदों में अनुमोदन होना बाकी है और भारतीय पेशेवरों व छात्रों के लिए वीजा बढ़ाने और सरल बनाने की मांग भारत की एक मुख्य शर्त रही है. इसलिए दोनों प्रधानमंत्रियों की शिखर बैठक में इस विषय पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है. चर्चा ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और संजय भंडारी जैसे वित्तीय भगोड़ों के प्रत्यर्पण को सरल बनाने पर भी होगी, जो भारत से पैसा मारकर ब्रिटेन में शरण ले लेते हैं. भारत और ब्रिटेन ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों की वजह से बिखरती नियम आधारित विश्व व्यवस्था को लेकर भी चिंतित हैं. संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं निष्प्रभावी होती जा रही हैं. यूक्रेन युद्ध के यूरोप में फैलने का खतरा बढ़ रहा है और गाजा में ट्रंप की शांति योजना पर भी सवाल बने हुए हैं. हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ते चीनी हस्तक्षेप से मुक्त रखने की वैश्विक रणनीति उपेक्षित होती दिख रही है. चीन पश्चिमी एशिया में भी पाकिस्तान के माध्यम से अपना वर्चस्व फैला रहा है. जलवायु परिवर्तन की मार गंभीर हो रही है और उसकी रोकथाम के वैश्विक प्रयास कमजोर पड़ने लगे हैं. इन सभी मुद्दों पर मोदी और स्टार्मर के बीच सार्थक चर्चा होने की संभावना है.

**(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

# अपार नंबर से जुड़ी समस्याओं को दूर करना जरूरी है

**ज्यां द्रेज**
अर्थशास्त्री
jaandaraz@riseup.net

**पल्लवी कुमारी**
टिप्पणीकार
pallavi1999nivi@gmail.com

**सारंग गायकवाड़**
टिप्पणीकार
saranggaikwad32@gmail.com

विकी मुंडा रांची के निकट रातू में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है. उसके आधार कार्ड पर नाम 'बिक्की मुंडा' लिखा है, जबकि स्कूल रजिस्टर में 'विकी मुंडा' लिखा गया था, क्योंकि आधार कार्ड में जनसांख्यिकीय विवरण डाटा-एंट्री ऑपरेटरों ने जल्दबाजी में भरे थे. इसके कारण विकी के माता-पिता व शिक्षकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. विकी के शिक्षक उसके लिए 'अपार नंबर' जेनरेट नहीं कर पा रहे. यह एक विशेष पहचान संख्या है, जो बच्चों को डिजिलॉकर उपलब्ध करायेगी. इसके स्वैच्छिक होने का दावा किया गया है, पर यह अनिवार्य हो गया है. अधिकांश माता-पिता उस 'स्वीकृति फॉर्म' को नहीं समझते, जो उनसे साइन करवाया जाता है.

अपार नंबर बनाने के लिए जरूरी है कि बच्चे का नाम आधार कार्ड और यूडीआइएसइ डाटाबेस, दोनों में समान हो. यूडीआइएसइ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) शिक्षा विभाग का एक डाटाबेस है. झारखंड में, यूडीआइएसइ में बच्चों के नाम एक पुराने डाटाबेस 'ई-विद्या वाहिनी' से आयात किये गये थे और ये नाम स्कूल रजिस्टरों पर आधारित थे. आज उनमें से कई नाम आधार कार्डों से मेल नहीं खाते. अगर एक ही अक्षर के अंतर की बात है, तो अपार जेनरेशन सॉफ्टवेयर स्थानीय शिक्षक या ऑपरेटर को इसे ठीक करने की अनुमति देता है. पर यदि गलती ज्यादा हो- जैसा कि विकी मुंडा के मामले में है- तो अपार नंबर नहीं बनाया जा सकता. वैसे में कुछ शिक्षक माता-पिता से कहते हैं कि वे बच्चे का नाम आधार में बदलवाएं, ताकि वह यूडीआइएसइ से मेल खा सके. पर आजकल बच्चों के आधार कार्ड में सुधार कराना मुश्किल हो गया है. इसके लिए दस्तावेजों की जरूरत होती है, जो अक्सर उनके पास नहीं होते. उसमें समय और पैसे भी लगते हैं. दूसरा विकल्प यह है कि शिक्षक एक फॉर्म भरकर जिला कार्यालय भेज दें और सुधार का अनुरोध करें. पर इसमें भी समय और ध्यान लगता है. शिक्षक अन्य जरूरी कामों में व्यस्त होते हैं. और यदि फॉर्म जिला को भेज भी दें, तो सुधार होने में लंबा समय लग सकता है, यदि हो पाये तो. इन तकनीकी समस्याओं के कारण झारखंड में लाखों बच्चों के अपार नंबर नहीं बन पा रहे. करीब एक साल से शिक्षकों पर अपने छात्रों के लिए सौ फीसदी अपार नंबर जेनरेशन का लक्ष्य पूरा करने का बहुत दबाव है. कभी-कभी उनको कहा जाता है कि यदि वे यह लक्ष्य समय पर पूरा नहीं करेंगे, तो उनकी तनख्वाह रोकी जा सकती है. पर अधिकांश शिक्षक इसे पूरा नहीं कर पा रहे. इस प्रक्रिया में उनका समय व्यर्थ हो रहा है, जो उन्हें पढ़ाने से रोकता है. याद रखें, झारखंड के लगभग एक-तिहाई सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एक ही शिक्षक है.

फरवरी और मार्च, 2025 में हमने लातेहार जिले के मनिका ब्लॉक में एक-शिक्षक वाले स्कूलों का सर्वेक्षण किया. मनिका प्रखंड में आधे सरकारी प्राथमिक स्कूलों में एक ही शिक्षक है. इन एक-शिक्षक स्कूलों में औसतन 59 बच्चे नामांकित हैं. कुछ स्कूलों में सौ से भी ज्यादा बच्चे हैं. इन स्कूलों की हालत बहुत बदतर थी. जैसे, 20 फीसदी से कम स्कूलों में कार्यशील शौचालय था. सर्वे के दिन एक-तिहाई बच्चे ही उपस्थित थे. ऐसे में, शिक्षकों की प्रमुख चिंता यह थी कि वे सौ फीसदी अपार जेनरेशन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे थे. उस समय इन स्कूलों में नामांकित बच्चों में से सिर्फ 51 फीसदी बच्चों के पास अपार नंबर था. उन स्कूलों में सात फीसदी बच्चे ऐसे थे, जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं था. एक उदाहरण है रिया- इसके माता-पिता नहीं हैं, वह अपने दादा-दादी के साथ कांकत्वा गांव में रहती है. जन्म प्रमाणपत्र होने के बावजूद उसका आधार नंबर नहीं बन पाया है. कारण यह कि ऑपरेटर कंप्यूटर से बने जन्म प्रमाणपत्र की मांग कर रहे हैं. एक और उदाहरण है पोखरी गांव की प्रिया का. उसकी मां के नाम जन्म प्रमाणपत्र में 'रिंकी देवी' लिखा है, पर आधार कार्ड में 'रिंकू देवी'. ऑपरेटर के मुताबिक, इस अंतर को ठीक किये बिना प्रिया को आधार नंबर नहीं दिया जा सकता. आधार नहीं होने के कारण रिया और प्रिया अपार नंबर से वंचित हो रही हैं.

एक हफ्ता पहले हमने फिर से फोन पर इन शिक्षकों से संपर्क किया. पता चला कि अब भी अपार नंबर बनाने का काम अधूरा है. मनिका के एक-शिक्षक स्कूलों में अपार कवरेज 51 फीसदी से बढ़ कर 73 फीसदी हुआ है, पर अब भी 27 फीसदी बच्चों के पास अपार नंबर नहीं है. इस काम की शुरुआत को करीब एक वर्ष हो चुका है. अपार नंबर के बिना बच्चों को अनेक दिक्कतें होंगी. स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष से ही कक्षा नौ से 12 तक की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अपार नंबर अनिवार्य करना चाहता है. ऐसा हुआ तो यह अन्याय होगा. सवाल यह है कि जब बच्चों के पास पहले से आधार नंबर है, तो उन्हें अपार नंबर क्यों लेने को मजबूर किया जा रहा है? जिन शिक्षकों से हमने बात की, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था. यह स्पष्ट है कि डिजिटल बहिष्कार शिक्षा के लिए एक बड़ी बाधा बन रहा है और वंचित समुदायों के बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं.

**(ये लेखकत्रय के निजी विचार हैं.)**

**देश दुनिया**

## बुनियादी ढांचे पर लगातार हो रहे हमले से जर्मनी की सुरक्षा संकट में

लगभग हर दिन जर्मनी के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं. हाल ही में जब कई यूरोपीय हवाई अड्डों के ऊपर ड्रोन देखे गये, उसी सप्ताह एक साइबर हमले ने सुरक्षा सॉफ्टवेयर को ठप कर दिया. यह सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बर्लिन एयरपोर्ट पर भी इस्तेमाल होता है. इसी बीच जर्मनी की राष्ट्रीय रेल सेवा 'डॉयचे बान' भी फिर से तोड़फोड़ का शिकार हुई. निजी कंपनियों पर भी इस तरह के साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं. जर्मनी में डिजिटल इकोनॉमी संगठन 'बिटकॉम' के अनुसार, अर्थव्यवस्था को इससे लगभग 28,900 करोड़ यूरो का नुकसान हुआ है. रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 68 प्रतिशत मामलों में इसके पीछे अपराधी गिरोह होते हैं. लेकिन सर्वेक्षण में शामिल कंपनियों में से लगभग आधे ने कहा कि उन्हें कम से कम एक हमले का तार रूस से मिला है. लगभग उतनी ही कंपनियों ने वारदातों का चीन से संबंध होने की बात कही. थिंक टैंक 'एजी क्रिटिस' के बुनियादी ढांचा सुरक्षा विशेषज्ञ मानुएल अतुग कहते हैं कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि 'इनके पीछे कोई व्यक्ति हो सकता है. ये महंगे उपकरणों के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, यानी इसके पीछे किसी देश की सरकार का हाथ होने की आशंका बहुत अधिक है.' अतुग का अनुमान है कि इन हमलों का उद्देश्य समाज को अंदर से अस्थिर करना हो सकता है, ताकि लोग संस्थानों और सरकार पर से भरोसा खो दें. सितंबर महीने में जर्मनी की घरेलू खुफिया एजेंसी 'बीएनडी' ने बताया कि सरकारी संस्थानों और महत्वपूर्ण ढांचों पर लगभग हर दिन साइबर हमले हो रहे हैं. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरीष मैर्त्स ने भी माना कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद ही कभी देश की सुरक्षा इतनी गंभीर स्थिति में पहुंची हो. उधर जर्मनी की जनता भी अब बढ़ते खतरे को महसूस कर रही है. इसका कारण है कि डिजिटल ढांचे के मामले में जर्मनी आज भी काफी पीछे है.

**-एलिजाबेथ शूमाखर**

**पुण्यतिथि विशेष**

# संपूर्ण क्रांति के स्वप्नदर्शी थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण

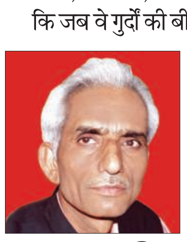

**कृष्ण प्रताप सिंह**
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लंबी जीवन यात्रा में लोक के लिए प्रेरक प्रसंगों की कोई कमी नहीं है. परंतु हमारी आज की युवा पीढ़ी के कम ही सदस्य जानते होंगे कि उनके सार्वजनिक जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग उनके निधन से दो सौ दिन पहले, 23 मार्च, 1979 को घटित हुआ था. उस दिन हुआ यह कि जब वे गुर्दों की बीमारी से पीड़ित होकर मुंबई के जसलोक अस्पताल में मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, आकाशवाणी ने अचानक खबर दी कि उनका निधन हो गया है. खबर की पुष्टि के बगैर तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष केएस हेगड़े ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के हवाले से लोकसभा को भी उनके निधन की सूचना दे डाली और श्रद्धांजलियों व सामूहिक मौन के बाद सदन को स्थगित कर दिया. खबर सुनकर लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए जसलोक अस्पताल पहुंचने लगे, तो जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर अस्पताल में ही थे. उन्होंने बाहर आकर लोगों से क्षमायाचना की और बताया कि लोकनायक अभी हमारे बीच हैं.

बहरहाल, जीते जी मिली संसद की इस 'श्रद्धांजलि' के बाद जेपी दो सौ दिनों तक हमारे बीच रहे और आठ अक्तूबर, 1979 को इस संसार को अलविदा कहा. वर्ष 1998 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया. इससे पहले 1974 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनमानियों के खिलाफ छात्र असंतोष के रास्ते शुरू हुए व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किया. इसी दौरान पांच जून, 1975 को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया. यह आंदोलन चल ही रहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली लोकसभा सीट से प्रतिद्वंद्वी रहे राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए श्रीमती गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया. इसके मद्देनजर 25 जून, 1975 को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में नागरिकों और सरकारी अमलों/बलों से उनके असंवैधानिक आदेशों की अवज्ञा की अपील कर दी, तो इंदिरा गांधी ने न केवल देश पर इमरजेंसी थोप दी, बल्कि जेपी समेत लगभग सारे विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया. उस उन्नीस महीने लंबे अंधेरे में जेपी ने इकलौते रोशनदान की भूमिका निभायी और 1977 में इंदिरा गांधी द्वारा कराये गये आम चुनाव में व्यापक विपक्षी एकता के सूत्रधार बने. फलस्वरूप वे करारी हार हारीं. गैर-कांग्रेसवाद का सिद्धांत भले ही डॉ राममनोहर लोहिया ने दिया था, उसकी बिना पर कांग्रेस की केंद्र की सत्ता से पहली बेदखली 1977 में जेपी के तत्वावधान में ही संभव हुई, जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली.

**जयप्रकाश नारायण**
(11 अक्तूबर, 1902–08 अक्तूबर, 1979)

जेपी के शुरुआती जीवन पर जायें, तो स्वदेश में आरंभिक शिक्षा के बाद 1922 से 1929 तक उन्होंने अमेरिका में रहकर समाजशास्त्र में एमए किया और कैलिफोर्निया व विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालयों की महंगी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए खेतों, कंपनियों व रेस्टोरेंटों आदि में छोटे-मोटे काम किये. इस तरह एक साथ पढ़ाई व कमाई का साथ निभाते हुए वे कार्ल मार्क्स के समाजवाद से खासे प्रभावित हुए, जिसने उनकी आगे की वैचारिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. हालांकि उनके समाजवादी मानस के निर्माण का बड़ा श्रेय बिहार विद्यापीठ को दिया जाता है. मां की बीमारी के चलते पीएचडी करने का अपना इरादा अधूरा छोड़ जेपी अमेरिका से लौटे, तो स्वतंत्रता संग्राम को जैसे उनका ही इंतजार था. वर्ष 1932 में इस संग्राम के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत ज्यादातर नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तो जेपी ने देश के कई हिस्सों में उसके नेतृत्व का जिम्मा संभाला. लेकिन सितंबर, 1932 में मद्रास में उन्हें भी गिरफ्तार कर नासिक जेल में डाल दिया गया. इसी जेल में अनेक समाजवादी नेताओं से विचार-विमर्श कर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की भूमिका तैयार की, जिसने 1934 के चुनावों में भाग लेने के कांग्रेस के फैसले का कड़ा विरोध किया. वर्ष 1939 में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जीत के अंग्रेजों के प्रयत्नों में बाधा डालने के लिए सरकार को किराया व राजस्व का भुगतान रोकने का अभियान चलाया. इस पर उन्हें नौ महीने की कैद की सजा सुनाई गयी. वर्ष 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन में उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में निरुद्ध किया गया, तो एक योजना के तहत वहां से फरार होकर 'आजाद दस्तों' के गठन व प्रशिक्षण के लिए वे नेपाल चले गये. सितंबर, 1943 में, पंजाब में एक रेल यात्रा के दौरान पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और अप्रैल, 1946 में उन्हें तब छोड़ा, जब गांधी जी ने साफ कह दिया कि उनकी रिहाई के बिना अंग्रेजों से कोई समझौता असंभव है.

जेपी ने स्वतंत्रता के बाद राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करने के प्रयत्नों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्नीस अप्रैल, 1954 को बिहार के गया में उन्होंने अपना जीवन सर्वोदय व भूदान आंदोलनों के लिए समर्पित कर दिया और चंबल के डकैतों के आत्मसमर्पण व पुनर्वास में भी अप्रतिम योगदान दिया.

**आपके पत्र**

### झारखंड सरकार का अच्छा प्रयास

झारखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया है, वह प्रशंसनीय है. इसके तहत पांचवीं और आठवीं कक्षा को चेक प्वाइंट बनाया गया है. अर्थात, अब इन कक्षाओं के बच्चों की विशेष परीक्षा ली जायेगी और उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक निर्धारित हैं, उतना प्राप्त करने पर ही विद्यार्थी को अगली कक्षा में भेजा जायेगा. नयी व्यवस्था के तहत होने वाले परिवर्तन बच्चों की शिक्षा के आधार को मजबूत करेंगे, जिसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी.

**देवेश कुमार देव**, गिरिडीह

### बेमौसम बारिश से बिहार में तबाही

मौसम का बदलाव हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गया है. दुर्गा पूजा के दौरान तेज आंधी-तूफान और बारिश ने त्योहार का आनंद फीका कर दिया. प्रकृति का कहर यहीं नहीं थमा, दुर्गा पूजा के बाद भी बिहार में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अनेक जिलों को जलमग्न कर दिया. लोगों के घरों व दुकानों में भी पानी घुस गया. इस समय शासन-प्रशासन और अस्पतालों को पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है. क्योंकि बारिश-बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है.

**अन्विका शेखर**, छपरा

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

# राजनीतिक दल भी चुनाव आयोग की तरह करें पहल

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कई नई शुरुआत भी की हैं। चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की दिशा में इन प्रयासों को सराहनीय कहा जा सकता है। मतदाताओं से लेकर चुनाव प्रक्रिया में जुड़ी मशीनरी का भी काम इन नई पहलों से आसान होगा, यह उम्मीद की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकाधिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयास किए गए हैं, जिनसे मतदाता अपने घरों से निकलकर वोट देने पहुंचे। बहुमंजिला इमारतों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाने और एक मतदान केंद्र पर 1200 मतदाताओं की सीमा तय करना भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है ताकि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगने की हर चुनावों में सामने आने वाली समस्या भी एक हद तक दूर की जा सके। चुनाव आयोग इन सत्रह सुधार उपायों को भविष्य में देशभर में लागू करने के संकेत दे चुका है।

पिछले सालों में चुनाव आयोग ने अशक्त व बुजुर्ग मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान कराने की जो व्यवस्था की थी उसके भी नतीजे मतदान बढ़ाने की दिशा में बेहतर रहे थे। मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने व वोट देने के बाद उन्हें वापस करने की व्यवस्था भी उन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाएगी, जो महज इस डर से मतदान करने नहीं पहुंचते कि उन्हें मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ईवीएम बैलेट पर अब तक उम्मीदवारों की फोटो श्वेत-श्याम होती थी और उम्मीदवारों का नाम क्रम भी छोटे आकार में होता था। मतदाताओं के लिए उम्मीदवारों के चेहरे व नाम संख्या की पहचान आसान हो यह भी जरूरी समझा गया है। इसी मकसद से कि मतदाता आसानी से अपने पसंदीदा उम्मीदवार पहचान कर उसे वोट दे सकें, अब ईवीएम बैलेट पर उम्मीदवार का रंगीन फोटो व क्रम संख्या का बड़ा आकार भी रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि आयोग की ओर से किए गए सत्रह नए बदलावों से बिहार में चुनाव सुगम तरीके से होंगे। आयोग ने नई पहल की है तो राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उम्मीदवारों के चयन को लेकर है। सब जानते हैं कि जातिवाद और भाई-भतीजावाद एवं राजनीति के अपराधीकरण का विरोध करने वाले राजनीतिक दल जब उम्मीदवारों के चयन की बारी आती है तो इन्हीं बुराइयों के जाल में फंस जाते हैं। मतदाताओं के पास नोटा यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प ऐसे उम्मीदवारों को नकारने का हथियार जरूर देता है लेकिन यह अधिकार भी नखदंतविहीन साबित हो रहा है।

आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव सभाओं और बयानबाजी का दौर भी रहने वाला है। ये दल भी राजनीति में शुचिता बनाए रखने की दिशा में संकल्पित हों तो बिहार के चुनाव आने वाले दूसरे चुनावों के लिए आदर्श पेश करने वाले हो सकते हैं। जरूरत सिर्फ पहल करने की है।

**498ए का दुरुपयोग:** गलत आरोप के विनाशकारी प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर असर डालते हैं

# कानूनी सुरक्षा या प्रतिशोध का खतरनाक हथियार?

डॉ. ऋतु सारस्वत
समाजशास्त्री
@patrika.com

**498ए का अदालत पहुंचा हर मामला गलत हो ऐसा नहीं है पर हर आरोप सच्चा हो ऐसा भी संभव नहीं है। सच के सामने आए बिना किसी को अपराधी मान लेना उस वैधानिक व्यवस्था का अपमान है जो यह मानती है कि कानून के समक्ष स्त्री और पुरुष समान हैं।**

देश की शीर्ष अदालत ने 'शोभित कुमार मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश' के मामले में वैवाहिक विवाद की सुनवाई करते हुए आइपीसी की धारा 498ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 84) के दुरुपयोग पर एक बार पुनः चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजकल, सास यानी बेटे की मां और पति झूठी शिकायतों के कारण पत्नी से बहुत सावधान रहते हैं। हमने कई शिकायतें खारिज कर दी हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर मामला झूठा है, लेकिन धारा 498ए बहुत कठोर है और इसका दुरुपयोग किया जाता है। यह मामला एक महिला की ओर से शादी के डेढ़ महीने के भीतर धारा 498ए के तहत दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा था। न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और न्यायाधीश आर. महादेवन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वैवाहिक विवादों में परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति के प्रति चेतावनी देते हुए कहा कि विशिष्ट विवरणों का उल्लेख किए बिना केवल उत्पीड़न के सामान्य आरोप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

इसी अवधि में 'पूजा रासने बनाम दिल्ली राज्य और अन्य' के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि आइपीसी की धारा 498ए महिलाओं को वैवाहिक क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए महत्त्वपूर्ण है, लेकिन पति के रिश्तेदारों के खिलाफ व्यापक और निराधार आरोपों के माध्यम से इसके दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। केवल तभी जब आरोप कानूनी जांच में खरे उतरें और प्रथम दृष्ट्या सही साबित हों, तभी मुकदमे की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए...ऐसा दृष्टिकोण निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक मुकदमेबाजी और वैवाहिक झगड़े में होने वाली कठिनाइयों, उत्पीड़न और अपमान से बचाता है। बीते वर्षों में अनेकानेक बार सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के दुरुपयोग पर अक्सर चिंता जताई है। मई 2024 में, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने संसद से अनुरोध किया कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 और 86 के लागू होने से पहले उनमें बदलाव करने पर विचार करे। पीठ ने कहा कि ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और उसकी व्याख्या का ही प्रतिरूप हैं।

उल्लेखनीय है कि 2010 में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश दलवीर भंडारी और न्यायाधीश केएस राधाकृष्णन की पीठ ने सरकार से साफ तौर पर कहा था कि वह दहेज विरोधी कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए पर पुनर्विचार करे। धारा 498ए के तहत मिथ्या शिकायतों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए पीठ ने कहा था कि हमारे सामने बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आती हैं, जो प्रामाणिक भी नहीं होतीं और परोक्ष उद्देश्यों से दर्ज की जाती हैं। अब समय आ गया है कि विधायिका इस पर विचार करे और जनमत को ध्यान में रखते हुए कानून में उपयुक्त बदलाव करे। न्यायालय ने इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए फैसले की एक प्रति केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी थी। न्यायालय के इस निर्देश को एक वैचारिक बदलाव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा था। एक ऐसे सांस्कृतिक बदलाव के रूप में जहां केवल महिलाओं को पीड़ित के रूप में देखा जाता है, जो कि झूठे आरोप लगाने में असमर्थ मानी जाती है।

महिलाओं को चुपचाप सहने वाली और कुछ भी गलत नहीं करने वाली धारणा ने न्याय प्रशासन को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से प्रभावित किया है। परंतु शीर्ष अदालत के आदेश के 15 साल बीत जाने के बावजूद भी 498ए के प्रावधानों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। दुर्भाग्य यह है कि बीते दशकों में तथाकथित छद्म नारीवाद का प्रवाह इस विचारधारा को प्रबल बनाने में समर्थ रहा है कि पुरुष संवेदनहीन, लालची, निर्दयी एवं क्रूर होते हैं। महिलाओं के आरोप को 'अंतिम सत्य' मानने की मानसिकता पुरुषों को निर्दोष मानने को तैयार ही नहीं है। न्यायालय के फैसले आने से पूर्व ही उन्हें और उनके परिवार को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इन झूठे आरोपों की असली समस्या यह है कि न्यायालय में चाहे कुछ भी हो यह आरोप टिके रहते हैं। एक आरोप, खासकर इस त्वरित दुनिया में, इंटरनेट के जरिए समाज में अपनी जगह बना लेता है। अगर कोई व्यक्ति दोषमुक्त भी हो जाता है, तो भी दाग बना रहता है। किसी अपराध का गलत आरोप लगना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक हो सकता है। गलत आरोप के विनाशकारी प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं, व्यक्तिगत संबंधों, पेशेवर अवसरों और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। कई बार तो यह उस अवसाद तक पहुंच जाते हैं कि जीवन पर्यन्त व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता।

निश्चित रूप से 498ए का अदालत पहुंचा हर मामला गलत हो ऐसा नहीं है परंतु हर आरोप सच्चा हो ऐसा भी संभव नहीं है। सत्य के सामने आए बगैर आंखें मूंदकर किसी को अपराधी मान लेना अमानवीयता ही नहीं, अपितु उस वैधानिक व्यवस्था का भी अपमान है जो यह मानती है कि कानून के समक्ष स्त्री और पुरुष समान हैं। बिना किसी सबूत, बिना किसी मुकदमे, बिना किसी तथ्य के एक ही आरोप किसी पुरुष के कॅरियर, उसकी मानसिक स्थिति और उसके पूरे जीवन को तबाह करने के लिए काफी है। जब वह निर्दोष साबित भी हो जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नुकसान स्थायी होता है और वह महिला जिसने झूठ बोला? उसका कुछ नहीं होता। न जेल, न जुर्माना, और जाहिर है, कोई जवाबदेही नहीं। अगर पुरुष विरोधी इस सोच के मकड़जाल को जल्दी ही परिवर्तित नहीं किया गया तो वह समय दूर नहीं की विवाह संस्था मिथ्या आरोपों के भय से दरक जाएगी।

## प्रसंगवश

# ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर सही मायने में बने जनसेवा का माध्यम

### शिविरों में जनता को राहत देने के बजाय जिम्मेदारों की लापरवाही

राजस्थान में इन दिनों सभी जिलों में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आम जनता तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान करने के लिए ऐसे अभियानों को सरकारें अपने कामकाज का हिस्सा बनाती रही हैं। लेकिन समस्याओं के समाधान की जगह शिविर महज औपचारिकता निभाने के लिए ही लगाए जाने लगें तो सरकारी मंशा पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई जगहों से ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं कि शिविर में संबंधित महकमों में कई के अधिकारी-कर्मचारी पहुंचते ही नहीं। कोटा जिले में तो एक शिविर का अवलोकन करने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद ऐसी स्थिति से दो-चार हुए जब निर्धारित समय के एक घंटे बाद भी सारी कुर्सियां खाली पड़ी दिखीं। मंत्री ने शिविर में बैठकर ही अधिकारियों को फोन लगाना शुरू किया तो अधिकारी-कर्मचारी दौड़ते-हांफते पहुंचे। यह तो कोरी बानगी है। मंत्रियों ने कई शिविरों में पहुंचकर अफसरों को लताड़ लगाई है। यह कोई पहली बार नहीं है जब प्रदेश में ऐसे शिविरों का आयोजन किया गया हो। बरसों से यह परंपरा चली आ रही है कि कुछ दिनों के लिए विशेष शिविर लगाकर जनता के काम किए जाते हैं। घर-द्वार पर जनता की समस्याओं का समाधान हो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या सचमुच सरकारी दफ्तरों में लालफीताशाही हावी है। क्या दफ्तरों में सचमुच लोगों के काम अटकाने के प्रयास होते हैं? आठ-दस बरस राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त कराने के लिए सरकारी महकमों के चक्कर काटने वाले का काम शिविर में एक चुटकी में ही हो रहा है तो यह भी सवाल उठता है कि लंबे समय तक बिना वजह टरकाने वालों पर क्या कार्रवाई हुई? शिविरों में काम कर अधिकारी और विभाग अक्सर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि उन्होंने कोई असाधारण सेवा दी हो, लेकिन यही काम नियमित दिनों में क्यों टाल दिया जाता है। राहत देने के नाम पर लगाए जाने वाले शिविर महज सरकारी प्रचार का माध्यम नहीं बनने चाहिए।

- जयप्रकाश सिंह
jaiprakash.singh@in.patrika.com

## बुक इनसाइट

# फैंटम ऑर्बिट: ए थ्रिलर

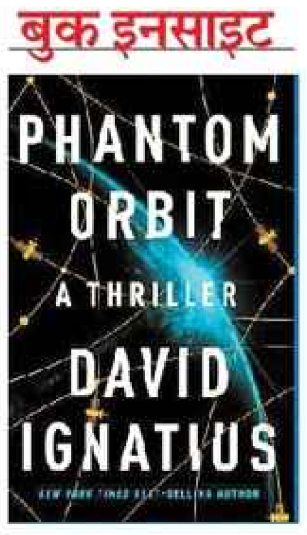


डेविड इग्नेशियस की नई किताब 'फैंटम ऑर्बिट: ए थ्रिलर' एक ऐसी रोमांचक कहानी है, जो पाठकों को अंतरिक्ष और जासूसी की दुनिया में ले जाती है। इग्नेशियस ने अपनी इस किताब में अंतरिक्ष उपग्रहों और गुप्त मिशनों के इर्द-गिर्द एक तनावपूर्ण कथा बुनी है। कहानी की पृष्ठभूमि स्पेस वॉरफेयर (अंतरिक्ष युद्ध) और सैटेलाइट इंटेलिजेंस की दुनिया में गढ़ी गई है। एक रहस्यमय सैटेलाइट, जो अचानक अपने ऑर्बिट से गायब हो जाता है। इससे पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति हिल जाती है। अमरीका और चीन के बीच तकनीकी जंग, खुफिया एजेंसियों की चाल और एक वैज्ञानिक की नैतिक दुविधा यही इस उपन्यास की मुख्य धारा है। लेखक ने इस कहानी को न सिर्फ तकनीकी तथ्यों की गहराई से लिखा है बल्कि इंसानी भावनाओं से भी जोड़ दिया है।

वैज्ञानिकों, जासूसों और सैनिकों के बीच के रिश्ते किताब को मानवीय बनाते हैं। संवाद सटीक हैं, गति तेज है और घटनाएं इतनी वास्तविक लगती हैं कि पाठक को लगता है वह किसी लाइव मिशन का हिस्सा है। कहानी की रफ्तार बेहद तेज है।

## फैक्ट फ्रंट

# गिंको बिलोबा: एक जीवित जीवाष्म

गिंको बिलोबा, एक ऐसा वृक्ष है जिसे दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पेड़ करीब 27 करोड़ वर्ष पुराना है यानी यह डायनासोर के युग से मौजूद है। इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। यह चीन और जापान में पाया जाता है। इसकी पत्तियां पंखे के आकार की होती हैं, जो हर मौसम में रंग बदलती हैं। वसंत में हल्की हरी, गर्मियों में गहरी हरी और शरद ऋतु में पूरी सुनहरी हो जाती हैं। यह पेड़ न केवल सुंदर है, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर भी है। इसकी पत्तियों में ऐसे तत्त्व पाए जाते हैं, जो स्मरणशक्ति बढ़ाने, रक्त संचार सुधारने और तनाव कम करने में मदद करते हैं। आज कई देशों में इससे औषधियां तैयार की जाती हैं। आधुनिक चिकित्सा में इसे एंटी-एजिंग और न्यूरोप्रोटेक्टिव दवाओं में उपयोग किया जाता है। गिंको बिलोबा की एक अद्भुत बात है कि यह पेड़ प्रदूषण, धूल और विकिरण को भी झेल सकता है। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने के बाद भी कई गिंको पेड़ जीवित रहे और फिर से हरे हो गए यह इसकी जीवनशक्ति का प्रमाण है।

## हेल्थ | विश्व दृष्टि दिवस 9 अक्टूबर को

# नेत्र रोगों के प्रति सतर्कता और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत

डॉ. सुरेश पाण्डेय
वरिष्ठ चिकित्सक
@patrika.com

नेत्र मानव शरीर का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग हैं। जन्म के बाद 80 प्रतिशत ज्ञान, जो हम प्राप्त करते हैं वह हमारी आंखों (दृष्टि) से होता है। चाणक्य द्वारा लिखित नीति सत्कर्म के अंत में कहा गया है- 'सर्वेन्द्रियं नयनं प्रधानम्' जिसका शाब्दिक अर्थ है, सभी इंद्रियों में, दृष्टि की भावना सर्वोच्च है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 9 अक्टूबर 2025 को मनाए जाने वाले वर्ल्ड साइट-डे की थीम है 'लव योर आइज।' विश्वभर में 4 करोड़ व्यक्ति दृष्टिविहीन/दृष्टि बाधित हैं, जिसमें तीन चौथाई दृष्टि विहिन/दृष्टि बाधित व्यक्ति एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्वभर में हर पांच सेकंड में एक व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाता है। भारत में नेत्र रोगों के प्रति आज भी सजगता एवं सतर्कता नहीं है और यही कारण है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में अंधता के क्षेत्र में भारत का स्थान तीसरे पायदान पर है। भारत में लगभग 2 लाख बच्चे अंधत्व से पीड़ित हैं एवं प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार नए ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो कि जन्म से देख नहीं सकते हैं। विश्व दृष्टि दिवस का उद्देश्य है आंखों के रोगों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना एवं सशक्त प्रयासों के माध्यम से दृष्टिहीनता को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए विश्वभर से उपचार योग्य अंधता का उन्मूलन करना है। नेत्र बीमारियों के समय पर उपचार के माध्यम से एवं समाज में जागरूकता बढ़ाकर से विश्वभर में होने वाली 80 प्रतिशत अंधता को रोका जा सकता है।

भारत में अंधता/दृष्टि विहीनता के पांच प्रमुख कारण - मोतियाबिंद (कैटरेक्ट), कालापानी (ग्लूकोमा), रेटिना (पर्दे की बीमारियां), दृष्टि दोष (रिफ्रेक्टिव एरर), कॉर्निया(पारदर्शी पुतली) की बीमारियां हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 38 लाख व्यक्ति मोतियाबिंद होने के कारण दृष्टि बाधित हो जाते हैं। हमारे देश में कुल अंधता का लगभग 1 प्रतिशत आंखों की पारदर्शी पुतली के सफेद हो जाने (कॉर्नियल ब्लाइंडनेस) के कारण है। आइए विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर सामूहिक प्रयासों से उपचार योग्य अंधता के उन्मूलन का संकल्प लें।

वर्ल्ड साइट-डे की थीम 'लव योर आइज' के अनुसार आइए हम बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास सप्ताह में एक दिन करने के लिए प्रेरित करें। सप्ताह में एक दिन कुछ घंटे प्रकृति के सानिध्य में बिताएं। अपनी आंखों से प्रेम करें एवं सभी मिलकर विश्वभर से उपचार योग्य अंधता के उन्मूलन के लिए साझा प्रयास करें। विश्वभर से उपचार योग्य अंधता के उन्मूलन के लिए हम सभी को मिलकर जनसामान्य को नेत्रों की सुरक्षा के प्रति सचेत करना होगा एवं नेत्र रोगों के निदान और उपचार के लिए सुविधाएं देश के छोटे गांवों में भी उपलब्ध करवानी होंगी।

## सुपरमून: न्यूयॉर्क स्काईलाइन में सुनहरी चमक

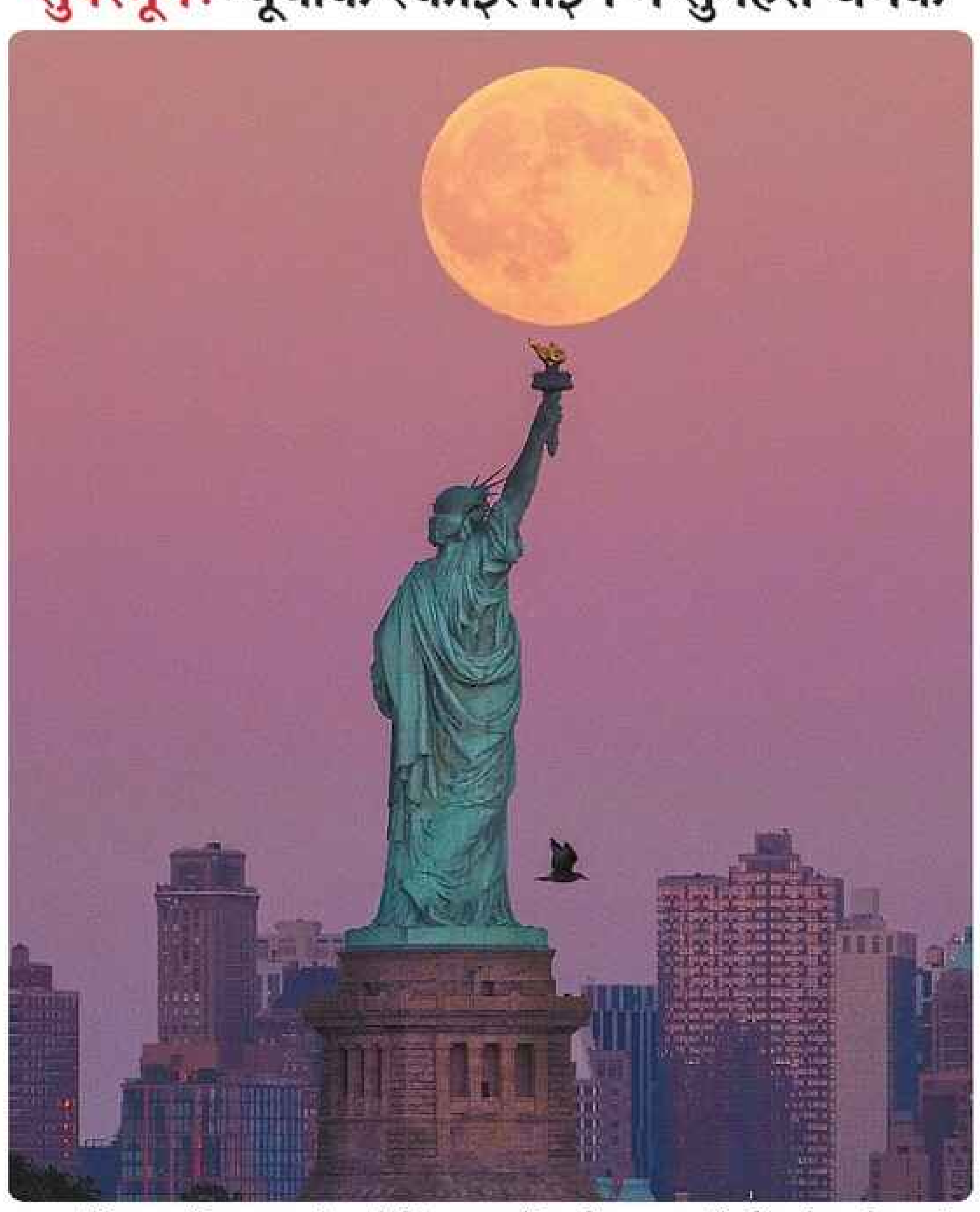

*शरद पूर्णिमा पर हार्वेस्ट सुपरमून ने न्यूयॉर्क के आकाश में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। यह चंद्रमा न्यू जर्सी के जर्सी सिटी से देखा गया, जहां यह स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे उठते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी सुपरमून को उठाए हुए हो। फोटोग्राफर एडम ग्रे ने इसे कैप्चर किया है।*

## विचार | बच्चों को 'स्व' की कोटर में बंद न करें

# दूसरों के दर्द को समझना ही मानवता की पहचान है

डॉ. गौरव बिस्सा
मैनेजमेंट ट्रेनर
@patrika.com

आज समाज में जिस तरह की हृदयविदारक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वह मन को विचलित करती हैं। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हम मानवता के मूल्यों को कहीं भूलते तो नहीं जा रहे। मनुष्य के हृदय में भावनाएं होना अत्यावश्यक है। भावनाएं मनुष्य के जीवित होने का प्रमाण है। जिस व्यक्ति का समूचा जीवन ही भावों से रिक्त हो तो जीवन बेकार है। भावप्रवण व्यक्ति सुख में खुश होना और दुःख में दुखी होना जानता है। उसकी जिन्दगी किसी प्रोफेशनल जैसी नहीं होती, जो अपनी हरेक क्रिया में लाभ-हानि की गणना करता हो।

भावनाओं से परे रहने वाला व्यक्ति कुटिल, जटिल, आपराधिक और हर बात में लाभ हानि तलाशने वाला होगा। जो शिक्षा मनुष्य में संवेदना, मानवीयता और राष्ट्रप्रेम न जगा सके वह सिर्फ साक्षरता दे रही है। साक्षरा का उल्टा शब्द है राक्षसा। पढ़े-लिखे मनुष्य रूपी राक्षसों को शिक्षित मानने की भूल नहीं करनी चाहिए।

समाज में उच्च डिग्रीधारियों ने ऊपर लिखे अपराधों जैसे कृत्य किये हैं। इससे ये स्पष्ट है कि शिक्षा में मानवीय गुणों का, नैतिकता का समावेश अत्यावश्यक है। मानवीयता, सहृदयता, प्रेमपूर्ण व्यवहार, समान अनुभूति और सकारात्मक कम्युनिकेशन से हम स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं तथा मशीन मानव के स्थान पर मनुष्य बन सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से दस लोगों पर हुए शोध से यह बात सामने आई कि मनुष्य की सफलता में उसके ज्ञान, कौशल, डिग्री, कला और कार्य अनुभव का महत्त्व सिर्फ पंद्रह प्रतिशत के लगभग है। बाकी 85 प्रतिशत सफलता का कारण, लोगों के साथ व्यक्ति के अंतरवैयक्तिक सम्बन्ध हैं अर्थात यदि मानवीय मूल्य और नैतिकता है तो सफलता तय है।

सॉफ्ट स्किल्स जैसे प्रेम, दया, करुणा, वार्ता शैली आदि को पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए और उनके अंक भी परिणाम में जुड़ने चाहिए। ऐसा न हुआ तो शिक्षा जगत मनुष्य रूपी रोबोट्स ही बनाती रहेगी। अभिभावक अपनी सन्तान को 'अदर्स सेंट्रिक एप्रोच' अर्थात दूसरों के लिए जीवन जीना नहीं सिखाते। इस कारण बच्चे स्व केन्द्रित हो जाते हैं और उत्तम संस्कार ग्रहण नहीं कर पाते। दरअसल लालन-पालन के दौरान अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों से यह प्रश्न तो पूछते ही नहीं हैं कि वे अन्यों के लिए या समाज के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं?

बच्चों को स्व की कोटर में बंद करके 'आइ, मी एंड मायसेल्फ' की शिक्षा देना ही कष्ट का कारण बनती है। जब बच्चे को शुरू से ही सत्ता, धन, दूसरों पर शासन आदि के सूत्र सिखाए गए हों तो वे समाज कल्याण की राह कैसे पकड़ेंगे? यह सीखना होगा कि हमारे कारण दूसरों के जीवन में प्रसन्नता आए, तभी हम स्वयं को मनुष्य कह सकते हैं।

## आपकी बात

### निजी जानकारी साझा न करें

**साइबर** अपराधों में कमी के लिए अपनी निजी जानकारी कभी सोशल मीडिया पर साझा न करें। अपने फोन या मोबाइल पर किसी भी लॉटरी या लालच वाले मैसेज या लिंक्स पर क्लिक न करें। फर्जी कॉल्स व मैसेज पर ध्यान न दें। उन्हें ब्लॉक करें। **- निर्मला वशिष्ठ,** अलवर

**patrika.com** पर पढ़ें

### पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

**पत्रिकायन** का सवाल था, 'साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें। https://shorturl.at/z4YuJ

### आज का सवाल

**बच्चों में स्वच्छता की आदतें किस प्रकार डाली जा सकती हैं?**

ईमेल करें: edit@epatrika.com

## टेक्नोलॉजी | विदेशी तकनीक पर आश्रित होना छोड़कर हमारे देश को चाहिए अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता

# स्वदेशी एआइ: भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की कुंजी

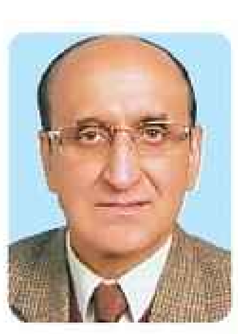

के.एस.तोमर
वरिष्ठ पत्रकार
एवं स्तंभकार
@patrika.com

कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआइ) इक्कीसवीं सदी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीक बन चुकी है, जिसने उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की गति को अभूतपूर्व ढंग से बदल दिया है। भारत के लिए सवाल यह नहीं है कि एआइ को अपनाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमें अपनी 'स्वदेशी एआइ' क्षमताएं विकसित करनी होंगी।

यदि भारत आत्मनिर्भर एआइ का निर्माण नहीं करता, तो जोखिम है कि हमारा विशाल डेटा विदेशी कंपनियों के पास जाएगा और वे ही उससे लाभ कमाएंगी, जबकि भारत केवल उपभोक्ता बनकर रह जाएगा। भारत के लिए तीन प्रमुख कारण इस दिशा में निर्णायक हैं। पहला, आर्थिक स्वतंत्रता और नवाचार। यदि भारत अपनी घरेलू एआइ पारिस्थितिकी विकसित करता है तो इससे स्टार्टअप्स को बल मिलेगा, निजी निवेश आएगा और विदेशी निगमों पर निर्भरता घटेगी। दूसरा, सांस्कृतिक और भाषाई समावेशन। भारत की विविधता इतनी गहरी है कि एक वैश्विक एआइ टूल उसकी भाषाई और सांस्कृतिक बारीकियों को नहीं समझ सकता। किसान, छात्र या लघु उद्यमी- सभी की जरूरतें अलग हैं।

स्वदेशी एआइ हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी से लेकर दर्जनों भाषाओं में सेवाएं देकर डिजिटल लोकतंत्रीकरण कर सकती है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा। विदेशी एआइ मॉडल में छिपे हुए जोखिम हो सकते हैं। अगर रक्षा, शासन और महत्त्वपूर्ण ढांचे विदेशी तकनीक पर आधारित होंगे तो यह पारदर्शिता और संप्रभुता के लिए खतरा बनेगा। यदि भारत निर्णायक कदम नहीं उठाता तो इसके गंभीर परिणाम होंगे- डिजिटल निर्भरता बढ़ेगी। विदेशी मॉडल भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित होंगे और भारत को उन्हीं के उपयोग के लिए भुगतान करना होगा। आर्थिक असमानता आएगी। भारी वित्तीय शक्ति वाली वैश्विक कंपनियां भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगी। डेटा सुरक्षा जोखिम बढ़ेगा। संवेदनशील नागरिक डेटा विदेश जाकर दुरुपयोग का शिकार हो सकता है। तकनीकी पिछड़ापन आएगा। जबकि एनविडिया- ओपनएआइ 10 गीगावॉट जीपीयू क्षमता तक पहुंच रहे हैं, भारत के पास अभी केवल लगभग 30,000 जीपीयू हैं।

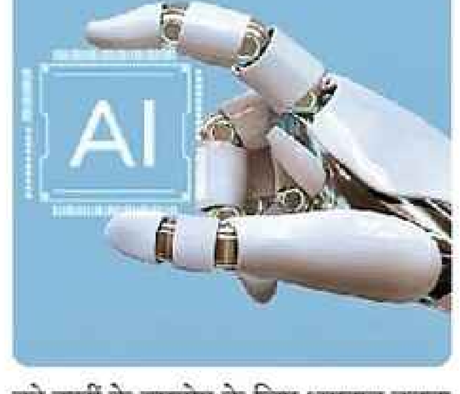


स्वदेशी एआइ का असर हर वर्ग पर होगा। शिक्षा में, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री से ग्रामीण-शहरी खाई कम होगी। कृषि और व्यापार में, मौसम, मूल्य प्रवृत्ति और ऋण सुविधा की जानकारी किसानों व छोटे उद्यमियों तक पहुंचेगी। शासन में, नागरिक सरल चैटबॉट से योजनाओं, पेंशन या सब्सिडी की जानकारी अपनी मातृभाषा में पा सकेंगे। रोजगार में, कुछ काम भले समाप्त हों, लेकिन एआइ विकास, डेटा एनोटेशन और नई सेवाओं में अवसर भी पैदा होंगे। भारत को तीन मोर्चों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, जिसमें पहला है डेटा और मानक। सभी एआइ मॉडल को भारत में होस्ट किया जाए और डेटा स्थानीय ही रहे। दूसरा है कम्प्यूटिंग शक्ति, घरेलू जीपीयू क्षमता बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी आवश्यक है। तीसरा है प्रतिभा विकास। विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स को इंजीनियर, नैतिक विशेषज्ञ और नीति निर्माता तैयार करने होंगे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोई सामान्य तकनीकी लहर नहीं है, बल्कि भविष्य का परिभाषित मंच है। भारत के पास प्रतिभा, विशाल बाजार और डिजिटल ढांचा मौजूद है। लेकिन आत्मनिर्भर एआइ के बिना देश केवल डेटा निर्यातक और सेवाओं का आयातक बनकर रह जाएगा।

स्वदेशी एआइ न केवल नागरिकों को सशक्त बनाएगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करेगी, स्टार्टअप्स को उभारेगी और भारत को वैश्विक तकनीकी मंच पर नेतृत्व प्रदान करेगी।

हर दिन नियमित रुप से दोहराए गए छोटे-छोटे अनुशासन धीरे-धीरे महान उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। -जॉन सी. मैक्सवेल

**जयपुर के अस्पताल में लगी आग से हुई मौतें दुखद और विडंबनापूर्ण हैं। लेकिन सोचने की बात तो अलबत्ता यह भी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अस्पतालों में आग लगने के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं।**

# अस्पताल और आग

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग से हुई मौतों की खबर जितनी दुखद और विडंबनापूर्ण है, उतनी ही सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर देश के अलग-अलग हिस्सों में अस्पतालों में आग लगने के हादसे बार-बार क्यों सामने आ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले लखनऊ के एक अस्पताल में आग लगी थी। गनीमत रही कि उसमें सभी को बचा लिया गया था। पिछले साल झांसी के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 18 नवजातों की मौत हो गई थी। पिछले साल ही दिल्ली के एक अस्पताल में लगी आग से सात बच्चों की मौत हुई थी। खुद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों में 2021, 2022 और 2024 में आग लग चुकी है। ताजा हादसे में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में पानी टपकने और करंट लगने की शिकायतें पहले भी कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इमारतों में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर कुछ प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। इसके बावजूद, उच्च न्यायालय का राज्य में सरकारी इमारतों में अक्सर हो रहे हादसों पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। हालांकि, बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ऐसी लापरवाही कहीं भी हो, निंदनीय है। दरअसल, अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं में आई तेजी और उनमें हुई मौतें स्मरण कराती हैं कि चाहे निजी हों या सरकारी, अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के रख-रखाव को पूरे देश में निहायत ही कम तरजीह दी जाती है। ऐसे ज्यादातर हादसे शॉर्ट सर्किट या ओवर लोडिंग की वजह से ही होते हैं। कई बार वायरिंग पुरानी होने की वजह से भी शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि समय-समय पर वायरिंग की जांच कराई जाती रहे, जो अमूमन अस्पताल नहीं कराते हैं। ऐसे हादसों के बाद स्वाभाविक ही फायर

ऑडिट की जरूरत पर चर्चाएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर अस्पताल इस कसौटी पर भी खरे नहीं उतरते। दूसरी जगहों की तुलना में अस्पतालों में आग इसलिए भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि इनमें ज्यादातर ऐसे मरीज होते हैं, जो बगैर मदद के उठकर भाग भी नहीं सकते। सार्वजनिक जगहों व इमारतों, खासकर अस्पतालों और स्कूलों में सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक तरह से नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ऐसे में, हादसों को रोकने के लिए नीति-नियंताओं को एक दीर्घकालीन योजना के तहत काम करना होगा। ऐसे हादसे सिर्फ एक अस्पताल की विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्थागत चूक की ओर इशारा करते हैं, जिसे अविलंब सुधारने की जरूरत है।

# न्यायाधीश तो संन्यासी होता है

**न्यायाधीश को संन्यासी कहे जाने के पीछे गहरा अर्थ यही है कि उसे उन लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, जिनके अधिकारों और दायित्वों का फैसला वह खुद करता है। न्याय को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह अनुशासन जरूरी है, जो वर्षों की साधना से ही आता है।**

**विनय झैलावत**
*पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता*

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने न्यायाधीशों से संयम बरतने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका के पक्ष में व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि फैसले बोलने चाहिए। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों को अपने फैसलों में लिखी बातों से आगे बढ़कर बोलने के प्रलोभन से बचना चाहिए। उनके अनुसार, 'एक न्यायाधीश की अनिवार्य जरूरत कम बोलना, कम लिखना, सटीक लिखना और यथासंभव संक्षिप्त लिखना और सच्चाई को व्यक्त करना है। यह एक साधना या अभ्यास है, जो हमें करना होगा।'

यह पहली बार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया के उपयोग से बचना चाहिए, और फैसलों पर राय देने से भी बचना चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वरमडे की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि न्यायपालिका दिखावे का मंच नहीं है। उन्होंने कहा, 'न्यायिक अधिकारियों को फेसबुक पर नहीं जाना चाहिए। उन्हें फैसलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल, अगर फैसले का हवाला दिया जाता है, तो न्यायाधीश पहले ही किसी न किसी तरह अपनी बात कह चुके होंगे।' न्यायालय ने कहा, 'यह एक खुला मंच है। न्यायाधीशों को एक संन्यासी की तरह रहना होगा और घोड़े की तरह काम करना होगा।'

उच्च न्यायालयों में अनौपचारिक रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि जब किसी वकील को न्यायाधीश के पद पर आसीन किया जाता है, तो उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने चाहिए। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा इस अनौपचारिक नियम का बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट

इसे अनदेखा करते प्रतीत होते हैं। यह देखा गया है कि युवा न्यायाधीश अपने निजी जीवन की झलक दिखाने और सेलिब्रिटी जैसी हैसियत का आनंद लेने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।

इस संबंध में नियमों की कमी न्यायाधीशों को सोशल मीडिया पर रहने की अनुमति देती है। सन 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण न्यायालय के संदर्भ द्वारा न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन नामक एक दस्तावेज को अपनाया। हालांकि, यह संहिता लागू नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर किसी न्यायाधीश के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायाधीशों की अपेक्षाओं का दृष्टांत बताया है। वास्तव में, विधि आयोग ने अपनी 195वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि संहिता के उल्लंघन को दुर्व्यवहार माना जाए। हालांकि, उक्त सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

संहिता के दो प्रासंगिक सिद्धांत यह हैं कि 'एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक अलगाव का अभ्यास करना चाहिए और प्रत्येक न्यायाधीश को हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जनता की नजरों में है।' सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य मामले में, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा है कि 'न्यायाधीश अपने निर्णयों और आदेशों के माध्यम से बोलते हैं। किसी मामले की सुनवाई करते समय किसी न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियां कभी-कभी न्यायाधीश की अपनी सोच और मान्यताओं की रूपरेखा को उजागर कर सकती हैं। ये टिप्पणियां, खासकर अगर मीडिया द्वारा उठाई जाती हैं, तो कभी-कभी अनजाने में सार्वजनिक आख्यान पैदा कर सकती हैं, जो किसी मामले के वास्तविक कानूनी गुणों को ढक देती हैं।' हाल ही में सीजेआई गवई की अगुवाई वाली पीठ ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है और याचिकाकर्ता से कुछ हस्तक्षेप के लिए 'भगवान विष्णु से प्रार्थना' करने को कहा।

तत्काल समाचारों के युग में, जहां 'ब्रेकिंग न्यूज' अक्सर 'न्यायपीठ द्वारा तय किए गए मुद्दे की वास्तविक समझ से परे होती है।' ऐसी टिप्पणियां कभी-कभी पूरे कानूनी संदर्भ के बिना ही रिपोर्ट की जाती हैं। इसके दुष्प्रभाव दिख ही रहे हैं।

एक अन्य मामले में, जब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया, तो यह टिप्पणी तुरंत सार्वजनिक चर्चा में आ गई। अदालत कक्ष के बाहर भी बहस छिड़ गई, जो तय किए गए मुद्दे से कोसों दूर थी। किसी मामले की सुनवाई करते समय किसी न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियां कभी-कभी उसकी अपनी सोच और मान्यताओं की रूपरेखा को उजागर कर सकती हैं।

यह न्यायिक प्राधिकार पर सवाल उठाने की बात नहीं है, जो अपने क्षेत्राधिकार में निरंकुश रहता है। यह न्यायिक दृष्टिकोण के बारे में है। एक न्यायाधीश के शब्दों का कानूनी महत्व और सार्वजनिक प्रभाव दोनों होता है। यहां तक कि एक आकस्मिक टिप्पणी, या एक क्षणिक टिप्पणी भी, यदि व्यापक रूप से रिपोर्ट की जाए, तो वह फुटनोट के बजाय सुर्खी बन सकती है। यह कभी-कभी फैसला सुनाए जाने से पहले ही जनता की धारणा को प्रभावित कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदर्श न्यायाधीश को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, जो एक संन्यासी की तरह रहता और व्यवहार करता है, जिसकी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। इस 'एकांत जीवन' के पीछे तर्क यह है कि एक न्यायाधीश को उन लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, जिनके अधिकारों और दायित्वों का फैसला वह खुद करता है।

न्यायाधीशों के लिए संयम मौन नहीं है। यह अनुशासन है। यह केवल वही बोलने की कला है, जो न्याय के लिए उपयोगी हो। ऐसी किसी भी बात को रोकना, जो उसे प्रभावित कर सकती हो। ऐसे समय में जब हर शब्द मिनटों में अदालतों से लाखों स्क्रीन तक पहुंच सकता है, यह अनुशासन न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है। दरअसल, न्याय सबसे जोर से तब बोलता है, जब वह सिर्फ वही बोलता है, जो जरूरी है। एक न्यायाधीश जो जानता है कि कब चुप रहना है, उसके लिए चुप रहना नहीं है। वह बुद्धिमान है। और कभी-कभी, शब्दों के बीच का विराम ही असली सच्चाई को उजागर करता है।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा

जेम्स क्लियर

किसी भी खेल को हर कोई जीतने के लक्ष्य के साथ खेलता है। लेकिन ध्यान सिर्फ नतीजे पर रहेगा, तो खेल का मजा कैसे ले सकेंगे। ध्यान खेल पर होगा, तो नतीजा खुद ही बेहतर होता जाएगा।

# परिणाम स्वयं अपनी चिंता कर लेगा

*सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे स्वस्थ शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और अमल में लाने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था, जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए और कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल रहा। धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना-देना था। लगभग हर चीज का लेना-देना उन व्यवस्थाओं से था, जिनका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या फर्क है? यह एक विशिष्टता है।*

*सबसे पहले मैंने इसे डिलबर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं वे प्रक्रियाएं हैं, जो आपको नतीजों की ओर ले जाती हैं। यदि आप कोच हैं, तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है, जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप एक संगीतकार हैं, तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, गुरु से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। एक रोचक प्रश्न है कि यदि आप अपने लक्ष्यों की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था में ध्यान देते हैं, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबाल कोच हैं, और स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूं, मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ 'फिनिश' करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। तीन बार के सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्श के शब्दों में, 'स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा।' यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं। व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या हैं? क्या लक्ष्य बेकार की चीज है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती हैं, जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है, तो समस्या आप नहीं हैं। समस्या आपकी प्रणाली में है।*

## हर दिन प्रयास करें

सूत्र

*यदि आप केवल लक्ष्य को देखकर चलेंगे, तो कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जरूरी यह है कि आप उस प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दें, जो लक्ष्य की ओर ले जा रही है। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन प्रक्रिया प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। हर छोटा कदम मायने रखता है, इसलिए हर दिन एक फीसदी बेहतर होने का प्रयास करें।*

## दूसरा पहलू

बदलते परिदृश्य में कंटेंट निर्माता कुछ मिनटों की कहानियां पेश कर रहे हैं, जिनमें सस्पेंस, इमोशन और क्लाइमेक्स, सब कुछ मिलेगा।

# इस माइक्रो ड्रामा के आप भी किरदार हैं

**औसतन** हर व्यक्ति दिन में करीब पांच घंटे मोबाइल स्क्रीन से चिपका रहता है। सवाल यह है कि इन पांच घंटों में हम देख क्या रहे हैं? लंबी फीचर फिल्में और टीवी धारावाहिक हाशिये पर जा रहे हैं। युवा सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में चाहता है। रील्स देखते-देखते उसकी ध्यान अवधि लगातार गिर रही है। बदलते परिदृश्य को समझते हुए कंटेंट निर्माताओं ने नया विकल्प पेश किया है, माइक्रो ड्रामा। यानी कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाने वाली कहानियां, जिनमें सस्पेंस भी है, इमोशन भी और क्लाइमेक्स भी।

**मुकुल श्रीवास्तव**

हर एपिसोड तेज रफ्तार, डायलॉग्स और ट्विस्ट से भरा होता है, ताकि देखने वाले का अगली कड़ी देखने का मन हो जाए।

माइक्रो ड्रामा जिसे लोग वर्टिकल माइक्रो वेब-सीरीज भी कहते हैं ये एपिसोड 1-2 मिनट के होते हैं। हर एपिसोड तेज रफ्तार, डायलॉग्स और ट्विस्ट से भरा होता है, ताकि देखने वाले का अगली कड़ी देखने का मन हो जाए। माइक्रो ड्रामा का सबसे ज्यादा विस्तार चीन में हुआ है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, साल 2024 के अंत तक माइक्रो ड्रामा का बाजार सात अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है। चीनी प्लेटफॉर्म क्वाइशोउ पर हर दिन 27 करोड़ लोग माइक्रो ड्रामा देखते हैं। अमेरिका में इन एप ने करीब डेढ़ अरब डॉलर का राजस्व हासिल किया है। भारत में भी माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट पैर पसार रहा है।

भारत के माइक्रो ड्रामा बाजार के अगले पांच वर्षों में 5 से 10 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म कुकू टीवी ने एक साल के भीतर ही पांच करोड़ से अधिक डाउनलोड्स दर्ज किए हैं।

भारत के माइक्रो ड्रामा बाजार के अगले पांच वर्षों में 5 से 10 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उदाहरण के लिए, भारत में माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म कुकू टीवी ने एक साल के भीतर ही पांच करोड़ से अधिक डाउनलोड्स दर्ज किए हैं। इसी तरह रील टीवी, पॉकेट टीवी रील शॉर्ट, फ्लिकरील्स जैसे कई प्लेटफॉर्म भी इस नए शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में उतरे हैं। दिग्गज एंटरटेनमेंट प्लेयर जैसे जी, टीवीएफ, एमएक्स प्लेयर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी इसमें काफी निवेश कर रहे हैं। जी ने हाल ही में अपने वर्टिकल एप बुलेट को लॉन्च किया है। कंपनियों के लगातार निवेश से साफ है कि यह नया फॉर्मेट अब महज एक ट्रेंड नहीं, बल्कि आने वाले मनोरंजन उद्योग की मुख्य धारा बनने की ओर बढ़ रहा है। ये माइक्रो ड्रामा बड़े बजट, बड़े सेट या बड़े एक्टर्स के मोहताज नहीं होते हैं। बस, अच्छी कहानी और कुछ ठीक-ठाक कलाकारों से भी काम चल जाता है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स खुद का माइक्रो ड्रामा बना रहे हैं। इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने यह तो साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में कहानी कहने का तरीका बदल गया है, अब स्क्रीन छोटी है, समय कम है, लेकिन दर्शकों को मनोरंजन भरपूर और पहले से अधिक चाहिए।

## आंकड़े

### सोने का आयात

सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, जो सवा लाख रुपये प्रति दस ग्राम के आंकड़े को छूने के करीब है। इसका आयात भी बढ़ रहा है।

| | |
|---|---|
| 2020 | 28.2 |
| 2022 | 46.2 |
| 2023 | 35.0 |
| 2024 | 45.5 |
| 2025 | 58.0 |

आंकड़े संबंधित वित्त वर्षों में भारत में हुए सोना आयात के, अरब डॉलर में | स्रोत : MoC&I

**केशवानंद महाराज जिस माई के यहां भिक्षा मांगने जाते थे, उसके बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने कहा, 'अरी पगली रोती क्यों है, तेरा लड़का मरा थोड़े ही है।'**

# भगवान पर भरोसा रखा करो

अंतर्यात्रा
संकलित

**संत** केशवानंद महाराज उर्फ धूनी वाले दादाजी के बारे में बताया जाता है कि वह साईखेड़ा से उज्जैन आकर रहने लगे थे। वह स्वभाव से अक्खड़ जरूर थे, लेकिन उतने ही दयालु भी। वह कई बार लोगों को डंडा भी मार देते थे, लेकिन हर किसी को नहीं। बताया जाता है कि वह उन्हीं लोगों को डंडा मारते थे, जिन्हें भक्ति मार्ग पर लगाना होता था।

दादाजी अपना जीवनयापन भिक्षा मांगकर करते थे। एक बार की बात है, वह साईखेड़ा में जिस माई के यहां भिक्षा लेने के लिए जाते थे, उसके बेटे की मौत हो गई। महाराज जब पहुंचे, तो वह माई दहाड़ मारकर रोने लगी और अपने मृत पुत्र को उन्हें दिखाने लगी। दादाजी ने उस माई से कहा, 'अरी पगली रोती क्यों है, तेरा लड़का मरा थोड़े ही है।' इतना कहने के बाद उन्होंने उस बच्चे को एक लात मारी। लड़का करीब दो-तीन फुट ऊपर उछलकर नीचे गिरा और जोर से रोने लगा। यह देखकर उस बच्चे की मां दादाजी के चरणों में लिपटकर खुशी के आंसू भरकर रोने लगी और उनका धन्यवाद किया। वहां मौजूद अन्य लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज ने मृत बच्चे को कैसे जिंदा कर दिया? दादाजी ने लोगों से कहा, 'पगलो, भगवान पर भरोसा रखा करो।' दादाजी के बारे में बताते हैं कि वह शारीरिक पीड़ा ही नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा भी दूर कर लोगों को भक्ति मार्ग पर चलाते थे।

## अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 08 अक्तूबर, 1954

# ईरान में दस सैन्य अफसरों, दो नागरिकों को फांसी की सजा

**ईरान की एक फौजी अदालत ने गद्दारी करने व सरकार को पलटने का षड्यंत्र करने के अभियोग में दस सैन्य अफसरों और दो नागरिकों को मृत्यु दंड का आदेश दिया। अब उनकी अपील एक फौजी अपीलीय अदालत सुनेगी।**

# संबंधों के एक नए युग की शुरुआत

**भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन नई भूमिका की तलाश में है। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के गहरे निहितार्थ हैं।**

केएस तोमर

द्विपक्षीय रिश्ते

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आज अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनकी यह दो-दिवसीय यात्रा भारत-ब्रिटेन संबंधों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस यात्रा को लेकर पहले ही काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना चाहते हैं। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन द्वारा नई वैश्विक साझेदारियों की तलाश की पृष्ठभूमि में भारत एक रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकता का प्रतिनिधित्व करता है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लागू करने, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों की पहचान करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करेगी। व्यापार के अलावा, स्टार्मर की मौजूदगी जलवायु परिवर्तन, एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता और शासन के बहुपक्षीय ढांचे जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करने की ब्रिटेन की इच्छा का संकेत देती है।

इस वर्ष 24 जुलाई को भारत-ब्रिटेन एफटीए पर हस्ताक्षर हुए थे, जो इस यात्रा के केंद्र में होगा। तीन वर्ष से ज्यादा समय की बातचीत के बाद हुए इस समझौते से टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवियर, खेल सामान, खिलौने, समुद्री उत्पाद, नग और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो उपकरण और ऑर्गेनिक केमिकल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टैरिफ हटने या कम होने की उम्मीद है। इससे द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 अरब पाउंड वार्षिक वृद्धि का अनुमान है और दोनों देशों ने 2030 तक 120 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है। एफटीए को भारत के सबसे व्यापक व्यापार समझौते और ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते के तौर पर वर्णित किया गया है। यद्यपि, इसकी सफलता के लिए निरंतर ध्यान देना पड़ेगा। प्रमुख चुनौतियों में नियामकीय दिशा सुनिश्चित करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना और दोनों पक्षों के लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को सुगम बनाना शामिल है। स्टार्मर की यात्रा इन परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर स्पष्टता प्रदान करने और हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने का अवसर प्रदान करती है।

इसके अलावा, ब्रिटेन और भारत द्वारा एफटीए को केवल टैरिफ-कटौती तंत्र से आगे ले जाने के लिए पूरक पहलों की खोज किए जाने की उम्मीद है। इनमें अनुसंधान एवं विकास, नवाचार समूहों, वित्तीय प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकी में संयुक्त निवेश शामिल हैं। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग को शामिल करके दोनों राष्ट्र एक लचीली, भविष्य-सुरक्षित आर्थिक साझेदारी बनाने का लक्ष्य रखते हैं। स्टार्मर की यात्रा केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर भी है, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, ऊर्जा, जलवायु, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंध निहित हैं। भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत-ब्रिटेन के बीच घनिष्ठ सहयोग एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार कर सकता है।

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री स्टार्मर मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा, दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण को संबोधित करेंगे, जहां उद्योग विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस मंच से भारत-ब्रिटेन साझेदारी में तकनीक, फिनटेक और नवाचार की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाले जाने की उम्मीद है। नौ अक्तूबर को, दोनों प्रधानमंत्री भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत प्रगति की समीक्षा करेंगे, जो विजन 2035 के अनुरूप है। यह एक दस वर्षीय रोडमैप है, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा व लोगों के बीच संबंधों से जुड़ी पहलों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एजेंडे में व्यवसायों व उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत भी शामिल है, जिसमें विशेष रूप से हाल ही में हस्ताक्षरित एफटीए से उत्पन्न अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

स्टार्मर की यात्रा भारत-ब्रिटेन संबंधों के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। अपनी शक्ति का लाभ उठाकर भारत और ब्रिटेन एक ऐसी दूरदर्शी साझेदारी की नींव रख सकते हैं, जो वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। अर्थशास्त्र से परे इस यात्रा के संकेत गहरे हैं। भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। इसलिए, यह यात्रा भारत-ब्रिटिश संबंधों के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक हो सकती है, जिसके निहितार्थ द्विपक्षीय गलियारों से कहीं आगे बढ़कर व्यापक एशियाई और वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित करेंगे।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

# हरित पटाखों की पैरवी

पिछले कई वर्षों से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दाग ढोने वाली दिल्ली और इसके बाशिंदों के लिए यह वाकई चिंता की बात है कि खुद दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों की इजाजत हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सूबे की मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और पर्व, दोनों को जरूरी करार देते हुए सोमवार को एलान किया कि उनकी सरकार जन-भावनाओं का ख्याल करते हुए इस अनुमति के लिए प्रयास करेगी, ताकि लोग पूरे उल्लास से दीपावली मना सकें। दीपावली के आस-पास दिल्ली में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अक्सर पड़ोसी प्रदेशों के किसानों को दोषी ठहराया जाता है कि उनके पराली जलाने की वजह से दिल्ली वालों की सांसें फूल रही हैं। अभी बहुत दिन नहीं बीते, जब इससे संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी कि वह नियमों के खिलाफ जाकर पराली जलाने वाले किसानों को गिरफ्तार नहीं कर रही। अदालत ने पंजाब सरकार के नुमाइंदे से पूछा था, अगर पर्यावरण संरक्षण का आपका इरादा सच्चा है, तो कार्रवाई से पीछे क्यों हट रहे हैं?

निस्संदेह, सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली में गहराते प्रदूषण का एक बड़ा कारक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में किसानों द्वारा अपने खेतों में पराली जलाने को माना जाता है। इस समस्या के निदान के लिए वहां की सरकारें अपने किसानों को मशीनें और सब्सिडी तक दे रही हैं, ताकि दिल्ली का दर्द कुछ कम हो सके, मगर यहां दिल्ली सरकार ही पटाखे की पैरवी कर रही है! ग्रीन या हरित पटाखों को पर्यावरण के अनुकूल बताया जाता है, मगर ये पूर्णतया प्रदूषण मुक्त नहीं होते। ज्यादातर ग्रीन पटाखों में बोरियम नाइट्रेट नहीं होता, जो पारंपरिक पटाखों का सबसे खतरनाक घटक होता है। मगर तब भी विशेषज्ञों का दावा है कि ये सामान्य पटाखों के मुकाबले 30 प्रतिशत की ही राहत देते हैं। इसी तरह, आम पटाखे जहां 160 से 200 डेसिबल तक आवाज पैदा करते हैं, जबकि हरित पटाखों की ध्वनि-सीमा 100 से 130 डेसिबल तक सीमित होती है। जाहिर है, ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे में, दिल्ली सरकार अपनी मांग को अदालत में कैसे उचित ठहराएगी?

**दीपावली हर अंधियारे कोने को रोशन करने का त्योहार है, अंधाधुंध आतिशबाजी के शोर-शराबे से अपने बच्चों-बूढ़ों को बीमार करने का अवसर नहीं।**

निस्संदेह, हमारे जीवन में पर्व-त्योहारों का काफी महत्व है और इनके उल्लास में कमी नहीं आनी चाहिए, मगर पटाखों से उपजे प्रदूषण का असर जब एक-एक नागरिक की तकलीफें बढ़ाने वाला हो, तब एक जिम्मेदार शहरी के नाते क्या हमारा यह दायित्व नहीं हो जाता कि उल्लास जाहिर करने के हम दूसरे अनुकूल तरीके अपनाएं? तमाम कोशिशों के बावजूद राजधानी में सामान्य पटाखों की बिक्री पर ही पूर्ण शिकंजा नहीं कसा जा सका है, तब दिल्ली सरकार का यह रुख इसकी चोर-बाजारी करने वालों का हौसला ही बढ़ाएगा। ग्रीन पटाखे वैसे भी आम पटाखों के मुकाबले महंगे होते हैं। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि सरकार किसी किस्म के पटाखे के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए लोगों को प्रेरित करे। हमारे त्योहारों को बाजार ने अधिक आडंबरयुक्त बनाया है और इसके कारण उनके मूल संदेश को क्षति पहुंची है। दीपावली हर अंधियारे कोने को रोशन करने का त्योहार है, अंधाधुंध आतिशबाजी के शोर-शराबे से बच्चों-बूढ़ों को बीमार करने का अवसर नहीं। इसलिए हमारी सरकारों को जन-भावनाओं का ख्याल करते हुए कोई अविवेकी कदम उठाने से बचना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 08 अक्तूबर, 1950

## तलवार की धार पर अमन

महात्मा गांधी की 82वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक विराट सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 'आज फिर कोरिया से लड़ाई की चिनगारी फैलने से विश्वव्यापी युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। कोरिया की सीमाएं दो बड़े जबर्दस्त देश- चीन और रूस से मिलती हैं। दुनिया का अमन एक तलवार की धार पर अटका हुआ है, न जाने थोड़े दिनों बाद हमें क्या खबर सुनने को मिले- विश्व-युद्ध की या अमन की।' और यह स्थिति अभी तक बनी हुई है।

यद्यपि कुछ अमरीकी राजनीतिक पर्यवेक्षकों को आशा है कि रूस स्वयं हस्तक्षेप नहीं करेगा और आवश्यक हुआ, तो साम्यवादी चीन को उत्तरी कोरिया की लड़ाई लड़ने के लिए फुसलायेगा, किन्तु समझ में नहीं आता कि रूस तथा चीन किस प्रकार अपने सुहृद उत्तरी कोरिया को अपने दुर्भाग्य पर माथा पीटते हुए देखते रहेंगे। दक्षिणी कोरिया की सेनाएं तो 38वीं अक्षांश रेखा को पार कर उत्तर में काफी बढ़ गई हैं, लेकिन मैकार्थर के आदेश से अमरीकी, ब्रिटिश तथा दूसरी सेनाएं अभी आगे नहीं बढ़ी हैं। कहा जाता है कि मैकार्थर संयुक्त राष्ट्र संघ से 38वीं अक्षांश रेखा को पार करने के लिए निश्चित आदेश चाहते हैं। आगे बढ़ने में उनकी हिचकिचाहट का कारण प्रचंड रूसी व चीनी सेनाओं से मुठभेड़ की संभावना भी हो सकता है। हो सकता है कि वह आत्मसमर्पण की मांग के बारे में साम्यवादियों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उपयुक्त अवसर पर उन सेनाओं को उत्तर की ओर अभियान करने का हुक्म दे देंगे, जो 38वीं अक्षांश रेखा पर जमा हैं।

प्रश्न यही है कि माओत्से तुंग की सरकार हस्तक्षेप करेगी या नहीं। यूं तो साम्यवादी शासन के वार्षिक दिवस पर पेकिंग में आयोजित समारोह में साम्यवादी चीन के प्रधानमंत्री चो-एन-लाइ ने संयुक्त राज्य अमरीका को उसकी आक्रमणात्मक कार्रवाइयों के बारे में चेतावनी देते हुए रोषपूर्ण शब्दों में कहा था कि चीन अपने पड़ोसी के विरुद्ध आक्रमण को चुपचाप नहीं सहेगा। इसके साथ ही यह समाचार भी मिला था कि दो लाख चीनी सेना कोरिया की सीमा पर भेज दी गई है। लेकिन अभी तक चीनी फौजों के साथ कहीं कोई मुठभेड़ नहीं हुई है।

# गाजा में कैसे होगा अमन का आगाज

औसाफ सईद | पूर्व राजनयिक

यहां स्कैन करें

**ट्रंप की गाजा शांति योजना जोखिम भरे दांव में बदल गई है। शर्म अल-शेख वार्ता इसे व्यावहारिक युद्ध-विराम की ओर ले जाएगी या अपने विरोधाभासों के कारण ध्वस्त हो जाएगी।**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना कूटनीतिक प्रयास से बढ़कर अब एक ऊंचे दांव वाली नाजुक हकीकत में तब्दील हो गई है। बीते 3 अक्तूबर को हमास द्वारा सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा के शासन से अलग रहने के सशर्त स्वीकार के बाद ट्रंप ने इजरायल को तत्काल बमबारी रोकने का आदेश दिया था। हालांकि, इसके बाद भी बमबारी हुई और इसमें दर्जनों लोग हताहत भी हुए। मगर आधिकारिक तौर पर पिछले दो साल से चल रहा युद्ध निर्णायक वार्ता के दौर में प्रवेश कर गया है। 7 अक्तूबर, 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इसकी दूसरी बरसी पर सभी की निगाहें मिस्र के शर्म अल-शेख पर टिकी हैं, जहां परदे के पीछे यह वार्ता चल रही है। इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधि के तौर पर ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ को भेज रखा है। इजरायल की ओर से रॉन डर्मर और हमास की ओर से खलील अल-हय्या के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 'तेजी से आगे बढ़ने' के लिए प्रेरित किए जाने के बावजूद अभी चर्चा प्रारंभिक चरण में ही है। इस बातचीत में बंधकों व कैदियों की अदला-बदली की रूपरेखा तय करने, दुश्मनी समाप्त करने और सुरक्षा गारंटी की व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। हालांकि, अब तक बंधकों या कैदियों की अदला-बदली पर कोई समझौता नहीं हुआ है। जहां तक प्रशासन के हस्तांतरण की बात है, तो ट्रंप की अध्यक्षता वाले 'शांति बोर्ड' की देखरेख में इसके लिए एक समिति गठित होनी है। इसके तहत एक 20-सूत्रीय योजना बनाकर ढांचा तैयार किया जाएगा, जो सुरक्षा, शासन और पुनर्गठन के तीन स्तंभों पर आधारित होगा। यह अस्थायी व्यवस्था फलस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के सत्ता संभालने तक कायम रहेगी। इस पर अभी हमास की स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि वह गाजा क्षेत्र से इजरायल की पूर्ण वापसी और निरस्त्रीकरण की शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय गारंटी की मांग कर रहा है। खबरों के अनुसार, इस मुद्दे पर हमास के राजनीतिक और सैन्य महकमों के बीच मतभेद उभर आने के संकेत मिल रहे हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए मिस्र फलस्तीनी गुटों का व्यापक सम्मेलन कराने वाला है।

उधर, हमास की प्रतिक्रिया पर ट्रंप के सकारात्मक रुख ने इजरायली खेमे में विवाद खड़ा कर दिया है। उसके वरिष्ठ अधिकारी हमास की सशर्त स्वीकृति को 'वास्तव में अस्वीकार' मान रहे हैं। फिर भी, ट्रंप के इस आशावादी दावे ने कि हमास 'स्थायी शांति के लिए तैयार है' प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चौंका दिया और इजरायल ने अधिक कठोर मुद्रा अपना ली है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हमास को शस्त्रहीन करके ही रहेंगे, चाहे उंगली टेढी ही क्यों न करनी पड़े। उन्होंने यह भी दावा किया कि इजरायली सेना गाजा पर नियंत्रण रखेगी। उन्होंने अलग फलस्तीन देश के वजूद को भी सिरे से नकार दिया। जाहिर है, इन सबसे इस योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के अपने अति-दक्षिणपंथी सहयोगियों को खुश करने के लिए नेतन्याहू इस तरह के बयान दे रहे हैं। उधर, तेल अवीव में हजारों प्रदर्शनकारी युद्ध-विराम की मांग कर रहे हैं और इस अवसर को 'अभी नहीं तो कभी नहीं' बता रहे हैं।

बहरहाल, अगर शर्म अल-शेख वार्ता सफल होती है, तो यह सशर्त समझौता अल्पकालिक लाभ देने वाला साबित हो सकता है। दुश्मनी खत्म होने से विनाशकारी नुकसान झेल रही आबादी को तत्काल राहत मिलेगी, जबकि बंधकों और कैदियों की वापसी से त्रासद मुद्दों का समाधान होगा। राफा क्रॉसिंग को फिर से खोले जाने से बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए गाजा में बड़े पैमाने पर सहायता आ सकेगी। अमेरिका के नेतृत्व वाला आईएसएफ आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने, विसैन्यीकरण में सहायता करने और स्थानीय व क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठाने के लिए तैयार है। इस्लामी देशों ने ट्रंप के दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन आईएसएफ के सैन्यीकरण में साझीदार बनने से उन्होंने परहेज ही बरता है।

ट्रंप की गाजा शांति योजना का वास्तविक महत्व इसके दीर्घकालिक भू-राजनीतिक नतीजों में निहित है। यह अब्राहम समझौते का रणनीतिक विस्तार है, जिसे फलस्तीनी संघर्ष को सुलझाने और इजरायल व खाड़ी के देशों के बीच पूर्ण क्षेत्रीय गठबंधन की मुख्य बाधा को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि यह सफल रहा, तो यह इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंध सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यदि विफल हुआ, तो यही माना जाएगा कि क्षेत्र में फलस्तीनी अधिकारों को कुचलकर ही स्थिति सामान्य हो सकेगी।

फलस्तीनियों के लिए 'राज्य के दर्जे का मार्ग' एक संप्रभु देश की ओर ले जाने वाली संभावना नहीं है। यह वादा फलस्तीन प्राधिकरण सुधारों पर निर्भर है और इसके लागू होने की कोई समय-सीमा नहीं है। इसलिए आलोचक इसे एक अनिश्चितकालीन स्थगन ही मानते हैं। इसके अलावा, इजरायल की गाजा से वापसी का वादा भी बहुत साफ नहीं है। सबसे संभावित परिणाम जो दिखता है, वह लंबा संक्रमणकालीन चरण है, जिसमें गाजा का प्रशासन एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के पास रहेगा।

इस प्रकार ट्रंप की गाजा शांति योजना जोखिम भरे दांव में बदल गई है। शर्म अल-शेख वार्ता एक परीक्षा है। यह इस मसले को या तो एक व्यावहारिक युद्ध-विराम की ओर ले जाएगी या अपने विरोधाभासों के कारण ध्वस्त हो जाएगी। देखा जाए, तो इस मामले में स्थायी सफलता हमास की सियासी महत्वाकांक्षाओं और इजरायल के पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण पर जोर वाले गहरे वैचारिक विभाजन के बीच पुल बनने पर निर्भर करती है। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इसके रचयिता इन असंगत मांगों को पूरा कर सकेंगे?

भारत के लिए यह योजना रणनीतिक दुविधा वाली है। इसकी सफलता त्रासद घटनाओं को कम करेगी और 'भारत, मध्य-पूर्व व यूरोप' के बीच के आर्थिक गलियारे को सक्रिय करने लायक वातावरण तैयार करेगी। मगर ईरान पर ट्रंप की अधिकतम दबाव की नीति मध्य एशिया के इस वैकल्पिक प्रवेश द्वार में भारत के निवेश को खतरे में डालती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंधों से छूट को हाल ही में रद्द कर दिया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# आदमखोर भेड़ियों के आतंक से फिर सहमा बहराइच

पंकज चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज में भेड़ियों के आतंक से लोग डरे-सहमे हुए हैं। बीते 27 सितंबर को वन विभाग ने घोषणा की कि उत्पात मचाने वाले भेड़िये मार गिराए गए हैं और 28 सितंबर की रात ही कैसरगंज के मझारा तौकली में खेत की रखवाली कर रहे 80 साल के खेदन और उनकी पत्नी के शव मिले। शवों के पास भेड़ियों के पदचिह्न पाए गए। मझारा तौकली में बीते 25 दिनों में ऐसे 24 लोग सामने आए हैं, जिन पर भेड़ियों ने हमला किया। पिछले साल 11 लोग आदमखोर भेड़ियों के शिकार बने थे और करीब 50 घायल हुए थे।

जब बरसात के बादल छंटने वाले होते हैं, तब घने जंगलों और सरयू या घाघरा व उसकी सहायक नदियों राप्ती, गेरुवा, कोदियाला से समृद्ध बहराइच के गांव-गांव से भेड़ियों की दहशत की खबरें आने लगती हैं। जिले के कैसरगंज इलाके में लाखों रुपये खर्च हुए और कहा गया कि छह आदमखोर भेड़िये मार गिराए गए हैं और लगभग उतने ही पकड़े गए हैं। लेकिन हर दिन पचास हजार रुपये खर्च करने के बाद भी आदमखोर भेड़िये काबू में नहीं आ रहे। वैसे, पर्यावरणीय अध्ययन इस बात का होना चाहिए कि आखिर भेड़िये हिंसक क्यों हो रहे है? एक विशेष इलाके और खास मौसम में ही उनका स्वभाव क्यों बदल रहा है? हमें यह भी समझना होगा कि किसी जंगल के पर्यावरणीय संतुलन में भेड़िया व लोमड़ी जैसे जीव अनिवार्य हैं।

**भेड़िया जंगल और प्राकृतिक संतुलन के लिए अहम है। हमने ऐसे ही चीते खो दिए, फिर 75 साल बाद अफ्रीकी देशों से उन्हें मंगवाना पड़ा।**

भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पैलिप्स) भूरे भेड़िये की एक लुप्तप्राय उप-प्रजाति है, जो भारतीय उपमहाद्वीप और इजरायल तक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। चिड़ियाघरों में कोई 58 भेड़िये हैं, जबकि पूरे देश में 55 प्रजाति के तीन हजार से कम भेड़िये ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इनकी संख्या संभवतः तीन सौ भी न हो। आम तौर पर भेड़िये इंसान से डरते हैं और मनुष्यों पर हमला करना दुर्लभ है। ऐसे में, भेड़ियों को मार देना या कैद कर लेना एक तात्कालिक विकल्प तो है, लेकिन गहन जंगल और गन्ने की सघन खेती वाले बहराइच में इस जानवर का नरभक्षी बन जाना इंसान-जानवरों के टकराव की ऐसी अबूझ पहेली है, जिसका हल नहीं खोजा गया, तो यह समस्या विस्तार ले सकती है।

जंगल के पिरामिड को समझें, तो सबसे घले वनों में, जहां पेड़ों की ऊंचाई के कारण रोशनी नीचे कम पहुंचती है, चमगादड़ जैसे निशाचर जानवर आदि का पर्यावास होता है। फिर ऊंचे पेड़ों व ऊंची झाड़ियों वाले जंगल आते हैं, जहां मांसाहारी पशु, जैसे बाघ, तेंदुआ आदि अपने-अपने दायरे में रहते हैं। इन वनों में रहने वाले हिरण, खरगोश, भालू, हाथी आदि जीव वनस्पति से अपना पेट भरते हैं और मांसाहारी जानवरों को जब भूख लगती है, तो वे अपने दायरे से बाहर निकल इनका शिकार करते हैं। मानव बस्ती और जंगल के बीच का दायरा चरागाहों का होता है और बिलाव, लोमड़ी, भेड़िये इसी में रहते हैं। वे मांसाहारी जीवों द्वारा अपने शिकार के छोड़े गए अंगों से पेट भरते हैं। यदा-कदा बस्ती के मवेशियों को पकड़ते हैं।

हमें समझना होगा कि कोई भी जानवर इंसान या अन्य जीवों पर भोजन के लिए या फिर भय के चलते हमलावर होता है। यदि बारीकी से देखें, तो जंगल के पिरामिड तहस-नहस हो गए हैं और अब कम घने जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवर भी बस्ती के पास आ जा रहे हैं। जब भेड़िया को बस्ती में उसके लायक छोटे पशु नहीं मिलते, तो वह छोटे बच्चों को उठाता है और एक बार अगर उसे मानव-रक्त का स्वाद लग जाता है, तो वह उसके लिए पागल हो जाता है।

निश्चित ही बहराइच में जब भेड़िये नरभक्षी हो गए हैं, तो उनसे निपटना जरूरी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आखिर ऐसे हालात बने ही क्यों? प्रकृति में भेड़ियों का भी हिस्सा है, फिर इंसान से अचानक टकराव क्यों हो गया? भेड़िया जंगल और प्राकृतिक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीव है। गौर कीजिए, हमने ऐसे ही चीते खो दिए थे, फिर 75 साल बाद अफ्रीकी देशों से उन्हें मंगवाना पड़ा।

आज जरूरत इस बात की है कि किसी भी जानवर को यूं हिंसक होने से रोका जाए, जिससे वह नरभक्षी बने और इसके लिए उनके जंगलों और स्वाभाविक आहार को संरक्षित करने का काम करना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

# तब तक आप अकेले नहीं

एक जिज्ञासु शिष्य का सवाल है, 'क्या हमें परम पुरुष से बार-बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें और शक्ति दें?'

आपके सामने कर्तव्य की पुकार है और परम पुरुष आपको इस आह्वान का जवाब देने के लिए आवश्यक शक्ति पहले ही दे चुके हैं। उनके लिए आपको शक्ति मांगना जरूरी नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि परम पुरुष ब्रह्मांड की हरेक इकाई में व्याप्त हैं- सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, निहारिकाओं, तारों और छोटे से छोटे अणुओं में उसकी व्याप्ति है। उनकी संगति और व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि आप कभी असहाय, अकेले नहीं हैं। जब तक आपके पैरों के नीचे धूल का एक कण है और सिर पर कोई तारा टिमटिमा रहा है, तब तक आप अकेले नहीं हैं। इसलिए भय और आशंका की कोई आवश्यकता नहीं। बस, आध्यात्मिक पथ पर स्थिर रहें।

हमेशा याद रखें कि परम पुरुष आपको चाहते हैं। उनकी विशेष इच्छा के सम्मान में आप अपनी साधना और कर्तव्य निभाते हैं। ध्यान रहे, आपकी साधना के दौरान परम पुरुष आपकी मानसिक वस्तु हैं और आप उनके विषय हैं। यह उल्टा प्रतीत होता है, पर यही सच्चाई है। जब आप इष्ट मंत्र का जाप करते हैं या विचार करते हैं, तब स्पष्ट होना चाहिए कि आप विषय हैं और परम पुरुष सब कुछ देख रहे हैं। मन में यह विश्वास रखें कि परम पुरुष ने अतीत में आप पर ध्यान दिया है, अब भी दे रहे हैं व भविष्य में भी देखभाल करेंगे। जब यह असंदिग्ध विश्वास आपके मन में होगा, तब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका विरोध या नुकसान नहीं कर सकती। परम पुरुष के ईश्वरीय आदेश आपकी सहायता करेगा।

इसलिए मनुष्य को इस संसार में हमेशा न्याय और सौहार्द के साथ रहना चाहिए। उसके लिए किसी का शोषण न करना, किसी को यातना या कष्ट न देना और अपनी क्षमता के अनुसार अपनी शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक है। उसे अपनी बुद्धि, शरीर और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जब आपने अपनी सारी शक्ति और क्षमता का प्रयोग कर लिया, तब परम पुरुष स्वयं आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। आपको अतिरिक्त शक्ति के लिए प्रार्थना में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।

**आपको अतिरिक्त शक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। यह चिंता करना कि अब मेरा क्या होगा, बिल्कुल निरर्थक है। परम पुरुष हर परिस्थिति को देखते रहते हैं और आवश्यक कदम उठाते हैं।**

यह चिंता करना या डरना कि अब मेरा क्या होगा, बिल्कुल निरर्थक है। परम पुरुष हर परिस्थिति को देखते रहते हैं और आवश्यक कदम उठाते हैं।

इसलिए, मानव जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है- परम पुरुष प्रदत्त शक्ति का उपयोग, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह और पूरी निष्ठा से परम पुरुष की कृपा का अनुभव करना। भय, आशंका और निर्भरता छोड़ दें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। यही मानव और परम पुरुष के बीच का संबंध हैं-सहयोग, सम्मान और अविश्वसनीय सुरक्षा।

**श्री श्री आनंदमूर्ति**

योगी आदित्यनाथ | मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसके पास सर्वाधिक कृषि विश्वविद्यालय हैं। वर्ष 1950 की तुलना में 2023 में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश में पांच गुना की वृद्धि हुई है।

अनुलोम-विलोम

सनातन

# सनातन में हिंसा और नफरत का स्थान नहीं

सनातन धर्म को लेकर इधर हर कोई मुखर है। चाहे उसके पक्ष में हो या विपक्ष में। तर्क भी ऐसे-ऐसे कि सुनने वाला थोड़ा भी पढ़ा-लिखा और जानकार हो, तो अपना सिर पकड़कर बैठ जाए। सनातन का मतलब है, जो आदिकाल से चला आ रहा है। इसका समर्थन करने वाले लोग हरेक बात में सनातन को आधार बना लेते हैं, वह नफरत फैलाना हो या किसी विचार पर हमला करना। इसी उधार ली गई बुद्धि के कारण सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में काफी बवाल मचा रहा। यहां एक मामले की सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी कुछ वकीलों को नागवार गुजरी और उन्होंने इसे सनातन के अपमान का मुद्दा बना दिया।

उनमें से एक वकील ने अशोभनीय अचारण का प्रदर्शन किया। अब अगर सीजेआई की मूल टिप्पणी को कोई विवेकपूर्ण तरीके से देखे, तो उसमें सनातन या किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई अपमानजनक बात नहीं दिखती। लेकिन कुछ सिरफिरे किस्म के लोगों को इन दिनों किसी न किसी बहाने चर्चा में आने और धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बनने का मौका मिल जाता है। अगर कोई टिप्पणी किसी को पसंद नहीं हो, तब भी उसे अभद्र व्यवहार करने की छूट नहीं मिल जाती है। उस पर हिंसा पर उतारू अगर कानून का ही रक्षक कहलाने वाला वकील हो, तो इसको बिल्कुल अस्वीकार्य ही माना जाएगा। इसलिए प्रधान न्यायाधीश के साथ अभद्रता करने वाले उद्धत अधिवक्ता को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीजेआई के आचरण को देखिए, इस पूरी घटना के दौरान वह शांत बैठे रहे और अदालत की कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से उनके कार्यों पर फर्क नहीं पड़ता। उचित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वकील के दुस्साहस पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है।

आज समाज में जिस तरह घृणा और नफरत का माहौल बन गया है, यह उसी का प्रतिफल है। सनातन कोई ऐसी छुई-मुई चीज नहीं है, जिस पर किसी तरह की टिप्पणी का कोई प्रतिकूल असर पड़ जाए। यह हमारी हजारों साल की संस्कृति का जीता-जागता प्रमाण है। सनातन धर्म ने अनेक झंझावातों का सामना किया और उनसे नई ऊर्जा, नया तेज और नई आभा लेकर पूरित हुआ। इसने न केवल अपने अनुयायियों को, बल्कि हजारों अनजान नस्लों, आक्रांताओं को भी अपना बनाया है। इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं और वकीलों को इसके इस्तेमाल से बाज आना चाहिए।

**अपूर्व कौशल**, छात्र

# धर्म पर किसी तरह का हमला हम क्यों सहें

सनातन धर्म उतना ही प्राचीन है, जितनी यह दुनिया। सनातन ने हमारे देश, समाज और नैतिकता की मान्यताओं को गढ़ा और उसे सुदृढ़ किया है। यह इस देश के हिंदू समाज का प्राण है, उसका जीवनदाता है। इसे नष्ट करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन यह आज तक बना हुआ है, बल्कि मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि दुनिया भर में सनातन को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और कई हिस्सों से इसे मिटाने की कोशिश भी हुई है। लेकिन अब ऐसे कुत्सित प्रयासों के खिलाफ हिंदू समाज सजग है और इस पर होने वाले किसी प्रकार के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।

हाल के दिनों में सनातन के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया गया है और इसकी छवि को धूमिल करने की कोशिशें हुई हैं। इसमें सनातन धर्मावलंबियों ने भी कीचड़ उछाले हैं। अभी कुछ साल पहले ही तमिलनाडु सरकार में मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ी फटकार लगाई। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म को मिटाने की बात की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टालिन को कहा, 'आप आम आदमी नहीं हैं। आप एक मंत्री हैं। आपको परिणाम पता होना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग बताया। दरअसल, उदयनिधि स्टालिन ने 'सनातन उन्मूलन सम्मेलन' में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से इसकी तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि इसके विरोध की नहीं, बल्कि सफाये की जरूरत है। इससे कई लोग खुश भी हुए, लेकिन वृहत्तर हिंदू समाज को बुरा लगा। लेकिन देखें, तो सनातन का अपमान कराने में केवल इसके विरोधी ही नहीं हैं, बल्कि सनातन के स्वयंभू ठेकेदार कई बाबा टाइप लोगों ने भी अपनी बयानबाजी और अनैतिक कृत्य से सनातन विरोधियों को मौका दिया है।

लेकिन इन सब बातों को छोड़कर हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए और सनातन विरोधियों को सबक सिखाना चाहिए। अब सनातन धर्म पर किसी तरह के हमले को किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें सनातन पर हमला करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि इस तरह की नफरत का एक छोटा हिस्सा भी दूसरे धर्मों के बारे में फैलाकर वे देख लें, तो पता चलेगा। उनमें थोड़ा-बहुत विवाद हो जाए कि आसमान सिर पर उठा लिया जाता है। लेकिन सनातन में अपमान सहने की क्षमता है और विरोधियों को मजा चखाने की भी।

**नेहा कुमारी**, गृहिणी

# सुरक्षित यातायात

यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित यातायात की आवश्यकता पर ध्यान दिया और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि वे सड़क सुरक्षा के नियम तय करें और ऐसा करते समय पैदल यात्रियों एवं गैर मोटर चालित वाहनों की आवाजाही को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करें। हालांकि अभी ऐसे नियम हैं तो, लेकिन पैदल यात्रियों और गैर मशीनी वाहनों की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता से बाहर हैं। सरकारों को सबकी सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता इसलिए देनी होगी, क्योंकि असुरक्षित यातायात के चलते हर वर्ष जो लाखों लोग जान गंवाते और गंभीर रूप से घायल होते हैं, उनमें एक बड़ी संख्या पैदल यात्रियों और गैर मोटर चालित वाहन चालकों या उनमें बैठे लोगों की होती है। वैसे मोटर चालित वाहनों की सुरक्षा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। भारत में सड़क दुर्घटना में मरने और घायल होने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यह इसलिए कहीं अधिक चिंताजनक है, क्योंकि देश में विश्व के कई देशों की तुलना में कहीं कम वाहन हैं। यदि इसके बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या के मामले में देश शीर्ष पर है तो इसका कारण है सरकारों, यातायात पुलिस और आम लोगों की ओर से सुरक्षित यातायात को महत्व न दिया जाना। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें और उनका स्थानीय प्रशासन सुरक्षित यातायात को लेकर आयोजन करता रहता है। कभी हेलमेट, सीट बेल्ट पहनने, सावधानी से सड़क पार करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और कभी यातायात का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती की जाती है, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसी पहल कुछ ही दिन अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे ही यातायात पुलिस की सख्ती थमती है, यातायात अव्यवस्थित एवं अराजक हो जाता है। इस अराजकता का सबसे अधिक शिकार बनते हैं साइकिल, रिक्शा चालक और पैदल यात्री। इसका कारण यह है कि अनेक स्थानों पर तो साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर चलने की गुंजाइश ही नहीं होती। अपने देश में सामान्य सड़कों की बात कौन करे, राजमार्गों पर भी हर तरह के वाहन चलते दिखते हैं। इस कारण भी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। सड़क दुर्घटनाओं का कारण केवल यातायात नियमों की अनदेखी ही नहीं, सड़कों के रखरखाव में कमी भी है। रही-सही कसर यातायात नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति और यातायात संकेतकों के अभाव या फिर उनके सही तरह से काम न करने से पूरी हो जाती है। यह ध्यान रखा जाए कि यातायात तब सुरक्षित होगा, जब यातायात नियमों का हर कोई पालन करेगा। सुरक्षित यातायात को लेकर किसी खास दिन, सप्ताह या पखवाड़े में ही नहीं, हर दिन सतर्क रहा जाना चाहिए।

# राहत के हों इंतजाम

बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन को मजबूर हुए हैं। प्रभावित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल इनकी मदद के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। लोगों को चिंता है कि क्या वह घर पर दीपावली, छठ मना पाएंगे। आमदनी के भी प्रभावित होने की आशंका है। सूप-डलिया बनाने वाले, मिट्टी के दीए और मूर्तियां बनाने वाले कामगारों का समय तो दिन-रात इसी में बीत रहा कि कैसे परिवार को सुरक्षित रखें। इन्हीं त्योहारों से होने वाली कमाई से कई कामगारों का घर कई महीनों चलता है, लेकिन फिलहाल सब ठप है। पशुपालकों की भी कुछ ऐसी ही चिंता है। पशुओं को ठीक से चारा नहीं मिल रहा, उनका दुग्ध उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में त्योहारों में दूध की बढ़ी मांग से होने वाली कमाई पर ग्रहण लगता दिख रहा है। राहत के नाम पर सिर्फ पेट भरने का इंतजाम और सिर पर छत मुहैया कराने जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा देने से काम नहीं चलेगा। त्योहारों में इनकी कमाई का रास्ता बंद नहीं हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाने की जरूरत है। जहां इन्होंने आश्रय ले रखा है, वहां आसपास ऐसे स्थल उपलब्ध कराने होंगे, जहां इन हुनरमंद कामगारों के हाथ अपना जौहर दिखा पाएं। बांस, चाक के साथ दूसरी जो भी सामग्रियां हों, वह उपलब्ध कराई जाएं। इनके सामान बाजार तक पहुंच जाएं, यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

**बाढ़ प्रभावित इलाकों के कामगारों की आमदनी के लिए इंतजाम होने चाहिए।**

## कह के रहेंगे

माधव जोशी

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला सही है?**

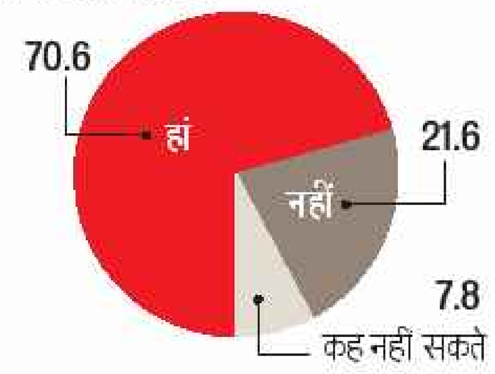


**आज का सवाल**
क्या जोहो का अरट्टई एप वाट्सएप का भारतीय विकल्प बनने में सक्षम है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# भारत के लिए अवसर और चुनौती

राजीव शुक्ला

**यदि भारत वैश्विक नेतृत्व का चेहरा बनना चाहता है, तो उसे घर के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा**

अवधेश राजपूत

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा संकट बार-बार सामने आता है जिसे 'किंडलबरगर ट्रैप' कहा जाता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री चार्ल्स किंडलबरगर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि जब कोई महाशक्ति वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व छोड़ देती है और कोई नई शक्ति उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे नहीं आती, तो पूरी दुनिया अराजकता के चंगुल में फंस जाती है। बीसवीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन कमजोर हो चुका था, अमेरिका तैयार नहीं था और नतीजा यह हुआ कि महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी आपदाएं दुनिया पर टूट पड़ीं। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ऊब का शिकार और घरेलू स्तर पर विभाजित है। चीन आधा-अधूरा और अविश्वसनीय नेतृत्व पेश कर रहा है। यूरोप अपने संकट में उलझा हुआ है। सवाल यह है कि इस बार वैश्विक व्यवस्था को अराजकता में जाने से कौन बचाएगा। क्या भारत इस खालीपन को भर सकता है?

भारत के पास आज वह पूंजी है, जो शायद किसी और देश के पास नहीं। आधे से अधिक भारतीय तीस वर्ष से कम आयु के हैं। जब पूरी पश्चिमी दुनिया वृद्ध होती आबादी से जूझ रही है और चीन जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है, तब भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति उसे भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बना सकती है। यह युवा शक्ति केवल श्रम नहीं है। यह विचार, नवाचार और डिजिटल ऊर्जा का भी स्रोत है। हालांकि यही युवा पीढ़ी रील, वीडियो और तात्कालिक प्रसिद्धि के आकर्षण में उलझकर अपनी दिशा खो सकती है। अगर युवा शक्ति को जिम्मेदारी की ओर मोड़ी जाए, तो भारत न केवल खुद को, बल्कि पूरी दुनिया को किंडलबरगर ट्रैप से निकाल सकता है।

भारत की ताकत उसकी विविधता है। भाषाओं, पंथों, जातियों और संस्कृतियों की अनगिनत परतों के बावजूद इस देश ने लोकतंत्र को जीवित रखा है। यही माडल दुनिया को चाहिए, क्योंकि पश्चिम में पहचान की राजनीति और राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और चीन अधिनायकवादी प्रणाली थोपना चाहता है। भारतीय प्रवासी समुदाय इस संभावना को गहराई देता है। फ्रांस में ओणम के उत्सव से लेकर ब्रिटेन में गणपति विसर्जन की तस्वीरें भारत की साफ्ट पावर बढ़ाती हैं, जो उसे दूसरों से अलग करती है। फिर भी भारत के सामने सबसे बड़ी कसौटी लोकतांत्रिक विरोधाभास की है।

भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज कहता है, पर घरेलू स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। यदि भारत वैश्विक नेतृत्व का चेहरा बनना चाहता है, तो उसे घर के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा। भरोसेमंद नेतृत्व के बिना आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होता। विश्वास, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था ही दुनिया को अराजकता से बचा सकते हैं। भारत की मौजूदा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बड़े दावे किए हैं जैसे जी-20 की अध्यक्षता और 'विश्वगुरु' बनने का सपना, लेकिन देश के भीतर कई कमजोरियां इस दावे को कमजोर करती हैं। चुनावी प्रक्रिया में पैसे का बढ़ता दबाव, मीडिया की आजादी पर उठते सवाल और स्वतंत्र संस्थाओं पर राजनीतिक प्रभाव देश की लोकतांत्रिक छवि धूमिल करते हैं।

जलवायु बदलाव से निपटने के वादे भी अक्सर बड़े उद्योगों को रियायत देने में खो जाते हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सरकार का खर्च अभी भी बहुत कम है। विदेश नीति में भी कभी-कभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अचानक बदलाव दिखता है, जिससे भरोसे की कमी महसूस होती है। यदि सरकार घर के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत नहीं करती, तो दुनिया में भारत की नेतृत्वकारी छवि सिर्फ भाषणों तक सिमट जाएगी।

भारत की सबसे बड़ी संभावना उसका टेक्नो-डेमोक्रेटिक माडल है। यूपीआइ ने दिखा दिया कि डिजिटल लेनदेन को कैसे आम आदमी के लिए सहज और सुलभ बनाया जा सकता है। आधार ने पहचान को डिजिटल रूप दिया, कोविड के दौरान कोविन प्लेटफार्म ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वास्थ्य प्रबंधन में तकनीक का उपयोग पारदर्शी और कुशल तरीके से किया जा सकता है। यह सब केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं थीं, यह उस सोच का परिचय थी, जिसमें तकनीक को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि भारत यही माडल दुनिया को दे, तो वह चीन के तकनीकी अधिनायकवाद और पश्चिम के लाभ केंद्रित पूंजीवाद के बीच एक नया संतुलित विकल्प पेश कर सकता है। हालांकि केवल विकल्प पेश करना पर्याप्त नहीं। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वैश्विक व्यवस्था को केवल किसी के आर्थिक हितों की नहीं, बल्कि सार्वजनिक वस्तुओं की जरूरत होती है। जैसे जलवायु वित्त, महामारी प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और मानवीय संकटों में सहयोग। भारत ने हाल के वर्षों में यह दिखाने की कोशिश की है कि वह इस भूमिका के लिए तैयार है, पर ऐसे प्रयास निरंतरता मांगते हैं। भारत को लगातार यह साबित करना होगा कि वह केवल अवसर की राजनीति नहीं करता, अपितु संकट की घड़ी में भी वैश्विक भरोसा कायम कर सकता है।

अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और साइबर स्पेस में संघर्ष भविष्य का सबसे बड़ा तनाव बनेगा। जलवायु परिवर्तन और प्रवासन से पैदा हुए संकट इस तनाव को और गहरा करेंगे। आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटने पर विकासशील देशों को बड़ा झटका लगेगा। यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध से भी जटिल हो सकती है, क्योंकि अब संघर्ष केवल सैन्य या विचारधारा का नहीं होगा, बल्कि तकनीक, स्वास्थ्य, जलवायु और आर्थिकी एक साथ उलझेंगे। यही समय है जब भारत खुद को तीसरे ध्रुव के रूप में पेश करे। जिस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बीसवीं सदी में एशिया-अफ्रीका को एक अलग आवाज दी, वैसे ही इस सदी में भारत तकनीक और लोकतंत्र के एजेंडे पर दुनिया को एक नया विकल्प दे सकता है। इसके लिए उसे केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक नेतृत्व दिखाना होगा। इतिहास हमेशा मौके की कसौटी पर नेताओं और राष्ट्रों को परखता है।

(लेखक कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)
response@jagran.com

# आत्मनिर्भरता की आत्मघाती बाधा

राजीव सचान

**अखाद्य वस्तुओं की बात तो दूर रही, हम दवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर पाने में नाकाम हैं**

इन दिनों विषाक्त कफ सीरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत का मामला चर्चा में है। हर तरफ आक्रोश है और उसके चलते जांच एवं कार्रवाई की बातें हो रही हैं। क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं। 1986 में मुंबई में विषाक्त कफ सीरप से 14 बच्चों की जान गई थी और दिल्ली में 33 बच्चों की। इसके बाद 2020 में जम्मू में 12 बच्चों की मौत हुई। हर बार सब कुछ ठीक करने की बातें की गईं, लेकिन स्थितियां नहीं बदलीं। 2022 में भारतीय दवा कंपनियों की ओर से बनाई गई कफ सीरप से गांबिया और फिर उज्बेकिस्तान में कई बच्चों की मौत हुई। इन मौतों का संज्ञान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लिया। इन मामलों के कारण भारत की दवा कंपनियों की बदनामी भी हुई। माना जा रहा था कि इस बदनामी के कारण विषाक्त कफ सीरप बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाली सरकारी एजेंसियां अपना काम सही तरह से करेंगी, पर नतीजा ढाक के तीन पात वाला रहा।

गांबिया और उज्बेकिस्तान को कफ सीरप सप्लाई करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई तो हुई, पर ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जो नजीर बनती और विषाक्त कफ सीरप बनने का सिलसिला थमता। ऐसा ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सीरप सप्लाई करने वाली दवा कंपनी के साथ हो तो हैरानी नहीं, क्योंकि इस सीरप में विषाक्त रसायन के प्रयोग को लेकर विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया और उनकी गुणवत्ता की परख करने वाली सरकारी एजेंसियां और सरकारें कुछ भी दावा करें, यह काम सही तरह नहीं होता और इसका प्रमाण यह है कि आए दिन दवाओं के सैंपल फेल होने की खबरें आती हैं। पिछले महीने खबर आई थी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों की 94 दवाओं के सैंपल फेल हुए। जांच में तीन दवाएं नकली भी निकलीं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन हर माह ड्रग अलर्ट जारी करता है। अगस्त के ड्रग अलर्ट के अनुसार हिमाचल की 31 दवा कंपनियों की 38 दवाएं गुणवत्ता के पैमाने पर खरी नहीं उतरीं। इसी ड्रग अलर्ट के अनुसार उत्तराखंड, पंजाब और मध्य प्रदेश की दवा कंपनियों में बनीं 56 दवाओं के सैंपल भी फेल हुए। जुलाई के ड्रग अलर्ट के अनुसार कुल 143 दवा नमूने फेल पाए गए। जून के ड्रग अलर्ट में कुल 188 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इनमें हिमाचल, गोवा और महाराष्ट्र की दवा कंपनियों की दवाएं थीं। इस पर संतोष नहीं जताया जा सकता कि ये सैंपल बैच विशेष के होते हैं और उन्हें हटाने को कहा जाता है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कि दोयम दर्जे की दवाओं को हटाने के निर्देश जारी करने के पहले वे मरीजों तक नहीं पहुंच जाती होंगी। चूंकि हिमाचल फार्मा कंपनियों का गढ़ है, इसलिए दवाओं के फेल सैंपल के मामले में यहां की कंपनियों का नाम खूब आता है, पर सच यह है कि शेष देश की दवा कंपनियों के सैंपल भी फेल होने का सिलसिला कायम है। भारत ने जेनेरिक दवाओं के निर्माण में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन यदि दोयम दर्जे की दवाएं बनती रहीं तो यह पहचान खतरे में पड़ सकती है।

छिंदवाड़ा में जब्त की जाती कफ सीरप ● एएनआइ

क्या हम केवल दवाओं की गुणवत्ता ही बनाए रख पाने में नाकाम हैं? नहीं। दवाओं के साथ-साथ खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों की गुणवत्ता के मामले में भी हमारी स्थिति दयनीय है। डिब्बाबंद खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में रहती है। उनके निर्माण में मानकों का उल्लंघन होता ही रहता है। कई बार तो उनमें विषाक्त अखाद्य वस्तुओं की भी मिलावट की जाती है, लेकिन मुश्किल से ही कोई मिलावटखोर दंडित होता है। जिस तरह दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली सरकारी एजेंसियां और ड्रग इंस्पेक्टर अपना काम ले-देकर करते हैं, उसी तरह खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता की परख करने वाली सरकारी एजेंसियां और फूड इंस्पेक्टर भी। सरकारी तंत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार का ही यह नतीजा है कि भारत में न तो दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित है और न ही खाद्य एवं पेय पदार्थों की। दूध, खोया, मिठाई, मसालों आदि में तो मिलावट की आशंका बनी ही रहती है और अक्सर यह सही पाई जाती है।

दवाएं हों या खाद्य एवं पेय पदार्थ या फिर अखाद्य वस्तुएं, अपने देश में सबके निर्माण के लिए मानक बने हुए हैं और सबकी गुणवत्ता परीक्षण के नियम-कानून हैं, लेकिन उनका सही तरह पालन नहीं होता। जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार होना एक अलिखित नियम सा बन गया है। इसी तरह जहां कहीं भी सरकारी अनुमति, संस्तुति, परीक्षण आदि की आवश्यकता होती है, वहां भी मानकों की अनदेखी के साथ नियम-कानूनों का उल्लंघन होता है। हैरानी नहीं कि बहुत कम भारतीय उत्पाद ऐसे हैं, जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चूंकि हमारे उत्पाद विश्वस्तरीय नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए वे विश्व बाजार में अपनी छाप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसी कारण हम आत्मनिर्भर बनने के अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। स्वदेशी के सहारे स्वावलंबी बनने की यात्रा तब पूरी होगी, जब हमारे हर तरह के उत्पाद भरोसेमंद होंगे। अच्छा हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगने का थोथा दावा आत्मनिर्भरता की राह की आत्मघाती बाधा है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

## ऊर्जा

### ज्ञान की आकांक्षा

ज्ञानेप्सा दो शब्दों 'ज्ञान' एवं 'इप्सा' के संयोग से बना है। ज्ञान का अर्थ है जानना एवं इप्सा का अर्थ है-इच्छा अथवा आकांक्षा। इस प्रकार, ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा ही ज्ञानेप्सा कहलाती है। ज्ञानेप्सा उस आंतरिक लालसा की द्योतक है, जो मनुष्य को सत्य, तर्क और अनुभव के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। ज्ञानेप्सा ही वह प्रेरक शक्ति है, जो अंधकार में भी प्रकाश खोजने को उन्मुख करती है एवं मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान तथा असत्य से सत्य की ओर अग्रसर करती है। यह जानने की सामान्य प्रवृत्ति अर्थात जिज्ञासा से हटकर सत्य के प्रति एक गहन और सतत आकांक्षा है।

जब हम चहुंओर, स्वयं अपने अस्तित्व अथवा किसी विषय विशेष की गहराइयों में उतरने की उत्कंठा महसूस करते हैं, तब उस स्थिति में ही ज्ञानेप्सा का उदय होता है। यह वस्तुतः जिज्ञासा से एक कदम आगे की अवस्था है। जिज्ञासा प्रश्न को जन्म देती है, जबकि ज्ञानेप्सा उत्तर प्राप्ति हेतु उचित कर्म एवं साधना का क्रियान्वयन करती है। ज्ञानेप्सा में व्यक्ति केवल जानना ही नहीं चाहता, अपितु अनुभव करना चाहता है एवं सत्य के साथ एकात्म होना चाहता है। मनुष्य के जीवन का विकास तभी संभव है, जब उसके भीतर ज्ञान की पिपासा बनी रहे। जीवन में प्रगति एवं आत्मबोध का आधार ज्ञानेप्सा ही है। ज्ञानेप्सा के अभाव में जीवन जड़वत हो जाता है। न उसमें खोज का आनंद होता है, न ही सृजन की लय। यह ज्ञानेप्सा ही है जो छात्र को अध्ययन के लिए प्रेरित करती है, विज्ञानियों को प्रयोग करने को बाध्य करती है और साधक को सत्य की खोज में तप करने का साहस देती है। जब व्यक्ति ज्ञान के प्रति सचेत होता है, तो उसके विचार, व्यवहार और निर्णय सभी में विवेक का प्रकाश झलकता है।

भारतीय संस्कृति में सर्वत्र ज्ञानेप्सा का महत्व झलकता है। ज्ञानेप्सायुक्त व्यक्ति सदा गतिशील रहता है और गतिशीलता ही जीवन है।

प्रेरणा अवस्थी

## पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

### जनता में जागरूकता जरूरी

'चुनाव मैदान में बिहार' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। लगभग सभी राजनीतिक दल हर चुनाव में लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं। ऐसी कुछ घोषणाएं मुफ्तखोरी का चलन बढ़ाती हैं। मुफ्तखोरी तमाम समस्याओं को जन्म देने के साथ ही विकास में अवरोध भी खड़े करती है। कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने सराहनीय पहल की है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्र में लोकलुभावन घोषणाओं के साथ यह भी बताना होगा कि इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वित्तीय बंदोबस्त कहां से किया जाएगा? हालांकि इसे व्यवहार में लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक दल कोई न कोई तोड़ निकाल लेंगे। इसलिए चुनावी दौर में लोगों को उसी तरह समझदारी बरतनी होगी, जितनी वे अपने लिए किसी कीमती सामान को खरीदने के लिए बरतते हैं। विज्ञापन की चकाचौंध में आकर खरीदारी से अक्सर बाद में पछताना भी पड़ जाता है। इसलिए राजनीतिक वादों को भी विवेक की कसौटी पर कसना जरूरी है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

### मतदाता ही वास्तविक शासक

विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सवाल यह है कि कितने प्रतिशत मतदाता यह जानते हैं कि लोकतंत्र में वास्तविक शासक वही हैं। चूंकि आबादी बड़ी है, इसलिए वे अपने शासन करने के अधिकार को जनप्रतिनिधियों के हाथों पांच वर्ष के लिए हस्तांतरण करते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जो विज्ञापन कराए जाते हैं, उसमें इन बातों को शामिल करने से मतदाता अपने मत का महत्व समझेगा। यद्यपि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही होता है, तथापि मतदाता लुभावने वादे-घोषणाओं के फेर में फंस जाते हैं या फिर तात्कालिक लोभ-लालच के चक्कर में अपने हितों की बलि चढ़ा देते हैं। चुनाव उन्हें अवसर देता है कि वे अपने हितों के अनुरूप शासकों का संजीदगी से चुनाव करें।

मुकेश कुमार मनन, पटना

### वायु सेना का योगदान

देश की रक्षा में वायु सेना के समर्पण और भूमिका के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं मातृभूमि की रक्षा की खातिर वायु सेवा के बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष आठ अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है। 1962 के युद्ध को छोड़कर, हर युद्ध में वायु सेना ने अपनी क्षमता और कौशल से दुनिया को परिचित कराया एवं भारत को जीत दिलाई। वायु सेना का योगदान केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप अथवा आपातकालीन स्थितियों में राहत और बचाव कार्यों में इनकी भूमिका सराहनीय रही है। सरकार की जवाबदेही है कि वायुसैनिकों के हितों की रक्षा करे व समाज उनका सम्मान करे।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

### अदालत की गरिमा पर गहरा आघात

न्याय के मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर मुख्य न्यायाधीश पर एक अधिवक्ता द्वारा जूता फेंकने के प्रयास की घटना न केवल स्तब्ध करने वाली है, बल्कि यह हमारी न्यायपालिका की गरिमा और संस्थागत सम्मान पर एक गहरा आघात है। इस निंदनीय कृत्य को किसी भी तर्क या रोष की अभिव्यक्ति के रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता है। इस तरह का व्यवहार न केवल व्यक्ति विशेष (मुख्य न्यायाधीश) का अपमान है, बल्कि यह उस संस्था के प्रति अनादर है, जिसपर नागरिकों का विश्वास टिका है। अदालतें रोष प्रकट करने का स्थान नहीं हैं; उनके भीतर भी विरोध को गरिमापूर्ण और कानूनी दायरे में होना चाहिए। एक वकील कोर्ट का अधिकारी होता है और उससे उच्चतम स्तर के पेशेवर आचरण और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार का हिंसक और अनियंत्रित व्यवहार वकालत के पेशे की नैतिकता का घोर उल्लंघन है। यही कारण है कि बार काउंसिल आफ इंडिया ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिवक्ता का लाइसेंस निलंबित किया। देश की सर्वोच्च अदालत में इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाता है। अदालत कक्षों में भी पर्याप्त सतर्कता की आवश्यकता है ताकि कार्यवाही की पवित्रता और जजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, फुलवारी, पटना

## पोस्ट

हमारे एजुकेशन सिस्टम की बलिहारी, जो स्कूलों और कालेज में बच्चे बिना कोचिंग के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। अतुल कुमार राय@AuthorAtul

सीजेआइ जस्टिस गवई पर हमले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट था। पचास के करीब पुलिस वाले आए थे, बीस कैमरे आए थे कवरेज के लिए और करीब पांच वकील ही पहुंचे विरोध-प्रदर्शन के लिए।
प्रभाकर मिश्रा@PMishra_Journo

जहरीला कफ सीरप बनाने, बेचने और उसकी सरकारी खरीद करने वाले अधिकारियों, इन तीनों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसी सजा जिसका भय कम से कम कुछ सालों तक तो कायम रहे।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

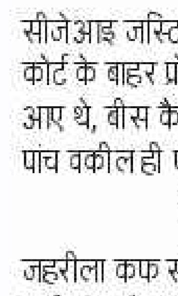

बीसीसीआइ के रवैये पर विराट और रोहित की तो कोई कड़वी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन कुछ प्रशंसक और ट्रोल विवाद की आग भड़का रहे हैं। याद रहे कि इन दिग्गजों का कद और भारतीय क्रिकेट में योगदान कप्तानी का मोहताज नहीं है। वे इतने अनुभवी हैं कि जब उचित लगेगा, तब खेलना छोड़ देंगे। सुशील दोशी@RealSushilDoshi

## जनपथ

रेवड़ियां बांटो चहे दो खाते में नोट,
किंतु जाति के नाम पर जाएगा हर वोट।
जाएगा हर वोट बांटते फिर भी रहिए,
लेन-देन का खेल पनपते रहना चहिए!
खाता देखें लोग फूटतीं मन फुलझड़ियां,
जब चुनाव के काल मिला करतीं रेवड़ियां!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 175

********

कल्पमेधा

*जिंदगी और समय, विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है।*

*– एपीजे अब्दुल कलाम*

# कानून के घर में

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन लोगों से संविधान और कानून की रक्षा, उसकी मजबूती के लिए काम करने की उम्मीद की जाती है, वही अपनी कुंठाओं का प्रदर्शन करते हुए सारे नियम-कायदे ताक पर रख दें। सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को प्रधान न्यायाधीश के साथ एक वकील ने जो किया, उससे यह तीखा सवाल उठा है कि ऊंची पढ़ाई-लिखाई करके वकालत का पेशा चुनने वाला एक व्यक्ति कैसे अपने दुराग्रहों की वजह से कानून और न्याय-प्रक्रिया को अपमानित कर सकता है। गौरतलब है कि एक वकील ने कार्यवाही के बीच में ही प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की ओर सिर्फ इसलिए जूता उछालने की कोशिश की कि उसके दिमाग पर सोशल मीडिया पर फैलाई गई कोई बात हावी हो गई थी। सरकार की ओर से हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था एक मुद्दा दिखने के बावजूद अदालत के भीतर इसका ढांचा कैसा था कि एक व्यक्ति अपनी मनमानी को लेकर बेखौफ था। गनीमत बस यह रही कि आरोपी की हरकत सीमित थी, वरना वहां कुछ भी हो सकता था।

सवाल है कि जिस व्यक्ति के भीतर विवेक इस कदर अनुपस्थित हो गया हो कि वह अदालत में ही प्रधान न्यायाधीश के प्रति आक्रामक हो गया, वह इससे ज्यादा हिंसक नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। इस मसले पर सोशल मीडिया पर फैलाई गईं बातों के असर में इस तरह बेलगाम और आक्रामक होना इस बात का भी सूचक है कि ऐसे व्यक्ति का विवेक सामान्य तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और वह कानून के तंत्र एवं शासन के बजाय हिंसा का रास्ता अख्तियार करना ज्यादा सही मानता है। शायद यही वजह है कि प्रधान न्यायाधीश ने भले ही उदारता दिखाते हुए आरोपी व्यक्ति के प्रति नरमी बरती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने आरोपी वकील का लाइसेंस जब्त कर उसे निलंबित कर दिया। मगर इस घटना की गंभीरता को समझते हुए ही खुद प्रधानमंत्री सहित अन्य कई बड़े नेताओं ने इसे निंदनीय बताया और चिंता जाहिर की।

हैरानी की बात है कि आरोपी ने अपनी मनमानी करने का जो कारण बताया, उससे यह साफ है कि वकील होने के बावजूद उसकी नजर में कानून या न्याय-प्रणाली की कोई अहमियत नहीं है। दरअसल, सोशल मीडिया पर प्रधान न्यायाधीश के एक बयान की मनमानी व्याख्या करके उसे फैलाया गया और उसके प्रभाव में आए लोगों ने इस पर सोचने-समझने या विवेक का उपयोग करने की जरूरत नहीं समझी। आरोपी वकील ने जिस सनातन के कथित अपमान की बात की, क्या वह उसे आक्रामकता और हिंसा का सहारा लेने का संदेश देता है? इस समूचे मामले में सोशल मीडिया की जैसी भूमिका सामने आई, वह भी बेहद चिंताजनक और बहसतलब है। विवाद के संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश ने साफ कहा था कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन अफसोसनाक है कि उसी मनमानी से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ धारणा बना ली। आजकल सोशल मीडिया पर जिस तरह बिना कुछ सोचे-समझे किसी बात की गलत व्याख्या करने और उसके जरिए व्यापक स्तर पर धारणा बनाने का चलन देखा जा रहा है, उसके घातक नतीजे सामने आ रहे हैं। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिसमें विचार, बहस और विवेक के उपयोग की जगह सिमटती जा रही है और आक्रामकता तथा हिंसक मनोवृत्ति का उभार देखा जा रहा है। यह स्थिति देश के लोकतंत्र और कानून के लिहाज से बेहद चिंताजनक है।

# संवेदनहीनता की हद

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर देने की घटना भयावह और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। इस पूरे प्रकरण में जिस तरह की मानसिकता सामने आई है, उसे किसी भी सभ्य समाज में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। भले ही इस मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सरकार के सामाजिक समानता के दावों और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दावा किया जा रहा है कि घटना के वक्त कुछ पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की मौजूदगी में इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया? क्या वजह रही कि आरोपियों को पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं रहा? क्या अपराध पर काबू पाने के सरकारी दावों की हकीकत यही है?

पुलिस के मुताबिक, जिस व्यक्ति की बर्बर तरीके से हत्या की गई, वह घटना वाली रात अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए पैदल ससुराल जा रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे चोर समझ कर पकड़ लिया। जब वह लोगों के सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाया तो बर्बरता से पिटाई करने के बाद उसे रेलवे स्टेशन तक घसीटकर ले जाया गया और गंभीर हालत में वहीं छोड़ दिया गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल है कि अगर स्थानीय लोगों को उस व्यक्ति पर कोई संदेह था, तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? कानून अपने हाथ में लेकर ऐसी बर्बरता करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? और अगर पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे, तो वे मूकदर्शक बनकर क्यों खड़े रहे? यह घटना राज्य सरकार के उस दावे को भी झुठलाती नजर आती है कि प्रदेश में अब कानून का राज है। इस राज में समाज के दमित-वंचित तबके के लोगों की क्या जगह है? संविधान और कानून हर नागरिक की सुरक्षा, उसके अधिकार और अभिव्यक्ति को समान दर्जा देता है। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

# पटाखों से पर्यावरण पर बढ़ता खतरा

**कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जितना अधिकार दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का है, उतना ही अधिकार उन सभी शहरों के लोगों का भी है, जहां प्रदूषण की समस्या बेहद चिंताजनक बनी रहती है।**

## अखिलेश आर्येंदु

खुशी का इजहार करने के लिए और भी कई तरीके हैं। इनमें संगीत-नृत्य का आयोजन, नगाड़े एवं ढोलक बजाना, लोकगीत गायन या खुल कर नृत्य करना हो सकता है। भूले-बिसरे पारंपरिक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। सहभोज को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि कुछ लोग खुशी की अभिव्यक्ति को केवल पटाखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं। जब पटाखों पर सवाल उठता है, तब कई लोग तर्क देते हैं कि इससे अधिक वाहनों और फैक्टरियों से प्रदूषण फैलता है, तो इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस तर्क में दम है, लेकिन वाहनों का निजी और सार्वजनिक उपयोग कहीं महत्त्वपूर्ण है। इसके समांतर पटाखों के पक्ष में तर्कों को कसौटी पर रखना चाहिए। पटाखे हर तरह से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ही नहीं, खतरनाक भी हैं। अरबों रुपए के आर्थिक नुकसान के साथ हर वर्ष पटाखों से काफी लोगों की मौत हो जाती है। पटाखा फैक्टरियों में इन्हें बनाते समय और पटाखों का इस्तेमाल करने के दौरान कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं।

कुछ समय पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने दिल्ली-एनसीआर में ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही क्यों पटाखों पर प्रतिबंध होना चाहिए? देश में जहां-जहां प्रदूषण की विकट समस्या है, उन शहरों और कस्बे में भी पटाखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? जितना अधिकार दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का है, उतना ही अधिकार उन सभी शहरों के लोगों का भी है, जहां प्रदूषण की समस्या बेहद चिंताजनक बनी रहती है। अदालत के मुताबिक, प्रदूषण के संबंध में जो भी नीति हो, वह अखिल भारतीय स्तर पर एक जैसी होनी चाहिए। इसके पहले पांच मई 2025 को सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती सें लागू करने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि इसका पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई बार सर्वोच्च न्यायालय इस बाबत आदेश जारी कर चुका है। इन आदेशों का कितना पालन हुआ, यह सभी जानते हैं। हालांकि हरित पटाखों को लेकर कुछ हलकों में सकारात्मक धारणा रही है।

पटाखों के इस्तेमाल से अनिद्रा, तनाव, कान के पर्दे फटने और बीमार लोगों के लिए बेहद गंभीर हालात पैदा करने जैसी तमाम परेशानियां सामने आती हैं। इनसे हुई गंदगी, उसके रसायन और बिखरे हुए कागज किसी मुसीबत से कम नहीं होते। मगर विडंबना यह है कि आम आदमी सभी तरह के आदेशों, सरकारी प्रतिबंधों और परामर्श को हमेशा अनदेखा करता आया है। पटाखों पर तमाम पाबंदियों के बावजूद बड़े पैमाने पर पटाखे और सुतली बमों का इस्तेमाल होता है। दीपावली और उसके आसपास एक-दो दिन तक रास्ते में चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई दिनों तक विषैले धुएं का गुबार वातावरण में छाया रहता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। पटाखों की ऐसी लड़ी जलाई जाती है कि सड़क पर यह लोगों के लिए जानलेवा

बन जाती है। सवाल यह है कि ये सब किसकी खुशी के लिए होता है? इस त्योहार पर होड़ देखी जा सकती है कि देखते हैं कौन कितना आगे है पटाखे फोड़ने में। खबरों के मुताबिक, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई परिवार एक हजार से लेकर एक लाख रुपए तक के पटाखे कुछ ही घंटों में जला

> **पटाखों का इस्तेमाल कई जटिल समस्याओं को भी जन्म देता है। पटाखों को जलाने पर इसकी तेज आवाज और इससे निकलने वाले विषैले कण-धुआं बेहद घातक हैं। ये पटाखे चलाने वालों में ही समस्या नहीं पैदा करते, बल्कि वहां मौजूद दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पटाखे जलाने से सल्फर डाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड के अलावा सीसा सहित अन्य रसायन वातावरण में फैल कर कई तरह की गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। ये सभी बेहद जहरीले होते हैं। दिल, दिमाग, यकृत, गुर्दे, खून और हड्डियों तक गंभीर रूप से असर करते हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के साथ मिट्टी और जल प्रदूषण भी होता है।**

देते हैं। सवाल है कि यह त्योहार मनाने का तरीका है या प्रदूषण फैलाने की प्रतियोगिता?

इस पर विचार किया जाना चाहिए कि पटाखों का इस्तेमाल कई जटिल समस्याओं को भी जन्म देता है। पटाखों को जलाने पर इसकी तेज आवाज और इससे निकलने वाले विषैले कण-धुआं बेहद घातक हैं। ये पटाखे चलाने वालों में ही समस्या नहीं पैदा करते, बल्कि वहां मौजूद दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पटाखे जलाने से सल्फर डाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड के अलावा लेड सहित अन्य रसायन वातावरण में फैल कर कई तरह की गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। ये सभी बेहद जहरीले होते हैं। दिल, दिमाग, यकृत, गुर्दे, खून और हड्डियों तक गंभीर रूप से असर करते हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के साथ मिट्टी और जल प्रदूषण भी होता है।

अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े में रोग जैसी बीमारियों की एक वजह पटाखे भी बन गए हैं। हृदयाघात का खतरा और दिल की धड़कन अनियमित होना सामान्य बात है। श्वसन से ताल्लुक रखने वाली समस्याओं और त्वचा संबंधी बीमारियों का जोखिम भी पटाखों से बढ़ जाता है। एक शोध के मुताबिक पटाखे सार्वजनिक जल आपूर्ति को भी जहरीला बना सकते हैं। उस पानी का इस्तेमाल करने वाली आबादी कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकती है। अनुसंधान में इसका वनस्पतियों पर भी बुरे असर का पता लगा है। बताया गया है कि वनस्पतियों के विकास और पैदावार दोनों पर असर पड़ता है। धूल तक जहरीली हो जाती है। पटाखे जमीन के नीचे के पानी को भी प्रदूषित कर सकते हैं। यही नहीं थाइराइड की बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। श्वास नली में विषैले तत्त्व जाने से इसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी होता है।

पटाखों से वायु, ध्वनि, भूमि और जल प्रदूषण होता है। यानी ये पूरे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पटाखों ने आर्थिक नुकसान के साथ शारीरिक तथा मानसिक रोग ही पैदा नहीं किए, बल्कि कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक परंपराओं और विधानों पर भी सवालिया निशान लगते हैं। जिन पटाखों को खुशी मनाने के नाम पर जलाया जाता है, वे हिंसक और शोर-गुल पसंद संस्कृतियों का कभी हिस्सा हुआ करते थे। भारत में मध्यकाल में इनका प्रचार-प्रसार ज्यादा हुआ और देखते-ही-देखते ये भारतीय समाज के हर वर्ग में खुशी का इजहार करने का जरिया बन गए। हमारे यहां किसी भी उत्सव और पर्व-त्योहार का हिस्सा ये नहीं होते थे, क्योंकि इनका यहां निर्माण ही नहीं होता था। शांति, प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता वाली भारतीय संस्कृति में खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य, संगीत समारोह, आम की पत्तियों से बंदनवार सजाने, चित्रकारी करने और अनेक प्रतीकों का प्रयोग किए जाने की परंपरा रही है।

पटाखों पर सरकारी प्रतिबंध और सर्वोच्च अदालत के आदेश का सभी राज्य की पुलिस कितना पालन करवा पाएगी, यह तो दीपावली और दूसरे त्योहारों पर ही पता चलेगा, लेकिन लोगों को जागरूक करने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। जिससे आने वाले समय में पटाखे को लेकर किसी तरह की प्रदूषण संबंधी समस्याएं न पैदा हों। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में पटाखों पर प्रतिबंध महज दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर उस शहर में भी लगाया जाएगा, जहां प्रदूषण की समस्या हमेशा बनी रहती है।

# धूप और छांव

**दुनिया मेरे आगे**

## मेघा राठी

'यात्रा में धूप से कठिनाई नहीं होती, बल्कि छाया से घबराना चाहिए, क्योंकि छाया में पथिक सो जाता है।' यह पंक्ति केवल शब्द नहीं हैं बल्कि जीवन में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन भी हैं। धूप और छाया केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, वे हमारे जीवन के संघर्ष और विश्राम के प्रतीक हैं। जीवन में इन दोनों का संतुलन समझने वाला व्यक्ति ही वास्तविक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकता है। धूप का अनुभव जीवन की चुनौतियों, कठिनाइयों और बाधाओं के रूप में होता है। यह धूप कभी तेज होती है, कभी अप्रत्याशित। पर यह हमारी सहनशीलता, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेती है। एक पथिक अगर धूप में चलता है, तो उसे जलन और थकान होती है, पर उसकी मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा और तेज हो जाती है। इसी तरह, जीवन में आने वाले संघर्ष हमें हमारी छिपी हुई क्षमताओं से परिचित कराते हैं।

संघर्ष केवल कठिनाई नहीं है। यह हमारी ऊर्जा का स्तंभ भी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में कई बार असफल होता है, तो वह निराश हो सकता है। पर यही असफलताएं उसे अपनी रणनीतियों को सुधारने, अपने कौशल को बढ़ाने और धैर्य सीखने का अवसर देती हैं। संघर्ष हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें यह सिखाता है कि असली सफलता धैर्य और प्रयास के माध्यम से ही प्राप्त होती है।

धूप हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में स्थिरता हमेशा सुखद नहीं होती। अक्सर हम चुनौतियों से बचने के लिए आसान रास्ते ढूंढ़ते हैं। मगर यही आसान रास्ता हमें सीमित कर देता है। अगर हम लगातार आराम और स्थिरता में ही रहेंगे, तो हमारी क्षमताओं का विकास नहीं होगा। संघर्ष और कठिनाइयां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें क्या सीखना है और हमें किस दिशा में बढ़ना है। वहीं छाया का महत्त्व भी कम नहीं है। जीवन में विश्राम और ठहराव आवश्यक हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक ऊर्जा फिर प्राप्त करने का समय देती है। पथिक की तरह, जो धूप की तीव्रता से थककर छाया में विश्राम करता है। हमें भी समय-समय पर ठहरकर अपने मन और शरीर को तरोताजा करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि छाया में अधिक समय बिताना आलस्य और निराशा का कारण बन सकता है। अत्यधिक आराम हमारे उद्देश्य से भटका सकता है और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है।

> **अक्सर हम चुनौतियों से बचने के लिए आसान रास्ते ढूंढ़ते हैं। मगर यही आसान रास्ता हमें सीमित कर देता है। अगर हम लगातार आराम और स्थिरता में ही रहेंगे, तो हमारी क्षमताओं का विकास नहीं होगा। संघर्ष और कठिनाइयां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें क्या सीखना है और हमें किस दिशा में बढ़ना है।**

संतुलन बनाए रखना जीवन की कला है। संघर्ष और विश्राम के बीच सही संतुलन बनाने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता पा सकता है। अत्यधिक संघर्ष मानसिक थकान पैदा कर सकता है, वहीं अत्यधिक विश्राम प्रगति को धीमा कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक किसान को दिन में खेत की मेहनत करनी होती है और शाम को विश्राम। अगर वह केवल काम या केवल आराम करे तो फसल सही तरीके से नहीं उग पाएगी। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है।

धूप और छाया के बीच संतुलन का मतलब यह है कि हम संघर्ष को नकारात्मक दृष्टि से न देखें, बल्कि उसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानें। मानसिक दृष्टि से भी यह महत्त्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्ति में मानसिक दृढ़ता और समस्या सुलझाने की क्षमता अधिक विकसित होती है। वहीं केवल आराम और स्थिरता में रहने वाले व्यक्ति में आलस्य और आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। जीवन में संघर्ष और विश्राम का संतुलन हमें यह भी सिखाता है कि किस समय प्रयास करना है और कब ठहराव लेना है। जैसे एक विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करता है, पर बीच-बीच में विश्राम नहीं करता तो उसकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। वहीं अगर वह केवल आराम करता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, तो उसकी सफलता अधूरी रहती है। इसी तरह, जीवन में धूप और छाया दोनों का उचित प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। मसलन, किसी खिलाड़ी की सफलता केवल अभ्यास और मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि पर्याप्त विश्राम और क्षमता को फिर से हासिल करने पर भी निर्भर करती है। अगर वह लगातार प्रशिक्षण लेता रहे और अपने शरीर को आराम न दे, तो उसकी क्षमता प्रभावित होगी। अगर वह केवल आराम करता रहे और अभ्यास नहीं करेगा तो वह कभी खेल में उन्नति नहीं कर पाएगा। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी है।

संघर्ष हमें जीवन की असली ताकत सिखाता है, जबकि विश्राम हमें ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। दोनों का सही प्रबंधन ही व्यक्ति को स्थिर, सशक्त और सफल बनाता है। मसलन, एक लेखक को नए विचारों के साथ लगातार लिखने की आवश्यकता होती है। अगर वह बिना विश्राम के लेखन करता रहे तो उसकी रचनात्मकता कम हो जाएगी।

इस तरह धूप और छाया दोनों हमारे शिक्षक हैं। धूप हमें सिखाती है संघर्षों से लड़ना और आगे बढ़ना। छाया हमें सिखाती है, विश्राम करना और फिर से ऊर्जा प्राप्त करना। इसलिए यह आवश्यक है कि हम धूप का स्वागत करें। उसकी गर्मी और कठिनाइयों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने का साधन मानें। वहीं छाया को केवल ऊर्जा फिर से प्राप्ति के लिए अपनाएं। उसमें डूबने से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखने का यही मंत्र है।

संघर्ष और विश्राम के इस संतुलन को अपनाने वाला व्यक्ति न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनता है, बल्कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से समझ पाता है। उसकी यात्रा न केवल मंजिल तक पहुंचती है, बल्कि रास्ते में उसे जीवन के अनुभवों का भी सटीक ज्ञान मिलता है। यह संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है और हमें यह समझने में मदद करता है।

## भारत का संदेश

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दुनिया के नक्शे पर उसे अपनी जगह बनाए रखनी है, तो आतंकवाद का समर्थन करना बंद करना होगा। भारत अबकी बार 'आपरेशन सिंदूर' जैसा संयम नहीं बरतेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। भारतीय लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करते। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने भी कहा है कि पाक सबूत दिखाए कि उसने भारतीय जेट गिराए। उन्होंने उसके खोखले दावों को महज कहानियां बनाना करार दिया। साथ ही दावे के साथ कहा कि हमने पाक के विमान एफ 16 और जे 17 गिराए हैं। इस तरह पाक के हर झूठ का पर्दाफाश करते हुए वायुसेना ने पाक को आईना दिखा दिया। पाक को समझ लेना चाहिए कि यह देश न अमेरिका के सामने झुकेगा और न चीन के सामने। इसलिए पाक को हर हाल में अपने यहां पल रहे आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, ताकि उसकी संप्रभुता दुनिया के नक्शे पर बनी रहे। साथ ही उसे झूठे दावे करने से भी परहेज करना चाहिए।

*– शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

## भरमाने का खेल

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दरों में हाल ही में हुए बदलाव का कितना लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे प्रधानमंत्री ने बचत उत्सव कहा है। मगर सवाल यह है कि पिछले कई वर्षों में जीएसटी दरों की इतनी वसूली हुई है कि चंद रुपए की राहत अब राहत नहीं लगती। हालांकि उपभोक्ताओं को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है। बाजार में कई तरीके से भरमाने का खेल शुरू हो गया है। दवाइयों से लेकर किराना सामान तक, कर सुधार लागू होने से पहले ही उनकी कीमतों में हेरा-फेरी हो गई। तौल घटाने-बढ़ाने से लेकर अलग-अलग तरह से ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि जीएसटी दरों में सुधार का लाभ उपभोक्ता तक न पहुंच सके। दरअसल, करों में कटौती कर केंद्र सरकार जो कुछ भी राहत देना चाहती है, वह उपभोक्ताओं तक शायद ही पहुंचे। जबकि शासन तंत्र की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं को करों में कटौती का प्रत्यक्ष लाभ मिले।

*– खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर*

## सपनों के सौदागर

'भ्रम के सहारे' (संपादकीय 6 अक्तूबर) में किया गया विश्लेषण सही है। प्रतियोगियों के भविष्य से खिलवाड़ सचमुच दुखद है। मिथ्या प्रचार के सूत्रधार बने अधिकांश कोचिंग संस्थान सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने उपयोगी मार्गदर्शन की जगह बाजारवाद के शिकंजे में छात्रों को जकड़ लिया है। अधिकतर शिक्षा संस्थानों के शिक्षक अपने मूल कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। वे अलग से कमाई के लिए कोचिंग संस्थाओं को सहयोग कर रहे हैं। विद्यालयों में यदि अध्यापन के मापदंडों का पालन हो, तो शिक्षार्थियों को कोचिंग की जरूरत ही नहीं होगी। सत्तर के दशक में ग्रामीण स्तर के युवा प्रतियोगियों ने योग्य और अनुभवी शिक्षकों के सहारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की, लेकिन अब सरकारी नियंत्रण न होने के कारण कोचिंग की चकाचौंध बढ़ गई है। छात्र बुनियादी अध्ययन के बजाय कोचिंग की पाठ्य सामग्री में उलझ कर अभिभावकों की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं।

*– अशोक कुमार, पटना, बिहार*

## उम्मीद की राहें

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) व्यापार को नई दिशा देगा। इसके तहत भारत ने इस समझौते से जुड़े देशों की 80 से 85 फीसद वस्तुओं पर शुल्क शून्य कर दिया है। इससे देश को शुल्क-मुक्त बाजार तक पहुंच मिलेगी। कृषि, सोया और कोयला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से अलग रखा गया है, ताकि घरेलू उद्योगों को नुकसान न हो। एफटीए की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अगले 15 वर्षों में भारत में सौ अरब डालर तक के निवेश की उम्मीद है। हरित ऊर्जा, रसायन, दवाएं, खाद्य प्रसंस्करण और उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी क्षेत्र में समझौते से जुड़े देशों का निवेश भारत की औद्योगिक गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को और मजबूत करेगा। वर्तमान में भारत का व्यापार घाटा है, लेकिन यह समझौता भविष्य में इसे संतुलित करने की दिशा में अहम साबित होगा।

*– विभूति बुपक्या, दिल्ली*

**हमें लिखें, हमारा पता :** edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

## चिंतन

# जहरीली कफ सिरप बनाने वालों को मिले सख्त सजा

आप जिस दवा को जीवनदायनी समझ कर ले रहे हैं, उसमें जहर निकले और मौत का कारण बन जाए तो इसे मुनाफाखोरी के मोह में जीवन से खिलवाड़ कहें, लालफीताशाही का निकम्मापन या कुछ और, क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश में 2 सितंबर से अब तक 19 और राजस्थान में 4 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसमें पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और देशभर में दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग की गई है। तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सिरप बनाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह दवा कांचीपुरम की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन उनकी मानसिकता के बारे में सोचने भर से रूह कांप उठती है, जिन्होंने नौनिहालों की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर दिया। बेचारे छोटे-छोटे बच्चे खांसी की दवा पीकर हमेशा के लिए सो गए। माता-पिता बच्चों को इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल से दवा दिलाएं और फिर कुछ ही घंटों में बच्चों के गुर्दे फेल हो जाएं और उनकी मौत हो जाए, यह भयानक, दर्दनाक और क्रोध पैदा करने वाला विषय है। क्या भरोसे के साथ बीमार बच्चों को सरकारी अस्पताल से दवा दिलवाना, माता-पिता की गलती है। बच्चों के माता-पिता और परिवार का अपनी आंखों के सामने बच्चों का हमेशा के लिए नींद में सो जाते हुए देखना दिल दहलाने वाला है, माता-पिता की चीखें परेशान करने वाली है, लेकिन क्या मासूमों की मौत के इस तांडव से हमारे सरकारी अमले की नींद टूटेगी या फिर वो अब भी पहले की तरह खर्राटें ही लेते रहेंगे। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि भारत में बनने वाले कफ सिरप बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। यह आदेश पंजाब स्थित क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड द्वारा निर्मित गुआइफेनेसिन टीजी सिरप के परीक्षण के बाद दिए थे। अब मध्यप्रदेश में जिस सिरप का इस्तेमाल हुआ, वह तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री में बना था। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग ने इस फैक्ट्री से लिए गए कोल्ड्रिफ सिरप के सैंपल की जांच की, जिसमें 48.6 प्रतिशत डाईएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। यह बेहद जहरीला रसायन है, जो किसी भी फार्मा प्रोडक्ट में तय मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तय है कि पैसों का लालच ही इन मौतों की एकमात्र वजह है और इसलिए जहरीली खांसी की दवा में सस्ती और घटिया रसायन मिलाकर इसे बनाया गया। सरकार ने अब दवाओं का स्टॉक वापस मंगवाकर नष्ट करने जैसे उपाय शुरू किए हैं। जो काम पहले हो जाना चाहिए था, जो जांच पहले हो जानी चाहिए थी, दवाओं का जो गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण पहले हो जाना चाहिए था, उसे अब किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसी कंपनी को तुरंत सील करे, जिसने मासूम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया। दवा उत्पादन की लागत कम और मुनाफा बढ़ाने के लिए कफ सिरप में सस्ते और जहरीले रसायन को प्रयोग किया गया, जिसके चलते बच्चों की मौतों का यह तांडव हुआ। इसकी तुरंत जांच करवाकर इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा से कोई ऐसी हिमाकत ही न करे।

वायु सेना दिवस
डॉ. एलएस यादव

# वायुसेना को और मजबूत बनाना होगा

भारती वायुसेना अब 94वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इन 93 वर्षों के इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब वायुसेना के जांबाजों ने दुश्मनों के दांत खट्टे करके अपनी ताकत का एहसास करवाया। ऑपरेशन सिंदूर में तो वायुसेना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले भी हर चुनौती के समय वायुसेना के विमान दुश्मन पर आफत बनकर टूटे हैं। हमेशा उन्होंने दुश्मनों को तबाह किया और हर युद्ध को जीतने में अहम भूमिका निभाई है। अब जरूरत है वायुसेना को और मजबूती देकर उसे शक्तिमान बनाने की। मिग-21 विमानों के दो स्क्वाड्रनों के रिटायर हो जाने के बाद अब भारतीय वायुसेना की जरूरत 42 स्क्वाड्रनों की जरूरत है इसे हर हाल में जल्द पूरा करना होगा।

आठ अक्टूबर 1932 से धीरे-धीरे प्रगति करती हुई भारतीय वायुसेना अपने 93 वर्ष पूरे कर 94वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इन 93 वर्षों के इतिहास में ऐसे कई अवसर आए जब वायुसेना के जांबाजों ने शत्रु के दांत खट्टे करके अपनी ताकत का एहसास करवाया। ऑपरेशन सिंदूर में तो वायुसेना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले भी हर चुनौती के समय वायुसेना के विमान दुश्मन पर आफत बनकर टूटे हैं। हमेशा उन्होंने दुश्मनों को तबाह किया है और प्रत्येक युद्ध को जीतने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है और चीन के पास यह ताकत कम नहीं है। ऐसे में पाक व चीन सीमा पर चुनौतियां काफी बढ़ी हुई हैं। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 29 स्क्वॉड्रन लड़ाकू विमान हैं। मिग विमानों के रिटायर होने के बाद यह संख्या और घट गई। इस कारण वायुसेना को तत्काल 250 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। चीन व पाकिस्तान से मिलने वाली सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर भारत के पास करीब 45 स्क्वॉड्रन लड़ाकू विमान होने चाहिए।

इन चुनौतियों के मद्देनजर भारत सरकार सीमान्त मोर्चों पर किसी भी दुश्मन को कोई अवसर देना नहीं चाहती। भारतीय वायुसेना की ओर से विमान बेड़ा बढ़ाने के लिए 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को दिया है। इन विमानों की कीमत दो लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इन विमानों का निर्माण फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी और भारतीय एयरोस्पेस कंपनियां मिलकर करेंगी। मेक इन इंडिया राफेल में 60 फीसदी सामान स्वदेशी होगा। रक्षा मंत्रालय इस पर कब निर्णय लेगा यह पता नहीं, लेकिन वायु सेना इस सौदे को जल्द फाइनल करना चाहती है, क्योंकि वायुसेना के विमान लगातार कम होते जा रहे हैं। इससे भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता प्रभावित हो रही है। मिग-21 विमानों के दो स्क्वाड्रनों के रिटायर हो जाने से यह समस्या और बढ़ गई है। हालांकि भारतीय वायुसेना की जरूरत 42 स्क्वाड्रनों की है, लेकिन दक्षिण एशिया की स्थिति और भू-राजनातिक उथल-पुथल को देखते हुए यह संख्या कम है। इन स्थितियों या दो मोर्चों पर युद्ध छिड़ने की स्थिति से निपटने के लिए 45 स्क्वाड्रन होना बेहतर होगा।

भारतीय वायुसेना की इस कमी को दूर करने के उद्देष्य से भारत सरकार ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर भरोसा जताया है। इसके लिए पिछले दिनों ही 180 तेजस मार्क-1ए विमानों की खरीद का आर्डर दिया है। विदित हो कि वर्ष 2021 में 46000 करोड़ रुपये की लागत से 83 तेजस मार्क-1ए विमानों की खरीद कों मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के मुताबिक इनकी आपूर्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। फिर भी सरकार ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2025 में 62,000 करोड़ रुपये की लागत से 97 विमानों की खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इन विमानों को बनाने वाली कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का कहना है कि वह इसी महीने से इन विमानों की आपूर्ति प्रारम्भ कर देगी। दरअसल, इन विमानों की आपूर्ति में देरी का मुख्य कारण अमेरिकी इंजनों की आपूर्ति है। एचएएल ने अमेरिका की जीई कंपनी से '404 इंजन'

लेने का समझौता कर रखा है। इस समझौते के मुताबिक इन इंजनों की आपूर्ति मार्च 2024 में शुरू होनी थी, परन्तु ऐसा नहीं हो पाया। जीई कंपनी ने इस साल पहला इंजन अप्रैल में, दूसरा जुलाई में और तीसरा सितम्बर में दिया। अब तक मात्र तीन इंजनों की ही आपूर्ति हो सकी है। डील के मुताबिक जीई कंपनी को हर माह दो इंजनों की आपूर्ति करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इस देरी से वायुसेना काफी चिंतित है। कुछ समय पहले वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने खुद कहा था कि बीते 40 साल से एचएएल तेजस निर्माण में लगा है, लेकिन अभी तक 40 विमानों की आपूर्ति नहीं कर पाया है। भारतीय वायुसेना के पास तेजस के दो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन हैं। अगर इंजनों की आपूर्ति तेजी से हो तो एचएएल दो से ढाई दर्जन विमानों की आपूर्ति सालाना कर सकता है।

अमेरिकी इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण भारत अब फ्रांस के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाएगा। इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान के बीच संयुक्त परियोजना को सरकार जल्द ही स्वीकृति प्रदान कर सकती है। सफ्रान कंपनी भारत के पांचवीं पीढ़ी के स्वदेषी लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत जेट इंजनों के विकास और उनके निर्माण में मदद करेगी। इससे भारतीय सेना और मजबूत होकर उभरेगी और चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य दोहरे इंजन वाले उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के लिए भारत में 120-किलोन्यूटन इंजन का विकास और उत्पादन करना है। इस काम के लिए सफ्रान कंपनी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करेगी। डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाई जाने इस परियोजना की अनुमानित लागत तकरीबन सात अरब डॉलर होगी। यदि यह मंजूरी मिलती है तो भारत उन विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपने विमान इंजन डिजाइन विकसित करने की क्षमता है। वर्तमान में ऐसे इंजन बनाने की यह तकनीक केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास है।

राफेल लड़ाकू विमान बढ़ाने की तैयारी के साथ ही भारत रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एसयू-57 के भारत में ही बनाए जाने की तैयारी में लगा हुआ है। रूस ने भारत को एसयू-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान की सौ फीसदी तकनीक के साथ-साथ सोर्स कोड दिए जाने का ऑफर दे रखा है। इस ऑफर में रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत इसके लिए तैयार होता है तो एचएएल के जिस प्लांट में सुखोई-30 एमकेआई का उत्पादन होता है उसी प्लांट में एसयू-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान का उत्पादन शुरू हो सकता है। इस काम के लिए रूस की एक टीम जल्द ही एचएएल के नासिक प्लांट का दौरा करने वाली है। एसयू-57 एक बहु-भूमिका वाला लड़ाकू विमान है जो हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले, टोही मिशन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में सक्षम है। इसमें लम्बी दूरी की आर-37 एम मिसाइलें लगी हुई हैं, जिनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लगी हुई हैं, जिनमें उन्नत एवियोनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुपरकंडक्टिविटी का बेहतर संयोजन है। इस बीच अमेरिकी प्रशासन भी भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान के सौदे का ऑफर दे रहा है, लेकिन भारत ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। कुल मिलाकर भारत पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की तरफ आगे बढ़ चुका है। निश्चित है कि अब वायुसेना का विमान बेड़ा बढ़ जाएगा और भारत अपनी भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा और अपनी सीमाओं की पूर्ण रूप से सुरक्षा कर पाएगा।

(लेखक सैन्य विज्ञान विषय के प्राध्यापक रहे हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

## अपराध
डॉ. रमेश ठाकुर

# हेल्थ सिस्टम पर 'कलंक' है 'कफ सिरप' हादसा

कफ सिरप कांड की चर्चाएं इस समय भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हैं। दिल-दहला देने वाली कथित 'कफ सिरप' घटना के गर्भ से उपजे इस अक्षम्य अपराध ने लोगों का ध्यान एकाएक भारत में कुकुरमुत्तों की तरह सक्रिय नकली फार्मा कंपनियों की ओर खींचा है। सरकारों की मिलीभगत से जाली फार्मा कंपनियों का जाल इस समय देश में गुपचुप तरीके से फैला है। नकली दवाइयों के निर्माण में अभी तक चीन ही बदनाम था। पर, 3 वर्ष पहले जब भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित नकली कफ सिरप के पीने से अफ्रीकी देशों में 50 से अधिक जब बच्चों की मौत हुई, तो दुनिया की नजरों में भारत आ गया। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों की जमकर थू थू भी हो रही है। अफ्रीकी बच्चे जब भारत में बनीं कफ सिरप पीकर मरे, तब, केंद्रीय हुकूमत ने जुर्माने सहित तमाम कठोर कदम उठाए थे। यहां तक कि कई फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट और कइयों के लाइसेंस तक रद किए गए थे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वह कंपनियां चुनावी चंदा देकर बहाल हो गई थीं। दुख इस बात का है कि अफ्रीका जैसी घटना की पुनरावृत्ति अब भारत में हुई है। राजस्थान-मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। घटना की तपिश पूरे देश में आग की तरह फैली हुई है। सभी जानते हैं कि जेनेरिक दवाओं के वितरण में बड़ा गोलमाल होता है। ऐसी खबरें भी समय-समय पर आती हैं कि नकली दवा के सेवन से मरीजों की किडनियां खराब हुईं, जिससे उनकी मौत भी हुई। आमजन से लेकर सरकारें भी इस सच्चाई से वाकिफ होती हैं कि दवा क्षेत्र में बड़े माफिया सक्रिय हो चुके हैं, जिनकी पहुंच सीधे-सीधे हुकूमतों तक होती है। इसलिए शिकायतों पर सरकारी तंत्र चुप रहता है। गलतियों पर आंख मूद लेता हैं। थोड़ी बहुत कार्रवाई की बात उठती है तो दवा माफिया कमिशन के नाम पर मोटा माल चढ़ाकर मामले को रफादफा करवा ही लेते हैं। लेकिन उनके ये कृत्य कई बेकसूर मरीजों की जान ले लेते हैं। भारत में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता कई समय से सवालों के घेरे में है। जेनेरिक दवाओं के वितरण में भारत में करीब 15 से 20 हजार औषधि केंद्र संचालित हैं, जबकि, इनकी संख्या इस साल के अंत तक 25 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, लेकिन इनके भीतर कितना गड़बड़झाला है, जिसकी भनक मरीजों को जरा भी नहीं है। फार्मा कंपनियों और कमिशनखोरों को अच्छे से पता होता है कि मरीज दवाओं के नाम पर जहर भी गटक जाएंगे, तो उन्हें पता थोड़ी न चलेगा? दवाइयों के सेवन से हुई मौतों के गुनाहगारों पर कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती? आरोपियों पर दोष तक सिद्ध नहीं होते, उससे पहले ही आजाद हो जाते हैं। इस तंत्र में सभी मिले होते हैं। एक मुनाफा खाता है तो दूसरा कमीशन?

बहरहाल, मौजूदा 'कफ सिरप' के पीने से हुई बच्चों की मौत ने न सिर्फ स्वास्थ्य सिस्टम को हिलाया है, बल्कि पूरा देश सोचने पर मजबूर है। कफ सिरप के नाम पर भारत में बीते कई वर्षों से मासूमों को जहर पिलाया जा रहा है। भांडा तब फूटा जब दर्जन भर के करीब बच्चे मौत के मुंह में समा गए। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मुद्दे को शांत करने और खानापूर्ति के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई और दिखावे की धरपकड़ हो रही है। गलत दवा लिखने वाले चिकित्सकों पर कड़ा एक्शन हो? और मुनाफा कमाने के भूखे केमिस्ट विक्रेताओं पर सरकारी चाबुक चले, ऐसी कल्पना सभी करते हैं।

लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता नहीं? भारत में करीब 3,000 से अधिक दवा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास 10,500 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं। यह उद्योग जेनेरिक दवाओं के निर्माण और आपूर्ति पर केंद्रित है। दवा निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। लेकिन अपने काले कारनामों के चलते ये फार्मा कंपनियां सभी की नजरों में आ गई हैं। भारतीय फार्मा उद्योग का कुल बाजार 2030 तक 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, केंद्र सरकार कफ सिरप कांड को लेकर एक्शन में है। छोटे बच्चों को खांसी में कफ सिरप नहीं देने को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर चुकी है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो किसी की लापरवाही के चलते अपना जीवन गवा गए। क्या उनके परिजनों को महज 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देकर उनके जख्मों को भरा जा सकेगा? शायद कभी नहीं? ऐसे सख्त आदेश पहले भी दिए गए। ऐसे मुद्दे जैसे ही शांत होते हैं, कार्रवाही भी दम तोड़ देती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

## यह मन का कमाल है

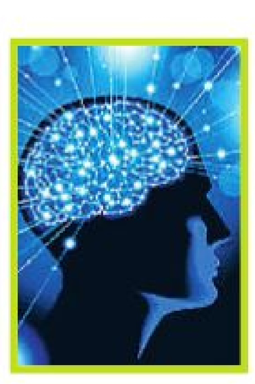

संकलित
**दर्शन**

सिर्फ अनुभव करने से ही यह आएगी। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन से कोई चीज हटाने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। दाढ़ी बनाते समय बहुत से लोग अपना चेहरा काट लेते हैं, क्योंकि वे त्वचा से अधिक निकट दाढ़ी काटना चाहते हैं और रेजर उनकी योजना से अधिक निकट चला जाता है। यह मन का कमाल है। जो चीजें आप चाहते हैं, उनका प्रतिरोध करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि वे आपके अंदर तीव्रता से व्यक्त होंगी। अगर आप कोई चीज नहीं चाहते हैं कि वह हो, तो उसे न होने देने की कोशिश कीजिए। तब वह जरूर होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आप एक ऐसी अवस्था में हैं, जहां आप अपने मन को पहले गियर में डालना चाहते हैं और वह रिवर्स गियर में चला जाता है। चीजें करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए कि अभी मन उसी तरह है, आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं, तो सिर्फ वही चीज घटित होगी। इसलिए मन का प्रतिरोध मन कीजिए, अपने मन की खोज कीजिए। आपका मन कैसे कार्य करता है, उसे समझना किसी बौद्धिक विश्लेषण से नहीं आता। इसकी खोज करनी पड़ती है। अपने शरीर को एक मुद्रा में रखिए और ध्यान दीजिए कि आपका मन किस विशेष ढंग से काम करता है। अपने शरीर को दूसरी मुद्रा में रखिए और ध्यान दीजिए कि आपका मन एक अलग ढंग से काम करता है। अगर आप एक आसन में बैठकर ठीक ढंग से सांस लेते हैं, तो मन विभिन्न अवस्थाओं में चला जाएगा।

## जब मन अशांत हो, इष्टदेव के मंत्रों का जप करें

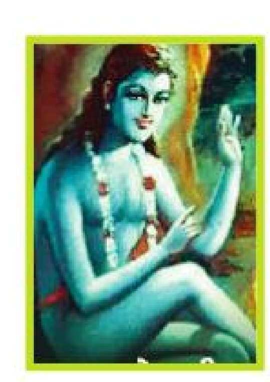

संकलित
**प्रेरणा**

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

## अंतर्मन

### आज की पाती

**क्रिकेट का चमकता सितारा यशस्वी जायसवाल**

भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का दौर जारी है और इस दौर का सबसे चमकता सितारा निस्संदेह यशस्वी जायसवाल हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता तक का प्रतीक बन चुकी है। मुंबई के आज़ाद मैदान के टेंटों से लेकर भारतीय टीम की जर्सी तक का उनका सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। अब भारतीय क्रिकेट में अगली उम्मीद है वनडे क्रिकेट में उनका नया अध्याय। टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी ने पहले ही अपने प्रदर्शन से दुनिया को चौंका दिया है। उनका 171 रनों का डेब्यू शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ और फिर इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेली गई 214 रनों की ऐतिहासिक पारी उनकी क्षमता और परिपक्वता का प्रमाण हैं। इतनी कम उम्र में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। *- प्रदीप जैन, कांकेर*

## ट्रेंड

**सहयोगियों पर हमला निंदनीय**

पश्चिम बंगाल में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करने वाले हमारे पार्टी सहयोगियों पर जिस तरह से हमला किया गया, वह बेहद निंदनीय है। यह तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता है।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

**अतिरिक्त राशि स्वीकृत**

जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ के कारण कई जगह मकान टूट गए। घरों के निर्माण के लिए 1,30,000 की मूल सहायता के साथ 40,000 की अतिरिक्त राशि शौचालय निर्माण के लिए हमने स्वीकृत कर दी है ताकि वे निर्माण कर सकें।
- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री

**पीएम मोदी का आभार**

मैं जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त समय से पहले जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अत्यंत आभारी हूं।
-मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर

**शर्मनाक घटना**

मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया। यह हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। 2014 के बाद जिस तरीके से राजकीय संरक्षण में विभिन्न-विभिन्न माध्यमों से देश में घृणा और हिंसा को नॉर्मलाइज किया गया है यह उसका दुष्परिणाम है।
-तेजस्वी यादव, राजद नेता

**अपने विचार**
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

## करंट अफेयर

# संरा की शांति वार्ताओं से महिलाएं नदारत: गुतारेस

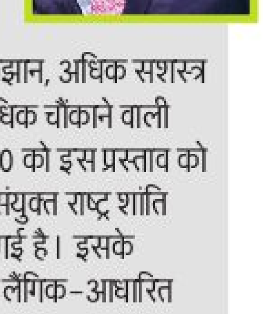

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने मंगलवार को इस बात पर चिंता जताई कि महिलाएं अक्सर शांति वार्ताओं से अनुपस्थित रही हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जब शांति प्रयासों में महिलाओं की समान भागीदारी वाले संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक प्रस्ताव को जारी हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला एजेंसी की प्रमुख ने भी चिंता व्यक्त की है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि 67.6 करोड़ महिलाएं घातक संघर्षों के 50 किलोमीटर के दायरे में निवास कर रही हैं। यह संख्या 1990 के दशक के बाद से सबसे अधिक है। संरा महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, 'पूरी दुनिया में हम सैन्य खर्च में परेशान करने वाले रुझान, अधिक सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ और भी अधिक चौंकाने वाली क्रूरता देख रहे हैं।' गुतारेस ने बताया कि 31 अक्टूबर, 2000 को इस प्रस्ताव को अपनाने के बाद कुछ प्रगति अवश्य हुई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के रूप में वर्दीधारी महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके अलावा महिलाओं ने स्थानीय मध्यस्थता का नेतृत्व किया है, लैंगिक-आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय को आगे बढ़ाया है।

## ऑफ बीट

# आहार की नई सिफारिश में अधिक सब्जियों पर जोर

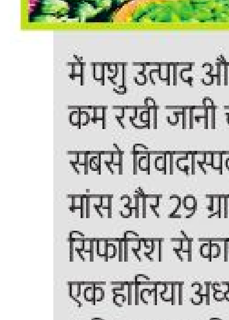

ईएटी-लैंसेट आयोग का कहना है कि पिछले सप्ताह जारी उनके 'प्लैनेटरी हेल्थ डाइट' को अपनाने से दुनिया भर में प्रतिदिन 40,000 समयपूर्व मौतों को रोका जा सकता है और 2050 तक कृषि से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में 15 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है। इस आहार में अधिक सब्जियों, फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे शामिल करने की सिफारिश की गई है, जबकि मांस, मछली, मुर्गी और दुग्ध उत्पाद को सीमित मात्रा में रखा गया है। यदि आप एक थाली की कल्पना करें, तो उसका आधा हिस्सा सब्जियों और फलों (जिनमें सब्जियां अधिक हों) से भरा होना चाहिए। बाकी आधे हिस्से में साबुत अनाज और वनस्पति आधारित प्रोटीन हों। इसमें थोड़ी मात्रा में पशु उत्पाद और स्वस्थ वसा के लिए स्थान है, लेकिन अतिरिक्त चीनी बहुत कम रखी जानी चाहिए। विशेष रूप से मक्खन का कहीं जिक्र नहीं किया गया। सबसे विवादास्पद सिफारिश है-मांस की मात्रा : केवल 14 ग्राम प्रतिदिन लाल मांस और 29 ग्राम प्रतिदिन चिकन। न्यूजीलैंड का पारंपरिक आहार इस सिफारिश से काफी अलग है। लेकिन देश भर में किशोर लड़कियों पर किए गए एक हालिया अध्ययन से संकेत मिलता है कि अब एक बदलाव आ रहा है और अधिकतर लड़कियां वनस्पति आधारित आहार को अपना रही हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 8 अक्टूबर, 2025

दैनिक जागरण
कल्पना विचार का आधार है

## सुरक्षित यातायात

यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित यातायात की आवश्यकता पर ध्यान दिया और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि वे सड़क सुरक्षा के नियम तय करें और ऐसा करते समय पैदल यात्रियों एवं गैर मोटर चालित वाहनों की आवाजाही को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करें। हालांकि अभी ऐसे नियम हैं तो, लेकिन पैदल यात्रियों और गैर मशीनी वाहनों की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता से बाहर हैं। सरकारों को सबकी सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता इसलिए देनी होगी, क्योंकि असुरक्षित यातायात के चलते हर वर्ष जो लाखों लोग जान गंवाते और गंभीर रूप से घायल होते हैं, उनमें एक बड़ी संख्या पैदल यात्रियों और गैर मोटर चालित वाहन चालकों या उनमें बैठे लोगों की होती है। वैसे मोटर चालित वाहनों की सुरक्षा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। भारत में सड़क दुर्घटना में मरने और घायल होने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यह इसलिए कहीं अधिक चिंताजनक है, क्योंकि देश में विश्व के कई देशों की तुलना में कहीं कम वाहन हैं। यदि इसके बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या के मामले में देश शीर्ष पर है तो इसका कारण है सरकारों, यातायात पुलिस और आम लोगों की ओर से सुरक्षित यातायात को महत्व न दिया जाना।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें और उनका स्थानीय प्रशासन सुरक्षित यातायात को लेकर आयोजन करता रहता है। कभी हेलमेट, सीट बेल्ट पहनने, सावधानी से सड़क पार करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और कभी यातायात का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती की जाती है, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसी पहल कुछ ही दिन अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे ही यातायात पुलिस की सख्ती थमती है, यातायात अव्यवस्थित एवं अराजक हो जाता है। इस अराजकता का सबसे अधिक शिकार बनते हैं साइकिल, रिक्शा चालक और पैदल यात्री। इसका कारण यह है कि अनेक स्थानों पर तो साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर चलने की गुंजाइश ही नहीं होती। अपने देश में सामान्य सड़कों की बात कौन करे, राजमार्गों पर भी हर तरह के वाहन चलते दिखते हैं। इस कारण भी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। सड़क दुर्घटनाओं का कारण केवल यातायात नियमों की अनदेखी ही नहीं, सड़कों के रखरखाव में कमी भी है। रही-सही कसर यातायात नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति और यातायात संकेतकों के अभाव या फिर उनके सही तरह से काम न करने से पूरी हो जाती है। यह ध्यान रखा जाए कि यातायात तब सुरक्षित होगा, जब यातायात नियमों का हर कोई पालन करेगा। सुरक्षित यातायात को लेकर किसी खास दिन, सप्ताह या पखवाड़े में ही नहीं, हर दिन सतर्क रहा जाना चाहिए।

## आनलाइन उपस्थिति का मंत्र

यूपी बोर्ड के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक की गई शिक्षकों और छात्रों की आनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था भले अभी आशंकाओं और व्यावहारिक बाध्यताओं के कारण पूरी तरह परवान नहीं चढ़ सकी है, लेकिन इसे लागू कराने के लिए बोर्ड की इच्छाशक्ति प्रशंसनीय है। जुलाई में माध्यमिक विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति के निर्देश बोर्ड ने दिए हैं। इसका अनुपालन शुरू हो गया है। 60 प्रतिशत से ज्यादा विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति अंकित की जा रही है। तय किया गया है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की आनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है, उन्हें परीक्षा केंद्र बनाने में 10 अंकों की वरीयता मिलेगी। तर्क यह है कि जहां शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की विद्यालय में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अंकित हो रही है, वहां केंद्र बनने पर परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगी। अभी तक विद्यालय में सीसीटीवी की सुविधा, स्मार्ट क्लास, परीक्षा परिणाम को ही मानक रखा गया था, अब आनलाइन उपस्थिति को भी जोड़ा गया है। इससे जहां एक तरफ अच्छे कालेजों के बीच प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार होगा और वे शैक्षिक संसाधनों के प्रयोग में दक्षता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, वहीं वे कालेज हतोत्साहित होंगे जो केवल जुगाड़ से परीक्षा केंद्र बनवाकर नकल माफिया की ताल पर थिरकते हैं।

**जहां 75 प्रतिशत उपस्थिति आनलाइन अंकित हो रही है, वहां बोर्ड परीक्षा केंद्र बनने पर परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगी**

# भारत के लिए अवसर और चुनौती

राजीव शुक्ला

**यदि भारत वैश्विक नेतृत्व का चेहरा बनना चाहता है, तो उसे घर के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा**

अवधेश राजपूत

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा संकट बार-बार सामने आता है जिसे 'किंडलबरगर ट्रैप' कहा जाता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री चार्ल्स किंडलबरगर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि जब कोई महाशक्ति वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व छोड़ देती है और कोई नई शक्ति उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे नहीं आती, तो पूरी दुनिया अराजकता के चंगुल में फंस जाती है। बीसवीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन कमजोर हो चुका था, अमेरिका तैयार नहीं था और नतीजा यह हुआ कि महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी आपदाएं दुनिया पर टूट पड़ीं। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ऊब का शिकार और घरेलू स्तर पर विभाजित है। चीन आधा-अधूरा और अविश्वसनीय नेतृत्व पेश कर रहा है। यूरोप अपने संकट में उलझा हुआ है। सवाल यह है कि इस बार वैश्विक व्यवस्था को अराजकता में जाने से कौन बचाएगा। क्या भारत इस खालीपन को भर सकता है?

भारत के पास आज वह पूंजी है, जो शायद किसी और देश के पास नहीं। आधे से अधिक भारतीय तीस वर्ष से कम आयु के हैं। जब पूरी पश्चिमी दुनिया वृद्ध होती आबादी से जूझ रही है और चीन जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है, तब भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति उसे भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बना सकती है। यह युवा शक्ति केवल श्रम नहीं है। यह विचार, नवाचार और डिजिटल ऊर्जा का भी स्रोत है। हालांकि यही युवा पीढ़ी रील, वीडियो और तात्कालिक प्रसिद्धि के आकर्षण में उलझकर अपनी दिशा खो सकती है। अगर युवा शक्ति को जिम्मेदारी की ओर मोड़ी जाए, तो भारत न केवल खुद को, बल्कि पूरी दुनिया को किंडलबरगर ट्रैप से निकाल सकता है।

भारत की ताकत उसकी विविधता है। भाषाओं, पंथों, जातियों और संस्कृतियों की अनगिनत परतों के बावजूद इस देश ने लोकतंत्र को जीवित रखा है। यही माडल दुनिया को चाहिए, क्योंकि पश्चिम में पहचान की राजनीति और राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और चीन अधिनायकवादी प्रणाली थोपना चाहता है। भारतीय प्रवासी समुदाय इस संभावना को गहराई देता है। फ्रांस में ओणम के उत्सव से लेकर ब्रिटेन में गणपति विसर्जन की तस्वीरें भारत की साफ्ट पावर बढ़ाती हैं, जो उसे दूसरों से अलग करती है। फिर भी भारत के सामने सबसे बड़ी कसौटी लोकतांत्रिक विरोधाभास की है।

भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज कहता है, पर घरेलू स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। यदि भारत वैश्विक नेतृत्व का चेहरा बनना चाहता है, तो उसे घर के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा। भरोसेमंद नेतृत्व के बिना आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होता। विश्वास, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था ही दुनिया को अराजकता से बचा सकते हैं। भारत की मौजूदा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बड़े दावे किए हैं जैसे जी-20 की अध्यक्षता और 'विश्वगुरु' बनने का सपना, लेकिन देश के भीतर कई कमजोरियां इस दावे को कमजोर करती हैं। चुनावी प्रक्रिया में पैसे का बढ़ता दबाव, मीडिया की आजादी पर उठते सवाल और स्वतंत्र संस्थाओं पर राजनीतिक प्रभाव देश की लोकतांत्रिक छवि धूमिल करते हैं।

जलवायु बदलाव से निपटने के वादे भी अक्सर बड़े उद्योगों को रियायत देने में खो जाते हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सरकार का खर्च अभी भी बहुत कम है। विदेश नीति में भी कभी-कभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अचानक बदलाव दिखता है, जिससे भरोसे की कमी महसूस होती है। यदि सरकार घर के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत नहीं करती, तो दुनिया में भारत की नेतृत्वकारी छवि सिर्फ भाषणों तक सिमट जाएगी।

भारत की सबसे बड़ी संभावना उसका टेक्नो-डेमोक्रेटिक माडल है। यूपीआइ ने दिखा दिया कि डिजिटल लेनदेन को कैसे आम आदमी के लिए सहज और सुलभ बनाया जा सकता है। आधार ने पहचान को डिजिटल रूप दिया, कोविड के दौरान कोविन प्लेटफार्म ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वास्थ्य प्रबंधन में तकनीक का उपयोग पारदर्शी और कुशल तरीके से किया जा सकता है। यह सब केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं थीं, यह उस सोच का परिचय थी, जिसमें तकनीक को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि भारत यही माडल दुनिया को दे, तो वह चीन के तकनीकी अधिनायकवाद और पश्चिम के लाभ केंद्रित पूंजीवाद के बीच एक नया संतुलित विकल्प पेश कर सकता है। हालांकि केवल विकल्प पेश करना पर्याप्त नहीं। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वैश्विक व्यवस्था को केवल किसी के आर्थिक हितों की नहीं, बल्कि सार्वजनिक वस्तुओं की जरूरत होती है। जैसे जलवायु वित्त, महामारी प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और मानवीय संकटों में सहयोग। भारत ने हाल में यह दिखाने की कोशिश की है कि वह इस भूमिका के लिए तैयार है, पर ऐसे प्रयास निरंतरता मांगते हैं।

अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और साइबर स्पेस में संघर्ष भविष्य का सबसे बड़ा तनाव बनेगा। जलवायु परिवर्तन और प्रवासन से पैदा हुए संकट इस तनाव को और गहरा करेंगे। आपूर्ति श्रृंखलाएं टूटने पर विकासशील देशों को बड़ा झटका लगेगा। यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध से भी जटिल हो सकती है, क्योंकि अब संघर्ष केवल सैन्य या विचारधारा का नहीं होगा, बल्कि तकनीक, स्वास्थ्य, जलवायु और आर्थिकी एक साथ उलझेंगे। यही समय है जब भारत खुद को तीसरे ध्रुव के रूप में पेश करे। जिस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बीसवीं सदी में एशिया-अफ्रीका को एक अलग आवाज दी, वैसे ही इस सदी में भारत तकनीक और लोकतंत्र के एजेंडे पर दुनिया को एक नया विकल्प दे सकता है। इसके लिए उसे केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक नेतृत्व दिखाना होगा। इतिहास हमेशा मौके की कसौटी पर नेताओं और राष्ट्रों को परखता है।

(लेखक कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)
response@jagran.com

# आत्मनिर्भरता की आत्मघाती बाधा

राजीव सचान

**अखाद्य वस्तुओं की बात तो दूर रही, हम दवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर पाने में नाकाम हैं**

इन दिनों विषाक्त कफ सीरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत का मामला चर्चा में है। हर तरफ आक्रोश है और उसके चलते जांच एवं कार्रवाई की बातें हो रही हैं। क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं। 1986 में मुंबई में विषाक्त कफ सीरप से 14 बच्चों की जान गई थी और दिल्ली में 33 बच्चों की। इसके बाद 2020 में जम्मू में 12 बच्चों की मौत हुई। हर बार सब कुछ ठीक करने की बातें की गईं, लेकिन स्थितियां नहीं बदलीं। 2022 में भारतीय दवा कंपनियों की ओर से बनाई गई कफ सीरप से गांबिया और फिर उज्बेकिस्तान में कई बच्चों की मौत हुई। इन मौतों का संज्ञान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लिया। इन मामलों के कारण भारत की दवा कंपनियों की बदनामी भी हुई। माना जा रहा था कि इस बदनामी के कारण विषाक्त कफ सीरप बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाली सरकारी एजेंसियां अपना काम सही तरह से करेंगी, पर नतीजा ढाक के तीन पात वाला रहा।

गांबिया और उज्बेकिस्तान को कफ सीरप सप्लाई करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई तो हुई, पर ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जो नजीर बनती और विषाक्त कफ सीरप बनने का सिलसिला थमता। ऐसा ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सीरप सप्लाई करने वाली दवा कंपनी के साथ हो तो हैरानी नहीं, क्योंकि इस सीरप में विषाक्त रसायन के प्रयोग को लेकर विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया और उनकी गुणवत्ता की परख करने वाली सरकारी एजेंसियां और सरकारें कुछ भी दावा करें, यह काम सही तरह नहीं होता और इसका प्रमाण यह है कि आए दिन दवाओं के सैंपल फेल होने की खबरें आती हैं। पिछले महीने खबर आई थी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों की 94 दवाओं के सैंपल फेल हुए। जांच में तीन दवाएं नकली भी निकलीं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन हर माह ड्रग अलर्ट जारी करता है। अगस्त के ड्रग अलर्ट के अनुसार हिमाचल की 31 दवा कंपनियों की 38 दवाएं गुणवत्ता के पैमाने पर खरी नहीं उतरीं। इसी ड्रग अलर्ट के अनुसार उत्तराखंड, पंजाब और मध्य प्रदेश की दवा कंपनियों में बनीं 56 दवाओं के सैंपल भी फेल हुए। जुलाई के ड्रग अलर्ट के अनुसार कुल 143 दवा नमूने फेल पाए गए। जून के ड्रग अलर्ट में कुल 188 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इनमें हिमाचल, गोवा और महाराष्ट्र की दवा कंपनियों की दवाएं थीं। इस पर संतोष नहीं जताया जा सकता कि ये सैंपल बैच विशेष के होते हैं और उन्हें हटाने को कहा जाता है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कि दोयम दर्जे की दवाओं को हटाने के निर्देश जारी करने के पहले वे मरीजों तक नहीं पहुंच जाती होंगी। चूंकि हिमाचल फार्मा कंपनियों का गढ़ है, इसलिए दवाओं के फेल सैंपल के मामले में यहां की कंपनियों का नाम खूब आता है, पर सच यह है कि शेष देश की दवा कंपनियों के सैंपल भी फेल होने का सिलसिला कायम है। भारत ने जेनेरिक दवाओं के निर्माण में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन यदि दोयम दर्जे की दवाएं बनती रहीं तो यह पहचान खतरे में पड़ सकती है।

छिंदवाड़ा में जब्त की जाती कफ सीरप। एनएनआइ

क्या हम केवल दवाओं की गुणवत्ता ही बनाए रख पाने में नाकाम हैं? नहीं। दवाओं के साथ-साथ खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों की गुणवत्ता के मामले में भी हमारी स्थिति दयनीय है। डिब्बाबंद खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में रहती है। उनके निर्माण में मानकों का उल्लंघन होता ही रहता है। कई बार तो उनमें विषाक्त अखाद्य वस्तुओं की भी मिलावट की जाती है, लेकिन मुश्किल से ही कोई मिलावटखोर दंडित होता है। जिस तरह दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली सरकारी एजेंसियां और ड्रग इंस्पेक्टर अपना काम ले-देकर करते हैं, उसी तरह खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता की परख करने वाली सरकारी एजेंसियां और फूड इंस्पेक्टर भी। सरकारी तंत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार का ही यह नतीजा है कि भारत में न तो दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित है और न ही खाद्य एवं पेय पदार्थों की। दूध, खोया, मिठाई, मसालों आदि में तो मिलावट की आशंका बनी ही रहती है और अक्सर यह सही पाई जाती है।

दवाएं हों या खाद्य एवं पेय पदार्थ या फिर अखाद्य वस्तुएं, अपने देश में सबके निर्माण के लिए मानक बने हुए हैं और सबकी गुणवत्ता परीक्षण के नियम-कानून हैं, लेकिन उनका सही तरह पालन नहीं होता। जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार होना एक अलिखित नियम सा बन गया है। इसी तरह जहां कहीं भी सरकारी अनुमति, संस्तुति, परीक्षण आदि की आवश्यकता होती है, वहां भी मानकों की अनदेखी के साथ नियम-कानूनों का उल्लंघन होता है। हैरानी नहीं कि बहुत कम भारतीय उत्पाद ऐसे हैं, जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चूंकि हमारे उत्पाद विश्वस्तरीय नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए वे विश्व बाजार में अपनी छाप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसी कारण हम आत्मनिर्भर बनने के अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। स्वदेशी के सहारे स्वावलंबी बनने की यात्रा तब पूरी होगी, जब हमारे हर तरह के उत्पाद भरोसेमंद होंगे। अच्छा हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगने का थोथा दावा आत्मनिर्भरता की राह की आत्मघाती बाधा है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

## ज्ञान की आकांक्षा

ज्ञानेप्सा दो शब्दों 'ज्ञान' एवं 'इप्सा' के संयोग से बना है। ज्ञान का अर्थ है जानना एवं इप्सा का अर्थ है-इच्छा अथवा आकांक्षा। इस प्रकार, ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा ही ज्ञानेप्सा कहलाती है। ज्ञानेप्सा उस आंतरिक लालसा की द्योतक है, जो मनुष्य को सत्य, तर्क और अनुभव के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। ज्ञानेप्सा ही वह प्रेरक शक्ति है, जो अंधकार में भी प्रकाश खोजने को उन्मुख करती है एवं मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान तथा असत्य से सत्य की ओर अग्रसर करती है। यह जानने की सामान्य प्रवृत्ति अर्थात जिज्ञासा से हटकर सत्य के प्रति एक गहन और सतत आकांक्षा है।

जब हम चहुंओर, स्वयं अपने अस्तित्व अथवा किसी विषय विशेष की गहराइयों में उतरने की उत्कंठा महसूस करते हैं, तब उस स्थिति में ही ज्ञानेप्सा का उदय होता है। यह वस्तुतः जिज्ञासा से एक कदम आगे की अवस्था है। जिज्ञासा प्रश्न को जन्म देती है, जबकि ज्ञानेप्सा उत्तर प्राप्ति हेतु उचित कर्म एवं साधना का क्रियान्वयन करती है। ज्ञानेप्सा में व्यक्ति केवल जानना ही नहीं चाहता, अपितु अनुभव करना चाहता है एवं सत्य के साथ एकात्म होना चाहता है। मनुष्य के जीवन का विकास तभी संभव है, जब उसके भीतर ज्ञान की पिपासा बनी रहे। जीवन में प्रगति एवं आत्मबोध का आधार ज्ञानेप्सा ही है। ज्ञानेप्सा के अभाव में जीवन जड़वत हो जाता है। न उसमें खोज का आनंद होता है, न ही सृजन की लय। यह ज्ञानेप्सा ही है जो छात्र को अध्ययन के लिए प्रेरित करती है, विज्ञानियों को प्रयोग करने को बाध्य करती है और साधक को सत्य की खोज में तप करने का साहस देती है। जब व्यक्ति ज्ञान के प्रति सचेत होता है, तो उसके विचार, व्यवहार और निर्णय सभी में विवेक का प्रकाश झलकता है। भारतीय संस्कृति में सर्वत्र ज्ञानेप्सा का महत्व झलकता है।

प्रेरणा अवस्थी

# आज भी प्रासंगिक है गांधी का शिक्षा-दर्शन

सुधीर कुमार

**गांधीजी ने नई तालीम योजना के जरिये रोजगारपरक शिक्षा की वकालत की थी**

1937 में महात्मा गांधी ने देश में बुनियादी शिक्षा में सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जो न केवल औपनिवेशिक काल में प्रासंगिक रही, बल्कि बदलते समय एवं समाज के संदर्भ में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। यह गांधीजी के शैक्षिक विचारों एवं चिंतन का अभिव्यक्त स्वरूप था, जिसे देश में न केवल शैक्षिक उन्नति बल्कि शैक्षिक-आर्थिक आत्मनिर्भरता के विकास के लिए प्रस्तुत किया था। दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद गांधी जेल से छूटे तो वे अपने मित्र जमनालाल बजाज के वर्धा स्थित मगनबाड़ी में रहने लगे। 1934 से 1936 तक गांधी यहीं पर रहे। इस दौरान उन्होंने देश में शिक्षा सुधार के लिए अपना चिंतन जारी रखा। जमनालाल बजाज उन दिनों वर्धा मारवाड़ी एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष थे, जो 1937 में समिति अपनी रजत जयंती मनाने की तैयारी कर रही थी। सोसायटी के सचिव श्रीमन्नारायण का विचार था कि इस अवसर पर गांधीजी के शैक्षणिक विचारों पर चर्चा के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाए। अतः एक अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन वर्धा में 22-23 अक्टूबर, 1937 को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए एक योजना पेश की, जिसे नई तालीम, वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना भी कहा गया। इसमें सात साल की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा, दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा और आत्मनिर्भर शिक्षा का उल्लेख किया गया था।

आज युवाओं के पास कई तरह की डिग्रियां हैं, परंतु रोजगार नहीं हैं, जबकि लगभग नौ दशक पहले गांधीजी ने नई तालीम योजना के जरिये रोजगारपरक शिक्षा की वकालत की थी। सीखने के दौरान कमाई गांधीजी की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का आदर्श वाक्य था। नई तालीम समानता पर आधारित कम खर्च वाली शिक्षण प्रणाली है, जिसके जरिए सभी बच्चों को शिक्षा देना संभव है। जबकि वर्तमान की बाजारीकृत शिक्षा ने समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया है। महंगी शिक्षा के कारण एक बड़ी आबादी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है। नई तालीम के तहत एक बच्चा 14 साल की अवस्था में स्कूल से प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर बनकर एक कमाऊ सदस्य के तौर पर घर लौटता था, जबकि आज की शिक्षा का इस पर कोई जोर नहीं है।

बहरहाल, नई तालीम ने केवल देश की शिक्षा नीतियों को ही दिशा नहीं दी, अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में कामयाब रहा है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में निहित चौथा लक्ष्य समावेशी शिक्षा तथा आठवां लक्ष्य आर्थिक विकास की बात करता है, जो नई तालीम से प्रत्यक्ष रूप से संगत नजर आता है। निःसंदेह नई तालीम शिक्षित बेरोजगारी में कमी और बालश्रम उन्मूलन में सहायक बन सकता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

### जनता में जागरूकता जरूरी

'चुनाव मैदान में बिहार' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। लगभग सभी राजनीतिक दल हर चुनाव में लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं। ऐसी कुछ घोषणाएं मुफ्तखोरी का चलन बढ़ाती हैं। मुफ्तखोरी तमाम समस्याओं को जन्म देने के साथ ही विकास में अवरोध भी खड़े करती है। कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने सराहनीय पहल की है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्र में लोकलुभावन घोषणाओं के साथ यह भी बताना होगा कि इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वित्तीय बंदोबस्त कहां से किया जाएगा? हालांकि इसे व्यवहार में लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक दल कोई न कोई तोड़ निकाल लेंगे। इसलिए चुनावी दौर में लोगों को उसी तरह समझदारी बरतनी होगी, जितनी वे अपने लिए किसी कीमती सामान को खरीदने के लिए बरतते हैं। विज्ञापन की चकाचौंध में आकर खरीदारी से अक्सर बाद में पछताना भी पड़ जाता है। इसलिए राजनीतिक वादों को भी विवेक की कसौटी पर कसना जरूरी है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

### आयकर मुक्त हो पेंशन

पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उस कर्मयोगी जीवन का सम्मान है जो किसी व्यक्ति ने देश और समाज की सेवा में समर्पित किया है। यह बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता और गरिमा का आधार है। ऐसे में पेंशन पर आयकर वसूली न केवल आर्थिक अन्याय है, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी अनुचित है।

## मेलबाक्स

सेवा काल में हर सरकारी कर्मचारी नियमित रूप से आयकर देता है। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन उसी वेतन का हिस्सा है, जिस पर पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका होता है। दूसरी ओर, आज महंगाई, दवाओं की बढ़ती कीमतें और जीवन यापन की लागत पहले से कई गुना बढ़ चुकी हैं। पेंशनर अपनी पेंशन से दवा, बिजली, किराया और दैनिक जरूरतों पर पहले ही अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सीमित पेंशन से आयकर वसूलना दोहरी मार है। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की आय घट जाती है, पर खर्च कम नहीं होते। स्वास्थ्य पर बढ़ता बोझ बुजुर्गों की सबसे बड़ी चुनौती है। जब किसी की आय का बड़ा हिस्सा इलाज में चला जाता है, तब उस पर कर लगाना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। दुनिया के कई देश-जैसे जापान, कनाडा और न्यूजीलैंड अपने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट या पूर्ण मुक्ति देते हैं। भारत जैसे कल्याणकारी लोकतंत्र में भी ऐसा कदम बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। सरकार को चाहिए कि पेंशन को 'जीवनभर की सेवा का प्रतिफल' मानते हुए इसे आयकर से पूरी तरह मुक्त करे। ऐसा कदम न केवल लाखों बुजुर्गों को राहत देगा, बल्कि यह भी संदेश देगा कि देश अपने सेवक नागरिकों के योगदान को सम्मानपूर्वक याद रखता है।

डा. मदनलाल गांगले, रतलाम (मध्य प्रदेश)

### लोकतंत्र का पर्व

बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मगर सवाल यह है कि कितने प्रतिशत मतदाता यह जानते हैं कि लोकतंत्र में वास्तविक शासक वही है। चूंकि आबादी बड़ी है। इसलिए वे अपने शासन करने के अधिकार को जनप्रतिनिधियों के हाथों पांच साल के लिए हस्तांतरण करते हैं। अधिक मतदान प्रतिशत को लेकर जो विज्ञापन कराए जाते हैं। उसमें इन बातों को शामिल करने से मतदाता अपने मत का महत्व समझेगा। यद्यपि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही होता है तथापि मतदाता लुभावने वादे-घोषणाओं के फेर में फंस जाते हैं या फिर तात्कालिक लोभ-लालच के फेर में अपने हितों की बलि चढ़ा देते हैं। लिहाजा चुनाव उन्हें अवसर देता है कि वे अपने हितों के अनुरूप शासकों का संजीदगी से चुनाव करें। इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मतदाता बढ़चढ़कर मतदान में भाग लें।

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक ( राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

*********

# { संपादकीय }

नई दिल्ली, बुधवार 08 अक्टूबर 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

## लोकतंत्र को कुचलने में गोडसे का रवैया

देश में दलितों को अधिकारसंपन्न होते देख सवर्णों का एक बड़ा तबका किस कदर आहत है, इसका बड़ा उदाहरण सोमवार को सामने आया, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर एक वकील ने जूता फेंक दिया। इस जगह पर हमने कल भी लिखा था कि भारत की आजादी के बाद से किसी मुख्य न्यायाधीश का या न्यायपालिका का इस तरह अपमान इससे पहले कभी नहीं हुआ। उस आरोपी वकील को पुलिस ने फौरन पकड़ लिया। लेकिन यह इस घटना का पटाक्षेप नहीं था। मुख्य न्यायाधीश गवई ने आरोपी पर किसी तरह का मामला दर्ज करने से साफ इंकार कर दिया और यह भी कहा कि वे ऐसी घटनाओं से विचलित नहीं होते हैं, जिसके बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। अब उसका बाकायदा साक्षात्कार समाचार एजेंसी एएनआई ने लिया, जिसमें राकेश किशोर ने खुलकर कहा कि उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। बल्कि इस कृत्य को भगवान का आदेश उसने बता दिया।

भारतेंदु हरिश्चंद्र होते तो भारत दुर्दशा का दूसरा हिस्सा लिखते और फिर कहते कि हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लेकिन भारत की ऐसी दुर्दशा होते देखना शायद जनता की मजबूरी बन चुकी है। जहां प्रधानमंत्री खुद को अवतरित बताएं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश कहें कि उन्होंने राम मंदिर पर फैसला देवी की मूर्ति के सामने बैठकर लिया और एक आरोपी कहे कि देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति पर जूता उछालने के लिए उसे भगवान ने कहा है।

जब सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है, तो फिर सरकार की भी क्या जरूरत है। वैसे भी सरकार अपना दायित्व पूरा करते नहीं दिख रही है। जिस घटना पर विपक्ष ने फौरन निंदा करते हुए प्रतिक्रिया दे दी, उस पर प्रधानमंत्री ने कई घंटे सिर्फ ये कहने में लगा दिए कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना से हरेक भारतीय आहत है। क्या मोदीजी का सूचना तंत्र वाकई इतना कमजोर है कि उन्हें हर बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया देने में कई घंटे लग जाते हैं। पुलवामा हमला, पहलगाम हमला दोनों आतंकी घटनाओं में श्री मोदी ने देर से जवाब दिया और अब न्यायपालिका पर हमले में उनका रवैया ढीला ढाला रहा। इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत से दक्षिणपंथी लोगों ने श्री गवई के लिए अपमानजनक ट्वीट करने शुरु कर दिए। कुछ यूट्यूबर्स का सितंबर आखिरी में रिकार्ड किया एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे खुलकर जस्टिस गवई के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और परोक्ष तौर पर हिंदुओं से आह्वान कर रहे हैं कि उन पर हमला हो। इस वीडियो में तीन कथित पत्रकार चर्चा कर रहे हैं, जिनमें एक कहता है कि, 'मैं एक गांधीवादी हूं। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। अगर मैं करता, तो मैं कहता, 'देखो, अगर गवई जी झगड़ा करते हैं, तो वे कचहरी में रहते हैं, और वहां हिंदू वकील हैं। कम से कम एक हिंदू वकील को गवई जी का सिर पकड़कर दीवार पर ज़ोर से मारना चाहिए, ताकि उसके दो टुकड़े हो जाएं। लेकिन मैं हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता।' वहीं दूसरा पत्रकार ने जस्टिस गवई की कार को घेरने का भी सुझाव दिया था। और इस चर्चा में यह बात भी कही गई कि '2 अक्टूबर आ रहा है। गोडसे ने जो किया वह तुम्हारी क्षमता से परे है, लेकिन तुम गांधी बन सकते हो। गवई के चेहरे पर थूकने की आईपीसी की धारा के तहत अधिकतम सज़ा क्या है? छह महीने से ज़्यादा नहीं? बस इतना ही। हिंदू तो ऐसा भी नहीं कर सकते?'

यह पूरी चर्चा सीधे तौर पर मुख्य न्यायाधीश के लिए हिंसात्मक विचारों का प्रसार कर रही है, जो संविधान और न्यायपालिका दोनों की अवमानना के समान है, लेकिन आश्चर्य है कि यह वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है। इसी तरह आरोपी वकील राकेश किशोर, जिसे कायदे से सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वह न केवल अपने कृत्य को सही बता रहा है, बल्कि अदालत में फैसलों को धार्मिक नजरिए से देखने का आग्रह भी कर रहा है। एएनआई को दिए साक्षात्कार में राकेश किशोर ने कहा कि 'मैं बहुत ही ज्यादा आहत हुआ कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी ने पीआईएल दाखिल की थी और गवई साहब ने उसका पहले तो मजाक उड़ाया। लेकिन दूसरे धर्मों के मामले में ऐसा नहीं होता। जैसे हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले स्टे लगा दिया। यह आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपूर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया कि आपने माहौल कर दिया। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से संबंधित कोई मामला आता है तो उसके ऊपर वो जरूर कोई ना कोई ऐसा आर्डर पास करते हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।' राकेश किशोर ने कहा कि ये सब क्यों करना पड़ा ये जरूर सोचने वाली बात है। पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है। मैं भी कोई कम पढ़ा-लिखा नहीं हूं और गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नशे में था और मैंने कोई गोलियां खा रखी थीं। उन्होंने एक्शन किया और ये मेरा रिएक्शन था। ना ही मुझे कोई अफसोस है कि क्या हुआ और क्या नहीं।'

ये भाषा बिल्कुल गोडसे वाली है, जिसमें अदालत में गोडसे गांधीजी की हत्या के पीछे न केवल कारण दे रहा है, बल्कि उसे सही भी ठहरा रहा है। गोडसे को महान बताने वाले लोग उन्हीं कारणों को गिनाते हैं। अब यही रवैया न्यायपालिका के अपमान, मुख्य न्यायाधीश पर हमले पर भी अपनाया जा रहा है।

# आजादी के संघर्ष में संघ की भूमिका और मोदी का झूठ

## स्वतंत्रता आंदोलन और संघ-1

जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का एक व्यंग्य वाक्य है- 'आदमी से उसका झूठ मत छीनो, क्योंकि वही उसके जीने का मूल आधार है। जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही आदमी भी झूठ के बगैर नहीं जी सकता।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीत्शे के इस कथन से परिचय हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन वे इस कथन को सार्थक करते हैं। उनके बारे में अब यह पूर्णत: स्थापित हो चुका है कि वे हर मौके पर सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने बचपन के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में और अपने वैवाहिक जीवन के बारे में ही गलत जानकारियां बयान नहीं कीं, बल्कि वे अपनी सरकार के काम-काज को लेकर भी हर मामले में पूरे आत्मविश्वास के साथ बेधड़क झूठ बोलने से कतई परहेज नहीं करते हैं।

पिछले सप्ताह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौवें स्थापना दिवस पर अपने एक ब्लॉग के जरिये मोदी ने जाहिर कर दिया कि जैसे ब्रह्मांड का कोई ओर-छोर नहीं है, वैसे ही उनके झूठ बोलने की भी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपने ब्लॉग में भारत के स्वाधीनता संग्राम में आरएसएस की भूमिका को लेकर ऐसी-ऐसी बातें लिखीं, जो कि आज तक आरएसएस के किसी सरसंघचालक ने भी कहने का साहस नहीं किया। यह स्थापित तथ्य है कि आजादी के संघर्ष में संघ की रंचमात्र भी भूमिका नहीं थी। मगर मोदी ने बाकायदा लिखा, 'डॉ. हेडगेवार समेत कई स्वयंसेवकों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कितने ही स्वाधीनता सेनानियों को संघ ने संरक्षण दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर काम किया।'

यह सही है कि आरएसएस के संस्थापक और पहले सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार आजादी की लड़ाई के दौरान दो बार जेल गए थे लेकिन वे संघ के मुखिया के रूप में नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में गए थे। हेडगेवार की आधिकारिक जीवनी (संघ-वृक्ष के बीज: डॉ .केशव बलिराम हेडगेवार) में लिखा है कि उन्हें पहली बार एक साल की जेल आरएसएस के गठन से पहले 1920-21 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुई थी। यह जीवनी मराठी में चंद्रशेखर परमानंद भिशीकर ने लिखी है।

हेडगेवार की दूसरी जेल यात्रा 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान हुई लेकिन उसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। उनकी जीवनी के मुताबिक हेडगेवार ने सब जगह सूचना भिजवाई थी कि 'संघ इस सत्याग्रह में भाग नहीं लेगा, किन्तु जिन्हें व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लेना हो, उन्हें मनाही नहीं है।' इसका मतलब है कि संघ में जिम्मेदारी वहन करने वाला कार्यकर्ता सत्याग्रह में भाग नहीं ले सकता था। जीवनी में लिखा है कि डॉक्टर साहब खुद गांधीजी के डांडी नमक सत्याग्रह में निजी तौर पर शामिल हुए लेकिन सरसंघचालक का पद छोड़कर। हेडगेवार की यह जीवनी इसके पीछे के गुप्त उद्देश्य का खुलासा करती

अनिल जैन

**जिस तरह भारत-विभाजन की विभीषिका इतिहास में अमिट है और जिसे कोई भुला या झुठला नहीं सकता, उसी तरह इस हकीकत को भी कोई नकार या नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मौजूदा सत्ताधीशों के वैचारिक पुरखों का भारत के स्वाधीनता संग्राम से कोई सरोकार नहीं था। यही नहीं, धर्म पर आधारित दो राष्ट्र-हिंदू और मुसलमान का विचार भी सबसे पहले उन्होंने ही पेश किया था।**

है कि, 'ऐसा विश्वास भी डॉ. साहब के मन में था कि वहां जो स्वातंत्र्य प्रेमी, त्यागी एवं प्रतिष्ठित मंडली साथ में रहेगी, उनसे चर्चा कर उन्हें संघ के काम से जोड़ा जा सकेगा।' जाहिर है कि हेडगेवार देशप्रेम की वजह से नहीं, बल्कि संघ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शामिल करने के मकसद से नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे।

दरअसल जिस तरह भारत-विभाजन की विभीषिका इतिहास में अमिट है और जिसे कोई भुला या झुठला नहीं सकता, उसी तरह इस हकीकत को भी कोई नकार या नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मौजूदा सत्ताधीशों के वैचारिक पुरखों का भारत के स्वाधीनता संग्राम से कोई सरोकार नहीं था। यही नहीं, धर्म पर आधारित दो राष्ट्र-हिंदू और मुसलमान का विचार भी सबसे पहले उन्होंने ही पेश किया था, जिसे बाद में मुस्लिम लीग ने भी अपनाया और उसी के आधार पर उसने पाकिस्तान हासिल किया।

भारत के मौजूदा सत्ताधीशों और उनके राजनीतिक संगठन यानी भाजपा की गर्भनाल संघ और हिंदू महासभा से जुड़ी हुई है। इन दोनों ही संगठनों ने स्वाधीनता संग्राम से न सिर्फ खुद को अलग रखा था बल्कि खुलकर उसका विरोध भी किया था। यही नहीं, 1942 में शुरू हुए 'भारत छोड़ो आंदोलन' के रूप में जब स्वाधीनता संग्राम अपने तीव्रतम और निर्णायक दौर में था, उस दौरान तो उस आंदोलन का विरोध करते हुए संघ और हिंदू महासभा के नेता पूरी तरह ब्रिटिश हुकूमत की तरफ़दारी कर रहे थे।

वैसे स्वाधीनता आंदोलन से अपनी दूरी और मुसलमानों के प्रति अपने नफरत भरे अभियान को संघ ने कभी छुपाया भी नहीं। हेडगेवार की आधिकारिक जीवनी में स्वीकार भी किया गया है- 'संघ की स्थापना के बाद डॉक्टर साहब अपने भाषणों में हिन्दू संगठन के बारे में ही बोला करते थे। सरकार पर टीका-टिप्पणी नहीं के बराबर रहा करती थी।'

महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के सभी समुदायों की एकताबद्ध लड़ाई की कांग्रेस की अपील को ठुकराते हुए हेडगेवार ने कहा था- 'हिंदू संस्कृति हिंदुस्थान की जिंदगी की सांस है। इसलिए स्पष्ट है कि अगर हिंदुस्थान की रक्षा करनी है तो हमें सबसे पहले हिंदू संस्कृति का पोषण करना होगा।'

1940 में हेडगेवार की मृत्यु के बाद आरएसएस के प्रमुख भाष्यकार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरुजी ने भी स्वाधीनता आंदोलन के प्रति अपनी नफ़रत को नहीं छुपाया। वे अंग्रेज शासकों के विरुद्ध किसी भी आंदोलन अथवा कार्यक्रम को कितना नापसन्द करते थे, इसका अंदाज़ा उनके इन शब्दों से लगाया जा सकता है- 'नित्यकर्म में सदैव संलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का और भी एक कारण है। समय-समय पर देश में उत्पन्न परिस्थिति के कारण मन में बहुत उथल-पुथल होती ही रहती है। 1942 में ऐसी उथल-पुथल हुई थी। उसके पहले 1930-31 में भी आंदोलन हुआ था। उस समय कई लोग डॉक्टर जी (हेडगेवार) के पास गए थे। इस 'शिष्टमंडल' ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया कि इस आंदोलन से देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी और इसलिए संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी से कहा कि वह जेल जाने के लिए तैयार है, तो डॉक्टर जी ने कहा- 'ज़रूर जाओ लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा?' उस सज्जन ने बताया, 'दो साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं, आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी मैंने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है।' इस पर डॉक्टर जी ने कहा- 'आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है तो अब दो साल के लिए संघ का ही कार्य करने के लिए निकलो।' घर जाने के बाद वे सज्जन न तो जेल गए और न ही संघ का कार्य करने के लिए बाहर निकले।' (श्री गुरुजी समग्र, खंड 4 पृष्ठ 39-40)

गोलवलकर द्वारा प्रस्तुत इस ब्यौरे से साफ जाहिर होता है कि आरएसएस का मकसद स्वाधीनता संग्राम के प्रति आम लोगों को निराश और उदासीन करना था। ख़ास तौर से उन देशभक्तों को, जो अंग्रेजी शासन के ख़िलाफ़ कुछ करने की इच्छा लेकर घर से आते थे। वैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति आरएसएस का हिकारत भरा रवैया गोलवलकर के इस शर्मनाक कथन से भी जाना जा सकता है- 'सन्1942 में भी अनेक लोगों के मन में तीव्र आंदोलन था। उस समय भी संघ का नित्य कार्य चलता रहा। प्रत्यक्ष रूप से संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया। परन्तु संघ के स्वयंसेवकों के मन में उथल-पुथल चल ही रही थी। संघ के बारे में कहा गया कि यह अकर्मण्य लोगों का संगठन है, इनकी बातों का कुछ अर्थ नहीं। ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं, संघ के कई स्वयंसेवकों ने भी कहा। वे बड़े रुष्ट भी हुए।' (श्री गुरुजी समग्र, खंड 4 पृष्ठ 40)

गोलवलकर का यह कहना कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आरएसएस का 'रोज़मर्रा का काम' ज्यों का त्यों चलता रहा, बहुत अर्थपूर्ण है। यह रोज़मर्रा का काम क्या था? इसे समझना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। यह काम था मुस्लिम लीग के समानांतर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को अधिक चौड़ा व गहरा करना। उनकी इस 'महान' सेवा से खुश होकर अंग्रेज़ शासकों ने उन्हें अपनी कृपा से नवाज़ा भी। गौरतलब है कि ब्रिटिश शासन में आरएसएस और मुस्लिम लीग पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगा। दोनों संगठनों को खुल कर खेलने की छूट मिली हुई थी।

**(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)**

**(शेष कल के अंक में)**

बिहार चुनाव

# भाजपा-राजद का कृष्णपक्ष, जदयू-कांग्रेस का शुक्लपक्ष

बीस साल से बिहार में राज्य कर रहे नीतीश कुमार जब हड़बड़ी में पटना मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे उसके कुछ घंटे बाद ही आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के चलते पटना और प्रदेश के अन्य शहरों में लगे उन होर्डिंगों और प्रचार सामग्री को उतारने में मजदूर जुट गए जिनसे राज्य सरकार आगामी चुनाव में कुछ लाभ पाने की उम्मीद कर रही है। मात्र तीन स्टेशनों के बीच मेट्रो चलाने की परियोजना भी इसी के चलते हड़बड़ी में शुरू हुई। लेकिन नीतीश कुमार और उनके साथ सत्ता में भागीदारी कर रही भाजपा को भरोसा है कि पचहत्तर लाख महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रुपए ट्रांसफर करने से लेकर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर वाली जिन लगभग एक दर्जन योजनाओं की घोषणा पिछले कुछ महीनों के अंदर हुई है वह बीस साल के एंटी-इंकम्बेन्सी को काटकर एनडीए को जीत दिला देगी। विपक्ष भी इस बारे में मुंह खोलने और आलोचना करने से बच रहा है क्योंकि इससे उसकी छवि खराब होगी। सो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर उनकी योजनाएं चुराने का आरोप लगा रहे हैं।

अरविन्द मोहन

**जिस भाजपा के लिए इस बार बिहार जीतने का मौका था वह सचमुच मुंह छुपा रही है या नीतीश को आगे करके लोक-लुभावन कार्यक्रमों और पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। पैंतीस साल से एक ही तरह की राजनीति और शासन झेल रहे बिहार को नई राजनीति चाहिए लेकिन न तो भाजपा उसके लिए तैयार है न प्रशांत किशोर खुद को विकल्प के रूप में पेश कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, होशियार है**

कहना न होगा कि अब वे वोट चोरी के सवाल को उस तरह उठाने का उत्साह नहीं दिखा रहे हैं जैसा डेढ़-दो महीने पहले कर रहे थे। इस मुद्दे को बहुत जोर-शोर से उठाने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी तो अचानक बिहार के राजनैतिक परिदृश्य से कुछ समय गायब हो गए लेकिन वोट चोरी का मसला सुप्रीम कोर्ट के कई बार दिए गए दखल से काफी कुछ लाइन पर आया और चुनाव आयोग तथा शासक गठबंधन ने भी मतदाता सूची पुनरीक्षण पर पहले जैसी गलतियां न करके मामले को कुछ ठंडा पड़ने दिया है। इस बीच प्रशांत किशोर ने प्रदेश भाजपा के चार प्रमुख नेताओं और नीतीश कुमार के एक दुलारे मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाकर बिहार में काफी खलबली मचाई है और वोट चोरी के सवाल को भी पीछे किया है। तेजस्वी की मुश्किल यह है कि वे भ्रष्टाचार के सवाल को भी ज्यादा जोर से नहीं उठा सकते क्योंकि लालू यादव का सजायाफ़्ता होना और खुद तेजस्वी समेत सारे परिवार के अभी भी आरोपों में घिरे होने से यह सवाल उनके चुनावी भविष्य के लिए मुश्किल बन सकता है। भाजपा ने जिस सम्राट चौधरी पर दांव लगाया था वे तो प्रशांत के आरोपों से लहूलुहान हुए ही हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दो पूर्व अध्यक्ष-संजय जायसवाल तथा मंगल पांडेय भी बुरी तरह घिर गए हैं। प्रशांत का जवाब देने के लिए भाजपा का एक भी बड़ा नेता सामने नहीं आया तो नीतीश कुमार तो मौनी बाबा बन ही गए हैं।

लेकिन जिस भाजपा के लिए इस बार बिहार जीतने का मौका था वह सचमुच मुंह छुपा रही है या नीतीश को आगे करके लोक-लुभावन कार्यक्रमों और पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। पैंतीस साल से एक ही तरह की राजनीति और शासन झेल रहे बिहार को नई राजनीति चाहिए लेकिन न तो भाजपा उसके लिए तैयार है न प्रशांत किशोर खुद को विकल्प के रूप में पेश कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, होशियार हैं लेकिन उनका अगड़ा होना और पैसों के संदिग्ध स्रोत उनकी राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पर भाजपा तो जैसे-जैसे अपने पैरों पर खड़ा होने की जगह नीतीश कुमार के चेहरे के पीछे छुप रही है वैसे-वैसे उसका स्वतंत्र ढंग से बिहार की राजनीति में बढ़ना थम गया है। खुद थक-हार गए नीतीश कुमार अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं तो भाजपा को क्या सहारा देंगे। एक उनकी ईमानदारी वाली छवि है और उसने बीस साल का राज दिलवा दिया है। जैसे-जैसे भाजपा के नेताओं का ग्राफ गिरा है नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति बढ़ती गई है। वह चुनाव जितवा देगी यह कहना जल्दबाजी होगी। खुद को असहाय पाती भाजपा इस बार चिराग पासवान, पप्पू यादव और ओवैसी जैसों के सहारे नीतीश और विपक्ष को पंचर करने का दोहरा खेल इस बार नहीं खेल पा रही है।

भाजपा के बाद सबसे मजबूत दल राजद का किस्सा हल्का बयान हुआ है पर यह भी कहना जरूरी है कि इस बार वह मुसलमान वोट के पूरी तरह इंडिया गठबंधन की तरफ आने से बम बम है। वक्फ कानून पर भाजपा का साथ देने से नीतीश कुमार पर मुसलमानों का भरोसा पूरी तरह टूट गया है। लेकिन उसी अनुपात में कांग्रेस का ग्राफ चढ़ा भी है इसलिए तेजस्वी या राजद को इस सच्चाई को ध्यान में रखना होगा। और कांग्रेस ने रविदासियों, मुसहरों और अति पिछड़ा समाज में घुसपैठ करने की गंभीर कोशिशें की हैं जैसा यादव दबदबे वाली राजद नहीं कर पाई है। लगभग 36 फीसदी आबादी वाला अति पिछड़ा समाज भी हाल के वर्षों में अपने विरोधाभासों से जूझता रहा है और वह एक साथ वोट देगा यह मानना जल्दबाजी होगी। उसे नीतीश कुमार का भरोसा है पर वह यह भी देख रहा है कि वे अब राजनीति में ज्यादा समय चलने वाले नहीं हैं और अगर यह वोट बैंक बिखरा तो कहां जाएगा? यह कहना अभी भी मुश्किल है। इतना कहा जा सकता है अगर भाजपा अपने दम पर होती तो इस समाज के उसके पास जाने का सबसे ज्यादा अवसर था।

भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे, अमित शाह की चौकस व्यवस्था, केंद्र के धन के साथ अपने अपार संसाधनों के बल पर है लेकिन स्थानीय नेतृत्व के मामले में कमजोर पड़ने से उसकी तकलीफ बढ़ रही है। और सिर्फ पिछड़ा नेता सामने करने के चलते उसे अगड़ों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है जो इस बार प्रशांत किशोर का नाम लेने लगा है। यह सिर्फ भाजपा को डराने और ज्यादा टिकट के लिए दबाव बनाने के लिए है यह जल्दी ही साफ हो जाएगा। ज्यादा नए वोटर कांग्रेस से जुड़ें तो भी हैरानी नहीं होगी क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के सवाल को जिस तरह उठाया है वैसा कोई और नहीं कर पाया है। यह जरूर है कि मजबूत संगठन और सामाजिक आधार न होने से कांग्रेस बूथ स्तर पर भाजपा या एनडीए का मुकाबला करती नहीं लगती लेकिन चुनाव में लोगों का मन ही सर्वोपरि महत्व की चीज है। इसलिए कांग्रेस और जदयू बढ़े तथा राजद और भाजपा की सीटें घटे तो हैरान न होइएगा। कम से कम इस लेखक को प्रशांत किशोर से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है।

## आपके पत्र

### बढ़ती छात्र आत्महत्याएं: कानून है, लेकिन संवेदना कहां है?

भारत में बढ़ती छात्र आत्महत्याएं एक गहरी सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकट का संकेत हैं। मानसिक स्वास्थ्य कानून (2017) और आत्महत्या रोकथाम नीति (2021) ने क़ानूनी ढांचा तो दिया, पर उसका असर सीमित रहा। जागरूकता की कमी, काउंसलिंग ढांचे का अभाव और अभिभावकों की अपेक्षाएं छात्रों को अवसाद की ओर धकेल रही हैं। अब ज़रूरत है भावनात्मक शिक्षा, प्रशिक्षित काउंसलर, डिजिटल सहायता और पारिवारिक संवेदना की। जब तक समाज यह नहीं समझेगा कि हर बच्चे की सफलता अलग है, तब तक कानून भी किसी की जान नहीं बचा पाएंगे।

यह एक सच्चाई है कि यहां हर साल हज़ारों विद्यार्थी पढ़ाई, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव के बोझ तले अपनी जान दे देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2023 में 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्याएं दर्ज की गईं — यानी हर 40 मिनट में एक विद्यार्थी अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहा है। यह सिर्फ़ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की नाकामी का सबूत है जो बच्चों को बचाने के बजाय उन्हें अंधे मोड़ पर छोड़ देती है।

सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कानून और नीतियां बनाई हैं — जैसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति 2021। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कागज़ों पर लिखे कानून ज़मीन पर किसी बच्चे को सच में बचा पा रहे हैं?

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 का मकसद था कि आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे मानसिक संकट के रूप में देखा जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा आत्महत्या की कोशिश करता है, तो उसे सज़ा नहीं, बल्कि सहारा दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी पहल थी, कानून ने यह भी कहा कि हर नागरिक को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार होगा। यानी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर काउंसलिंग और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कानूनों और नीतियों से आगे बढ़कर अब हमें कुछ व्यावहारिक, संवेदनशील और स्थायी उपाय अपनाने की ज़रूरत है। हर स्कूल और कॉलेज में प्रशिक्षित काउंसलर अनिवार्य होने चाहिए। सरकार चाहे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति कर सकती है। टेली-काउंसलिंग की सुविधा भी दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि असफलता अंत नहीं है।कोटा, दिल्ली, पटना या हैदराबाद— हर शहर से आती आत्महत्याओं की खबरें हमें झकझोरती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। जबकि हर बच्चा जो चला गया, वह हमारे समाज का आईना था— वह यह कह गया कि तुमने मुझे सुना नहीं।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति 2021 जैसी पहलें सही दिशा में कदम हैं, लेकिन ये तब तक अधूरी रहेंगी जब तक समाज, परिवार और शिक्षा संस्थान मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देंगे। हर आत्महत्या एक असफल नीति नहीं, बल्कि असफल संवेदना की कहानी है। समाधान किसी नए कानून में नहीं, बल्कि इस सोच में है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

## ललित सुरजन की कलम से

### संसद की सर्वोच्चता कायम रखने की जरूरत

*'मेरा सदैव से मानना रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कानून से नहीं चलती, जबकि हमारी विडंबना यह है कि कुछ भी गड़बड़ होने पर हम तुरंत एक नया कानून बनाने की मांग करने लगते हैं। जब कानून बन जाता है तो उस पर अमल हो भी रहा है या नहीं, यह देखने की सुध किसी को नहीं रहती। जहां अधिनायकवाद, राजतंत्र या सैन्यतंत्र है वहां शासन चलाने में न तो इतिहास की परवाह की जाती और न भविष्य की। सत्ताधीश की जुबान से निकली बात ही प्रथम और अंतिम होती है। इसके विपरीत जनतंत्र आम सहमति के आधार पर एक दीर्घकालीन दृष्टि को लेकर चलता है, जिसमें इतिहास से सबक लेकर वर्तमान की जमीन पर भविष्य के सपने बुने जाते हैं।'*

**(देशबन्धु में 3 अक्टूबर 2013 को प्रकाशित)**

https://lalitsurjan.blogspot.com/2013/10/blog-post_2.html

## गुरवाणी विचार

### चौथे नानक गुरु रामदास जी

शांति के पुंज अमृतसर बसाने वाले, रामदास सरोवर के निर्माता सिखों के पिता का नाम हरदास एवं माता का नाम दयाकौर था। आपका जन्म लाहौर में 24 सितंबर 2534 को हुआ था। आपके छोटे भाई और एक बहन भी थी। बचपन में मां-बाप का साया सिर से उठ जाने के कारण नानी अपने गांव बासर ले आई थी। जहां पर आप उबले चने बेचकर अपने छोटे भाई बहनों का पालन-पोषण करते थे। वहीं पर आप तीसरे नानक अमरदास के दरबार में भी जाते रहते थे। वहीं पर तीसरे नानक गोइंदवाल साहिब में बावली का निर्माण कराना प्रारंभ किए तब आप भी वहीं पर कार सेवा करने लगे। गुरु घर की हाजिरी भी भरते थे। एक दिन उन पर तीसरे नानक की कृपा दृष्टि पड़ गई और आप गुरु घर के दामाद बन गए। गुरु अमरदास की छोटी बेटी बीबी भाणी के साथ उनका विवाह दिसंबर 1552 में हो गया। आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा लगने लगा।

सेवाकार्य के दौरान गुरुदेव ने आपकी कई तरह की परीक्षाएं भी लीं और हर परीक्षा में वे खरे उतरते गए। तीसरी परीक्षा मिट्टी गारे से चबूतरा का निर्माण करने की भी परीक्षा ली गई जिसमें गुरुदेव के दोनों बेटों और दामाद भी थे जो परीक्षा में पीछे हट गए। बार-बार चबूतरा गिराने का इनको आदेश होता फिर वे उसका निर्माण करने को कहा जाता। आप पुराना चबूतरा गिराकर उसी स्थान पर फिर चबूतरा बनाने लग जाते। यह परीक्षा भी आपने पास की और गुरुदेव ने आपको चौथा गुरु नानक बना दिया नाम रखा गया भाई रामदास- गुरु अमरहु गुरु रामदास गुरु सेवा गुरु होय समाया।

ज्यों ही आप में निरंकारी ज्योति का प्रकाश हुआ आप गुरुवाणी की रचना करने में लग गए। आपने तीस रागों में कुल 679, शब्दों की रचना की जिसमें 245 पद, 31 अष्टपदी 183 पौड़ियां, 32 छंद 138 श्लोक, 8 वारें शामिल हैं। उपरोक्त सब बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। आपने ही अमृतसर नगर बसाया। गुरु रामदास सरोवर और संतोख सर सरोवर का अमृतसर में निर्माण कराया। गुरु रामदास सरोवर में दुख भंजनी बेरी के नीचे स्नान करने वालों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पार कमाते। 2 सितंबर सन् 1551 ई. को गोइंदवाल साहिब में आप इस संसार से विदा हो गए और आपने अपने छोटे पुत्र को सब तरफ से लायक समझकर पांचवा नानक अर्जुनदेव को बना गए। गुरु रामदास कितने गहन गंभीर थे आपके द्वारा रचित वाणी से स्पष्ट हो जाता है-

जो हमारी विधि होती मेरे सतगुरु, सा विधि तुम हरि जानौ आपै।
हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापै।

राग, द्वेष से मुक्त आप पूर्णरूपेण योगी थे। आप परोपकारी और शांति के पुंज थे। आपने मानव सेवा हेतु कई दवाखाने और लंगर घर प्रारंभ किए जहां बिना किसी भेदभाव के हर किसी को छुआछूत के लंगर ग्रहण कर सकते थे। तभी तो भट्ट कीरत जी फरमा रहे हैं-

हम अवगुण भरे एक गुण नांहि। अमृत छांड़ बिखे बिख खाहीं।
माया मोह भरम भय भूले सुत दारा संग प्रीति लगाई।
इक उदम पंथल सुनियो गुरु नानक तिह मिलत जम त्रास मिटाई।
इक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो सरणई।

**इंदर सिंह आहुजा**

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in